राष्ट्रीय संस्करण

महिला मुद्दे पर चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी का अपमान >> 3

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 179

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 7 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जहां हुई थी दरिंदगी, वहीं आरोपित ढेर

हैदराबाद में डॉक्टर से हैवानियत करने वाले चार आरोपितों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

सुबूत की तलाश में घटनास्थल पर ले जाए गए थे आरोपित, तभी हुई भागने की कोशिश

मुठभेड़ करने वाले पुलिसकर्मियों पर लोगों ने बरसाए फूल, मानवाधिकार आयोग ने दिया जांच का आदेश

हैदराबाद, एजेंसियां : महिला पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने और शव को जलाने वाले चारों आरोपितों को पुलिस ने शुक्रवार तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। यह संयोग ही है कि हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिस पुलिया के नीचे महिला चिकित्सक के शव को जलाकर दरिंदों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी, उसी जगह सुबूत की तलाश के दौरान चारों मारे गए। पुलिस उन्हें लेकर तड़के जब वहां पहुंची थी तो आरोपितों ने भागने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस से हथियार छीनकर फायरिंग भी की, लेकिन बहुत दूर तक भाग नहीं पाए।

एनकाउंटर स्थल पर ही प्रेस कांफ्रेंस कर साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जानार ने बताया कि पुख्ता साक्ष्य के आधार पर चारों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि महिला चिकित्सक का मोबाइल फोन, पावर बैंक व घड़ी उन्होंने पुलिया के पास झाड़ियों में छिपाया था। पुलिस सामान बरामद करने व सीन रिक्रिएट करने के लिए चारों को शादनगर के चटनपल्ली स्थित पुलिया पर ले गई थी। हैदराबाद-बेंगलुरु नेशनल हाईवे संख्या 44 पर स्थित इस पुलिया के नीचे ही महिला चिकित्सक के शव को जलाया गया था।

आरिफ ने हथियार छीन कर पहले फायरिंग की: सज्जानार ने बताया कि 10 पुलिसकर्मियों की टीम चारों आरोपितों मुहम्मद आरिफ, शिवा, नवीन और केशवुलू को लेकर घटनास्थल पर गई थी। इसी दौरान आरिफ व केशवुलू ने पुलिस से हथियार छीने और फायरिंग करते हुए झाड़ियों की तरफ भागे। बाकी के दो बदमाश भी उनके पीछे पुलिस पर ईंट-पत्थर चलाते हुए भागे। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और चारों मारे गए। एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी सिर में चोट आई है।

खबर मिलते ही झूम उठे लोग: आरोपितों के मारे जाने की खबर मिलते ही लोग खुशी से झूम उठे और बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गए। लोगों ने पुलिस को कंधे पर उठा लिया और पुलिस टीम पर फूल बरसाए।

एनएचआरसी ने दिए जांच के आदेश: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने घटना की जांच के आदेश देते हुए कहा है कि पुलिस मुठभेड़ चिंता का विषय है। इसकी सही तरीके से जांच कराई जाएगी। उधर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चारों आरोपितों के शव नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश से एनकाउंटर की शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।

ऐसी अन्य घटनाओं में शामिल होने का संदेह: सज्जानार ने बताया कि पीड़िता और चारों आरोपितों की डीएनए प्रोफाइलिंग और वैज्ञानिक डाटा व साक्ष्य जुटाए गए हैं। हम कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से भी महिलाओं की गुमशुदगी और उनके जले शव बरामद किए जाने का डाटा जुटा रहे हैं। हमें संदेह कि आरोपित दूसरे राज्यों में भी इस तरह के अपराध में शामिल रहे होंगे।

बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी: पुलिस मुठभेड़ में चारों दरिंदों के मारे जाने की खबर महिला चिकित्सक के परिजनों को टीवी के जरिये मिली। पीड़िता के पिता ने बेटी के कातिलों को मार गिराने वाली पुलिस के साथ ही तेलंगाना सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े लोगों का भी आभार जताया। पीड़िता की बहन ने कहा कि उसकी बहन जिंदा तो नहीं हो सकती, लेकिन दरिंदों के मारे जाने से उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। इस घटना से दूसरों में भी डर पैदा होगा।

निर्भया की मां ने जताई खुशी: हैदराबाद कांड ने दिल्ली में 2012 में निर्भया के साथ हुई घटना की याद दिला दी। निर्भया की मां ने खबर पर खुशी जताते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस ने एक नजीर पेश की है। उन्होंने यह भी कहा कि दरिंदों को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शादनगर में शुक्रवार को महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपितों को ढेर किए जाने के बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पुष्पवर्षा की ● एपी

ऐसे चली कार्रवाई

3:00 तड़के
साइबराबाद पुलिस महिला पशु चिकित्सक के साथ दरिंदगी करने वाले चारों आरोपितों को सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल शादनगर के चटनपल्ली स्थित पुलिया पर ले गई

5:45
पुलिस के मुताबिक सुबह धुंध होने के चलते आरोपितों ने आपस में इशारा कर भागने की योजना बनाई। आरोपितों ने इसके बाद हथियार छीनकर भागने की कोशिश की

6:15
करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और चारों आरोपितों को ढेर कर दिया।

हैदराबाद का इंसाफ! >> पेज 5-6
मुठभेड़ का सच >> संपादकीय

पॉक्सो एक्ट के दोषियों को न मिले दया याचिका का अधिकार : राष्ट्रपति

राज्य ब्यूरो, जयपुर

- संसद को संविधान संशोधन के बारे में विचार करना चाहिए : कोविंद
- कहा, महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम हुआ, बहुत होना बाकी

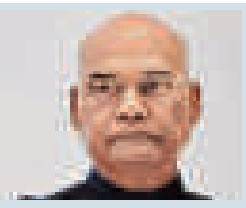

रामनाथ कोविंद फाइल

देशभर में दुष्कर्म के मामलों को लेकर सामने आ रही कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को दया याचिकाओं के इस विषय पर संविधान संशोधन के बारे में विचार करना चाहिए। संविधान ने दया याचिका का अधिकार दिया है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के दोषियों को ऐसे किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि निर्भया मामले में दया याचिका हाल ही में राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजी गई है। ऐसे में उनका यह बयान काफी अहम हो जाता है।

राष्ट्रपति शुक्रवार को राजस्थान के माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से महिला सशक्तीकरण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देशभर में दुष्कर्म और यौन हिंसा की वारदात पर चिंता जताते हुए कहा, महिला सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदात देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती हैं। उन्होंने कहा, लड़कों में 'महिलाओं के प्रति सम्मान' की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता-पिता, हर नागरिक की है। राष्ट्रपति ने कहा, बांसवाड़ा जैसे आदिवासी जिले में एक हजार बेटों पर 1003 बेटियां पैदा होने की बात से गर्व होता है। संसद में 78 महिला सांसदों का होना भी गर्व की बात है।

...तो दो परिवारों को होता है लाभ : राष्ट्रपति ने कहा, यह एक सामाजिक सत्य है कि जब आप एक बालक को शिक्षित बनाते हैं तो उसका लाभ एक परिवार को मिलता है, लेकिन जब आप बालिका को शिक्षित बनाते हैं तो उसका लाभ दो परिवारों को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य यह है कि शिक्षित महिलाओं के बच्चे अशिक्षित नहीं रहते।

निर्भया कांड के दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के निर्भया कांड के दोषी की दया याचिका अंतिम फैसले के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने याचिका खारिज करने की सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। मंत्रालय ने उपराज्यपाल की सिफारिश का समर्थन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने की निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन विनय की दया याचिका लंबित रहने के कारण दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकी है।

निर्भया की मां ने दया याचिका ठुकराने की मांग की

नई दिल्ली, प्रेट्र : निर्भया की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दया याचिका ठुकराने की मांग की है। मां ने कहा है कि एक दोषी फांसी की सजा लागू होने में अड़चन पैदा करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है। 'करीब सात साल बीत गए। आवेदिका ने इस दौरान आघात, पीड़ा और दुख का सामना किया है। न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार असहनीय है।'

जागरण पड़ताल

आचमन के लायक भी नहीं गंगा, क्या करेंगे पीएम!

कानपुर : चर्चा है कि 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन नमामि गंगे की समीक्षा करने के लिए कानपुर पहुंचेंगे तो गंगाजल से आचमन भी करेंगे...। कानपुर के लोगों और संतों की मानें तो यहां आचमन प्रधानमंत्री के लिए किसी चैलेंज से कम न होगा, क्योंकि जल बुरी तरह से प्रदूषित है। (पेज-10)

जागरण विशेष

नो ब्रोकर! अदद कमरे की तलाश में शुरू किया स्टार्टअप

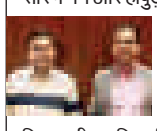

नई दिल्ली : दो आइआइटीयंस मेरठ के सौरभ गर्ग और हापुड़ के अमित अग्रवाल की सफलता की कहानी, जिनका स्टार्टअप 'नो ब्रोकर' रेंट-सेल-परचेस के बिजनेस में बिना कमीशन लिए भी बड़ा मुनाफा कमा रहा है। (पेज-10)

विश्वास. News

गोडसे पर अक्षय की वायरल हो रही पोस्ट फर्जी

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 10

'पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को मिलेगी राहत'

- प्रधानमंत्री मोदी ने एक निजी कार्यक्रम में कही यह बात
- सोमवार को संसद में पेश होगा नागरिकता संशोधन विधेयक

नई दिल्ली में शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किए जाने के पहले ही जहां राजनीतिक घमासान मचा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि यह ऐसे लाखों लोगों के लिए सुनहरा कल लेकर आएगा जो धार्मिक आधार पर दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। कैबिनेट से विधेयक मंजूर होने के बाद उन्होंने पहली बार इस संबंध में बयान दिया है। यह विधेयक सोमवार को संसद में पेश होगा।

शुक्रवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विधेयक का नाम लिए बगैर जहां सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया, वहीं राम मंदिर और इस विधेयक के प्रभाव पर भी बोले। उन्होंने कहा, 'हम हमेशा भूतकाल की बेड़ियों में बंधे नहीं रह सकते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कई लोग आशंका जता रहे थे कि इसके बाद देश में अशांति आएगी, लेकिन जनता ने ऐसे लोगों को गलत साबित कर दिया।'

इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में कई लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जिन्हें भारत में विश्वास है हम उनके भविष्य के लिए संकल्पित हैं। ध्यान रहे कि नागरिकता संशोधन विधेयक में बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस, तृणमूल, वाम जैसे दलों की ओर से इसका खुला विरोध किया जा रहा है जबकि कई दल अभी चुप हैं। वहीं भाजपा को विश्वास है कि सहयोगी दलों के साथ साथ कई गैर राजग- गैर संप्रग दलों की ओर से भी इसे समर्थन मिलेगा।

जिंदगी की जंग हार गई उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाई गई उन्नाव निवासी सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता शुक्रवार देर रात आखिरी जिंदगी की जंग हार गई। यहां सफदरजंग अस्पताल में रात 11.40 बजे पीड़िता ने अंतिम सांस ली। सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

गुरुवार देर शाम 95 फीसद जली अवस्था में पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता ने दिन में बताया था कि ऐसे गंभीर मामलों में इलाज बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात आठ से साढ़े आठ बजे के दौरान पीड़िता बात कर पा रही थी। वह अस्पताल में मौजूद अपने बड़े भाई से पूछ रही थी कि भइया क्या में बच जाऊंगी, मैं जीना चाहती हूं। आरोपितों को छोड़ना नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि इस दौरान उन्हें सांस लेने और बोलने में काफी तकलीफ भी हो रही थी।

भाई ने कहा, दरिंदों को मिले मौत की सजा : दिन में मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के भाई ने कहा था कि हैदराबाद में गुनाहगारों को सजा मिल चुकी है। उनकी बहन से दरिंदगी करने वालों को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार व पुलिस उनकी मदद कर रही है। बस बहन जल्दी से ठीक हो जाए। पीड़िता की मां भी दिल्ली आई थीं, लेकिन वह काफी परेशान हो रही थीं इसलिए घर भेज दिया गया।

भ्रष्टाचार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के घर समेत पांच जगह सीबीआइ छापे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- जस्टिस शुक्ला व उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व जज कुद्दूसी समेत छह के खिलाफ दर्ज है केस
- लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का आरोप

सीबीआइ मुख्यालय (फाइल फोटो)

सीबीआइ की दिल्ली स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एंटी करप्शन ब्रांच) ने उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन शुक्ला,छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आइएम कुद्दूसी समेत छह नामजद आरोपितों, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ केस दज किया। इसके बाद लखनऊ और मेरठ में पांच स्थानों पर छापे मारे। एजेंसी की टीम ने दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर छापा मारा। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश एसएन शुक्ला पर लखनऊ स्थित प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पक्ष में निर्णय देने के लिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। चार माह पहले देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई ने सीबीआइ को शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दी थी।

भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र : सीबीआइ ने न्यायाधीश एसएन शुक्ला, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आइएम कुद्दूसी, दिल्ली निवासी भावना पांडेय, लखनऊ निवासी भगवान प्रसाद यादव, पलाश यादव, मेरठ में सुधीर गिरि के घर पर छापा मारा। सुधीर का मेरठ मेडिकल कॉलेज है। प्रसाद एजूकेशन ट्रस्ट व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व आपराधिक षड्यंत्र की धारा के तहत केस दर्ज किया है।

सीबीआइ ने एसएन शुक्ला के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक फ्लैट पर भी छानबीन की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपितों के घरों पर छापों के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस मामले में आरोप है कि शुक्ला ने आरोपितों को राहत पहुंचाने और उनके पक्ष में फैसला देने के एवज में घूस ली। शुक्ला ने आरोपितों से अपने घर पर फैसले देने से पहले रकम हासिल की।

यह है मामला

केंद्र सरकार ने मई 2017 में लखनऊ के प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मानक स्तर की सुविधाएं न होने तथा जरूरी मापदंड पूरे न करने के चलते छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगा दी थी। 46 अन्य मेडिकल कॉलेजों पर भी इसी आधार पर दाखिला देने पर पाबंदी लगायी गयी थी। ट्रस्ट ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरोप है कि सीबीआइ के केस में नामजद आरोपितों ने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले लिया था। इसके बाद 24 अगस्त 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक अन्य याचिका दायर की गई। सीबीआइ की एफआइआर में आरोप है कि न्यायमूर्ति शुक्ला की भागीदारी वाली खंडपीठ ने 25 अगस्त 2017 को याचिका पर सुनवाई की और उसी दिन ट्रस्ट के पक्ष में आदेश दे दिया था। पक्ष में फैसला देने के लिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पक्ष में फैसला आने के बाद मेडिकल कॉलेज में छात्रों का दाखिला कर लिया गया था। इस मामले में सीबीआइ ने कोर्ट के आदेश पर प्रारंभिक जांच की थी।

घरेलू हिंसा कानून

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए पुरुषों को ही अपराधी मानने की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की

पुरुषों संग भेदभाव पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

- कहा, महिला की शिकायत पर पुरुष को तुरंत क्यों मान लिया जाता दोषी
- हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के रवैये पर भी उठाए सवाल

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट फाइल फोटो

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून में पुरुषों के साथ भेदभाव पर चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि किसी महिला द्वारा शिकायत करने पर पुरुष को तुरंत ही क्यों दोषी मान लिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायत मिलते ही ट्रायल कोर्ट भी आरोपित को अपराधी समझने लगता है। अक्सर शुरुआती दौर में ही गिरफ्तारी के लिए वारंट तक जारी कर दिया जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

जस्टिस फतेहदीप सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जज को ऐसे मामलों में यह प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रकार विवाद का निपटारा हो जाए और प्रतिवादी को भी न्याय मिल सके। पीठ ने आदेश की प्रति हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी न्यायिक अधिकारियों को भी सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिससे विचारण न्यायालय फैसले के दौरान इस बिंदु को ध्यान में रखें। घरेलू हिंसा कानून को पुरुषों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए पीठ ने समानता के अधिकार के प्रावधानों को लागू करने की प्रदेश सरकार को सलाह दी है। इस फैसले के साथ ही पीठ ने घरेलू हिंसा के हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कई याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि एक ही समस्या के लिए कई विकल्प देना कहां तक जायज है? महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने का संकल्प 1981 में इस आशय के साथ लिया गया था कि सभी प्रदेश इस दिशा में काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

पीठ ने पूछा, 21 प्रोटेक्शन ऑफिसर में एक भी पुरुष नहीं, क्यों?

जस्टिस फतेहदीप सिंह की पीठ ने कहा कि हरियाणा में 21 प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, लेकिन उनमें एक भी पुरुष नहीं है। इसी प्रकार पंजाब में 154 प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जिनमें 30 पुरुष और बाकी 124 महिलाएं हैं। चंडीगढ़ में केवल पांच प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत मदद के लिए एक तो कम अधिकारी हैं और जो हैं भी, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस स्थिति में घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकेगा।

अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए छह नई याचिकाएं दाखिल

नई दिल्ली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को छह नई याचिकाएं दाखिल की गईं। वकील एमआर शमशाद के माध्यम से दाखिल की गई याचिकाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और जफरयाब जिलानी ने अंतिम रूप दिया है। धवन ने इससे पहले कहा था कि मुस्लिम पक्ष ने उन्हें पुनर्विचार मामलों से अलग कर दिया है। (पेज-6)

सरकारी राहत के बिना बंद हो जाएगी वोडा-आइडिया : बिड़ला

नई दिल्ली : भारी घाटे और वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा है कि यदि सरकार एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मसले पर कंपनी को अपनी ओर से राहत नहीं देती है तो यह बंद हो जाएगी। बिड़ला ने कहा, 'यदि हमें कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि यह वोडाफोन आइडिया की कहानी का अंत है।' उन्होंने यह भी कह दिया कि राहत नहीं मिलने पर वह कंपनी को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में ले जाएंगे। (पेज-12)

जेपी के घर खरीदारों को नहीं मिलेगा विलंब मुआवजा

- बोली लगाने वाली कंपनियों ने खरीदारों के लिए विलंब मुआवजे का नहीं रखा प्रावधान
- फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी करीब 37 प्रतिशत रकम से हाथ धोना पड़ सकता है

नई दिल्ली, प्रेट्र : जेपी इन्फ्राटेक के 20,000 से ज्यादा घर खरीदारों को उनके फ्लैट के निर्माण में हुई देरी के एवज में कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत जेपी इन्फ्रा के लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी ने बोली लगाई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों की अंतिम बोली में घर खरीदारों के विलंब मुआवजा के लिए कोई रकम नहीं रखी गई है। इसका मतलब यह है कि बोली चाहे कोई भी कंपनी जीते, घर खरीदारों को विलंब मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जेपी इन्फ्रा के कर्जदाताओं को भी 3,700 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ेगा।

जेपी इन्फ्रा के सेक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के 9,763 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत किए गए थे। लेकिन घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू करीब 13,000 करोड़ रुपये होने के बावजूद दोनों बोलीकर्ताओं ने बकाया रकम के केवल 62 प्रतिशत भुगतान की पेशकश की है। कंपनी के घर खरीदारों को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान 325 करोड़ रुपये का विलंब मुआवजा मिला है। लेकिन अब दोनों बोलीकर्ता कंपनियों ने उनके लिए किसी भी रकम का प्रावधान नहीं किया है।

असल में दोनों बोलीकर्ताओं ने जेपी इन्फ्रा के लिए नकद भुगतान की मात्रा बेहद कम रखी है। इसकी जगह उन्होंने कंपनी की भू-संपत्तियों को कर्जदाताओं में बांटने पर जोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमा ही में जेपी इन्फ्राटेक का राजस्व 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है और कंपनी का कर-पूर्व लाभ भी 43 करोड़ रुपये रहा। जेपी इन्फ्रा का मूल्य करीब 3,500 करोड़ रुपये है।

1460 करोड़ रुपये केंद्र से मांगेगी दिल्ली सरकार बसों की खरीद के लिए। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने हाल ही में 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 7 दिसंबर 2019

दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर दमघोंटू

सांसों पर संकट ▶ राजधानी का एयर इंडेक्स 400 का आंकड़ा पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंचा

11 दिसंबर को बारिश के बाद ही बड़ी राहत मिलने के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर दमघोंटू हो गई है। हवा की रफ्तार मंद पड़ने और कोहरे के प्रभाव से शुक्रवार को एयर इंडेक्स 400 का आंकड़ा पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। हैरानी की बात यह कि आसमान पर स्मॉग की चादर तो नजर आने ही लगी है, साथ ही पहली बार पराली के धुएं का कोई खास असर न होने के बावजूद एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। मालूम हो कि शुक्रवार को पराली का प्रदूषण महज तीन फीसद रहा। फिलहाल इस स्थिति में राहत की संभावना भी नहीं है। अगर रविवार शाम तक हवा की गति में कुछ वृद्धि हुई तो प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हो सकता है। हालांकि बड़ी राहत 11 दिसंबर को बारिश के बाद ही मिलने के आसार हैं।

इससे पहले 15 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 458 दर्ज हुआ था। दिसंबर में यह पहला मौका है जब प्रदूषण का स्तर गंभीर हुआ है। सुबह लगभग सात बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 411 पहुंच गया था। दोपहर 12 बजे के बाद इसमें मामूली गिरावट आई। सफर के अनुसार सप्ताह भर में पराली जलाने का सिलसिला थम जाएगा। पराली के मामलों में भी काफी कमी आ गई है। गुरुवार को पराली जलाने के महज 145 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगले दो दिन पराली का धुआं दिल्ली को प्रभावित नहीं करेगा। अगले तीन दिनों तक दिल्ली में सुबह के समय हवा की रफ्तार मंद रहेगी। दोपहर के समय चार से छह किमी प्रति घंटे होगी इसकी वजह से प्रदूषण स्तर में मामूली कमी होगी। उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर 11 दिसंबर से दिख सकता है। इसके बाद ही हवा में तेजी आएगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को एनसीआर के शहरों का एयर इंडेक्स

शहर	एयर इंडेक्स क्वालिटी
दिल्ली	404
गाजियाबाद	419
ग्रेटर नोएडा	406
गुरुग्राम	386
नोएडा	413

राजपथ पर प्रदूषण से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर घूमते विदेशी पर्यटक। ध्रुव कुमार

कैग के शिकंजे में अब स्पोर्ट्स सिटी और फार्म हाउस घोटाला

जागरण संवाददाता, नोएडा

केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की टीम भौतिक निरीक्षण करने के लिए नोएडा पहुंच गई। टीम ने शुक्रवार को स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर-78, सेक्टर-150 में बन रही परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। यही नहीं फार्म हाउसों पर जांच करने पहुंची टीम ने यहां पर डाटा एकत्रित किया। इस डाटा के जरिये वह अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इससे कई अन्य मामले खुल सकते हैं।

स्पोर्ट्स सिटी और इस जैसी कई और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की परियोजनाओं पर कैग आपत्ति लगा चुका है, जिनका जवाब प्राधिकरण की ओर से दिया जाता रहा है। कैग प्राधिकरण में 10 साल की विकास योजनाओं की जांच कर रहा है।

उन्होंने जांच के आधार पर मुख्य बिंदुओं को शामिल किया। इसमें योजनाएं कब शुरू हुईं और कब पूरी हुईं। कहीं देरी से तो पूरी नहीं हुईं। यदि देरी से पूरी हुई हैं तो उसकी वजह क्या है। दूसरा प्रोजेक्ट का पूरा ब्योरा और उसका औचित्य खंगाला है। तीसरा विगत 10 वर्षों में प्राधिकरण ने कहां-कहां से पैसे लिए हैं और कहां-कहां भुगतान किया हैं। कैग ने बिल्डरों को दी गई सुविधाओं का भी अध्ययन किया है। ऐसे में कैग की टीम को सात स्थानों पर जाकर भौतिक निरीक्षण करना था। शुक्रवार को कैग की टीम नोएडा पहुंची। टीम ने सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स सिटी, फार्महाउस, चार औद्योगिक इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम के साथ प्राधिकरण के एजीएम स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे।

जीपीएस आधारित कैमरे से खींची गई फोटो : ऑडिट टीम के साथ जीपीएस आधारित एक कैमरा था। इससे फोटो खींची गईं ताकि लोकेशन के साथ समय व दिनांक इसमें शामिल रहे। ऑडिट टीम के लिए ये फोटो काफी अहम मानी जा रही हैं।

फाइल फोटो

बढ़ता जा रहा जांच का दायरा

उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मुख्यमंत्री ने तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के विकास कार्यों की कैग जांच कराने के निर्देश दिए थे। जनवरी 2018 में कैग की एक टीम ने नोएडा में डेरा जमा लिया। तीन माह में जांच पूरी होनी थी। अनियमितताओं और फाइलों में गड़बड़ी को देख जांच की समय सीमा बढ़ती जा रही है।

▶ फार्म हाउसों पर जांच करने पहुंची टीम ने डाटा एकत्रित किया

कैग इन ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर लगा चुका आपित्त

- यूनीटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर : 96, 98
- यूनीटेक लिमिटेड सेक्टर : 117
- यूनीटेक लिमिटेड सेक्टर : 113
- यूनीटेक लिमिटेड सेक्टर : 143 जीएच-002 (सरेंडर प्लाट)
- सुपरटेक लिमिटेड सेक्टर : 74
- यूनीटेक लिमिटेड सेक्टर : 117,113
- महागुन सेक्टर : 78 जीएच-002
- ग्रेनाइट गेट सेक्टर : 110 जीएच-05
- अंबिका सेक्टर : 115 जीए05
- यूनीटेक सेक्टर : 144 जीएच-3

न्यूज गैलरी

जारी रहेगी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की हड़ताल

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षकों की तरफ से तदर्थ शिक्षकों की बहाली व अन्य मांगों के लिए हड़ताल जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर डूटा के प्रतिनिधिय गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के उच्च शिक्षण संस्थानों के सचिव आर सुब्रमण्यम से मिले थे। इसके बाद एमएचआरडी की तरफ से तदर्थ शिक्षकों के लिए फैसला लिया गया कि जब तक स्थायी नियुक्तियां डीयू के कॉलेजों में नहीं होती हैं, तब तक अस्थायी शिक्षकों, अनुबंध शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों के साथ तदर्थ शिक्षकों की भी नियुक्यिां की जाएं। इसके साथ ही 28 अगस्त को डीयू प्रशासन द्वारा जो पत्र अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए जारी किया गया था, उसमें कुछ बदलाव का भी फैसला किया है। इसका शिक्षकों ने स्वागत किया लेकिन अभी भी कुछ शिक्षकों में असंतोष है। इसकी वजह से हड़ताल जारी करने का फैसला किया है। (जासं)

'छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित कर रहे प्रदर्शनकारी'

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र संघ के नेता और कुछ छात्रों को प्रशासन ने बताया कि वे अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। 12 दिसंबर से सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन होना है। ऐसे में प्रशासन बार-बार प्रदर्शनकारी छात्रों से निवेदन कर रहा है कि वह सेमेस्टर परीक्षा में बैठें। वही प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सेमेस्टर परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रो. प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से बड़ी संख्या में वास्तविक छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। (जासं)

'स्कूल की हर छात्रा को मुफ्त उपलब्ध कराएं सेनेटरी नैपकिन'

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार व नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे सभी स्कूलों की वर्तमान एवं पुरातन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराते रहें। इस संबंध में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान एवं उड़ान जैसी योजना भी जारी रखें। इस दौरान मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी स्कूलों में मुफ्त सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल संजय घोष ने बताया कि शिक्षा निदेशालय इस संबंध में जागरूकता अभियान चला रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के अधीन दिल्ली सरकार सब्सिडी रेट पर स्कूल के बाहर लड़कियों को छह रुपये में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करा रही है। (जासं)

भाजपा का आप सांसद के आवास पर प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के एनआरसी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में दिल्ली प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री रविंद्र गुप्ता एवं पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह ने किया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के लिए सांसद संजय सिंह की उल्टी-सीधी बयानबाजी यह स्पष्ट करती है कि पूर्वांचल के लोगों से वह कितनी नफरत करते हैं। नफरत की राजनीति करने वाली आप जानबूझ कर पूर्वांचल के लोगों के बीच डर का माहौल बना रही है। मनीष सिंह ने कहा कि आप के मुखिया, उनके नेता और मंत्री बार-बार पूर्वांचल के लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

संजय सिंह की मां ने पुलिस में दी शिकायत : भाजपा के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सांसद संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने पुलिस को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हंगामा कर उन्हें व उनकी पुत्रवधू को डराने का भी आरोप लगाया है।

नॉर्थ एवेन्यू थाने में दी गई शिकायत में राधिका सिंह ने कहा है कि शुक्रवार को वह बहू अनीता और पौत्र उत्कर्ष के साथ घर पर थीं। आरोप है कि शाम करीब चार बजे भाजपा की तख्ती लेकर बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे और नारेबाजी कर उनके परिवार को डराने की कोशिश करने लगे। उस समय संजय सिंह घर पर नहीं थे। इसलिए उन्होंने पुलिसकर्मियों से भीड़ को रोककर वहां से ले जाने के लिए भी कहा था। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह की उन्मादी भीड़ भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकती है।

प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह अपने साथियों के साथ कर रहे थे। इसलिए मनीष सिंह व अन्य लोगों के विरुद्ध शांतिभंग करने, भय का वातावरण उत्पन्न करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

पूर्वांचल विरोधी है भाजपा : संजय सिंह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आप सांसद संजय सिंह ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित आवास पर भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रदर्शन को सुनियोजित तरीके से घर पर हमला करने की साजिश बताया है। साथ ही कहा कि भाजपा ने किराये के लोगों से उनके घर पर प्रदर्शन करवाया है। बेवजह प्रदर्शन करने से साबित हो गया है कि भाजपा विधानसभा चुनावों से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है। सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को देश के कोने-कोने में पीटा गया है। अब पूर्वांचल के लोगों के प्रति झूठा दर्द दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को निकालने के लिए साजिश रची गई। भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर भाजपा के एक सांसद और उनके लोगों ने भाजपा के ही पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। छठ घाट को तोड़ा और पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा करने से रोका गया, उस समय भाजपा का पूर्वांचल प्रेम कहां चला गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी खुद को पूर्वांचल का कहते हैं, लेकिन उस समय उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला था। उल्टा इस मामले की लीपापोती कर दबाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि आप हमेशा पूर्वांचल के लोगों के साथ खड़ी रही है। उनके हक के लिए हमेशा आवाज उठाती रही है और अगर दिल्ली में पूर्वांचल के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

यूनिटेक बिल्डर को रेरा ने सुनाया रिफंड का आदेश

जासं, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में शुक्रवार को विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ सुनवाई हुई। पीठ-दो में 50, पीठ-तीन में 43 और न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 52 मामले सुने गए। पीठ-दो में हवेलिया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स इंडिया ट्रेड कंट्री प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटेक आदि बिल्डर परियोजना से जुड़े खरीदारों के मामले सुने गए।

पीठ-दो में सबसे ज्यादा यूनिटेक के 16 मामलों में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद पीठ सदस्य बलविंदर कुमार ने यूनिटेक के सभी मामलों में रिफंड का आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान खरीदारों ने बताया कि नोएडा स्थित बिल्डर की परियोजना अभी ढांचागत स्थिति में खड़ी है। निर्माण कार्य अधूरा है। बिल्डर ने बुकिंग के दौरान 2017 तक फ्लैटों पर कब्जा देने का वादा किया था। परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। खरीदारों ने बताया कि बिल्डर से कई बार परियोजना को पूरा कर फ्लैटों पर कब्जा देने की गुहार लगाई गई। लेकिन बिल्डर ने निर्माण पूरा कर कब्जा देने के बजाय परियोजना की पूर्णता की तारीख ही बदल दी। हार थककर खरीदारों ने यूपी रेरा में गुहार लगाई। रेरा ने सुनवाई पूरी कर परियोजना से जुड़े सभी मामलों में रिफंड का आदेश जारी किया है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर बढ़ सकती हैं टोल दरें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी बोर्ड बैठक, रखा जाएगा प्रस्ताव

▶ टोल से एकत्र राशि से यमुना एक्सप्रेस वे का किया जाएगा रखरखाव

यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दरें बढ़ सकती हैं। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में बोर्ड बैठक होगी। इसमें दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड ने मंजूरी दे दी तो जेपी के साथ एस्क्रो अकांउट खोला जाएगा। टोल दरों से प्राप्त धनराशि से एक्सप्रेस वे का रखरखाव करने की योजना है। हालांकि, टोल दरें अधिक नहीं बढ़ेंगी। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि मामूली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बने 165 किमी लंबे एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आइआइटी ने सुझाव दिए हैं। जेपी की लापरवाही के चलते इन सुझावों पर अभी तक मात्र पंद्रह फीसद कार्य ही हुआ है। यमुना प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा निगरानी समिति की शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में एक्सप्रेस वे पर हुए कार्यों का ब्योरा दिया। समिति ने प्राधिकरण को कड़े उपाय करने के निर्देश दिए। जेपी इंफ्राटेक ने आइआइटी के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए जून 2021 तक का समय मांगा है। हालांकि यमुना प्राधिकरण ने आइआइटी के 16 सुझावों पर जेपी इंफ्राटेक को अमल करने के निर्देश दे रखे हैं। बावजूद इसके कार्य अधूरे हैं। एक्सप्रेस वे के निकासी, प्रवेश, टोल प्लाजा, मुख्य मार्ग पर तीन लाख वर्गमीटर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग होनी बाकी है। दो टोल के बीच तय दूरी के हिसाब से वाहन की रफ्तार सीमा की जांच करने व निर्धारित रफ्तार से अधिक होने पर चालान काटने का आइआइटी ने सुझाव दिया था। इस पर भी पूरी तरह अमल नहीं हुआ है। आइआइटी ने सुझाव में मेडियन (एक्सप्रेस वे के दोनों मार्गों के बीच का स्थान) पर क्रैश बीम बैरियर लगाने का सुझाव दिया था, ताकि एक ओर के वाहन हादसे के बाद दूसरे ओर के मार्ग पर न जा सकें। जेपी इंफ्राटेक ने सिर्फ जेवर टोल प्लाजा पर एक स्थान पर इसे लगाया है। अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए प्राधिकरण टोल दरों में मामूली वृद्धि करना चाहता है। प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एस्क्रो अकाउंट खोलकर टोल दरों से जमा हुई धनराशि से एक्सप्रेस वे का रखरखाव करने की योजना है।

कांग्रेस का आरोप- महिलाओं के प्रति अपराधों में इजाफा, सरकार बेखबर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि केंद्र की मोदी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस पर जरा भी चिंतित नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि इनके शासनकाल में राजधानी में अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित बन गई है और केजरीवाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए बढ़ते अपराधों को देखते हुए कुछ भी नहीं किया है। पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ ने कहा कि केजरीवाल की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति असंवदेनशीलता इस बात से जाहिर होती है कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में निर्भया फंड की केवल पांच फीसद राशि खर्च की है। जबकि केजरीवल ने 45 फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थापित करने का वादा किया था, उसके लिए अभी तक कुछ नही हुआ है।

पूर्व विधायक अलका लांबा, पार्षद रिंकू और पूनम आजाद ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की बिगड़ती सुरक्षा के कारण ही दिल्ली दुष्कर्म की राजधानी बन गई है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 तक दिल्ली पुलिस वेबसाइट में दिल्ली में दुष्कर्म के मामलों की संख्या 1877 दर्ज है, मतलब प्रति दिन छह महिलाओं से दुष्कर्म। धारा 354 आइपीसी के तहत महिलाओं से छेड़छाड और हमले के 2520 मामले दर्ज हैं, जिनका औसत प्रतिदिन आठ महिलाओं के साथ अपराध और महिलाओं के अपहरण के लगभग 2988 मामले जो प्रति दिन 10 महिलाएं है।

उन्होंने कहा कि 2012 में जब केजरीवाल वसंत विहार कांड पर मोमबत्ती लेकर धरने-प्रदर्शन पर बैठ जाते थे, उस समय दिल्ली में दुष्कर्म के मामले केवल 706 थे। इसी वर्ष 31 तक 1877 मामले हो चुके हैं। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दुष्कर्म के मामलों में 165.86 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

भाजपा-आप के खिलाफ हल्ला बोल अभियान छेड़ेगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने व उन्हें मालिकाना अधिकार देने संबंधी अधिसूचना में शामिल जनविरोधी धाराओं व प्रावधानों के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा एवं आप के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठ दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से अभियान की शुरुआत होगी।

सरकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल होंगे आंबेडकर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर महान हस्ती थे। उन्हें सिर्फ दलितों के नेता के रूप में संकुचित कर दिया गया है। उनके जैसे महान व्यक्तित्व को सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। मुख्यमंत्री बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस कार्यक्रम में बाबा साहेब पर पाठ्यक्रम भी लांच किया। केजरीवाल ने कहा कि शुरुआत में इसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। बाद में निजी स्कूलों में भी यह पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा। उनके प्रति दिल्ली सरकार की यह सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर पर एक शॉर्ट बायोग्राफी पुस्तिका भी लांच की गई। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों समेत समाज के हर उस वर्ग की आवाज उठाई, जो समाज में दबा-कुचला था और अन्याय झेल रहा था। उन्होंने गरीब परिवार से निकलकर डबल डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने में उन्होंने काफी योगदान दिया। हमारे देश में महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार मिला है, इसमें उनका विशेष योगदान है। महान व्यक्तित्व के बारे में हम बच्चों को कहानी की तरह बताएंगे ताकि बच्चों को इससे प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बारे में लांच की गई पुस्तिका एक ड्राफ्ट की तरह है। इसे पढ़ाने के दौरान बच्चों व शिक्षकों का जैसा फीडबैक मिलेगा, उसी के अनुसार पुस्तिका को अपडेट किया जाएगा। इस बारे में दो साल में एक ऐसा कोर्स तैयार किया जाएगा, जिसे पूरे देश में पढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षक, बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन एक विचार है। उनका सपना था कि हिंदुस्तान के लोग अलग-अलग जाति व धर्म के होते हुए भी एक संविधान से बंधकर रह सकें। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों से बात करके उनकी जीवनी पढ़ी गई। इसके बाद उनकी बायोग्राफी तैयार कर पाठ्यक्रम बनाया गया है। हर बच्चा बाबा साहेब के प्रारंभिक जीवन को समझ सके और यह संकल्प ले सके कि वह समाज में भेदभाव नहीं होने देंगे। तभी हमारा मकसद पूरा होगा। स्पेशल क्लास लगाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छठीं, सातवीं व आठवीं कक्षा के बच्चों को डॉ. आंबेडकर की जीवनी, सोच व काम के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। किताब को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। वहीं, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली के बच्चों के सपनों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उड़ान दी है।

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शॉर्ट बायोग्राफी पुस्तिका का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (बीच में)। साथ में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (बाएं) और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (दाएं)। जागरण

12वीं तक मुफ्त शिक्षा पर कमेटी ने दिया प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसमें बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर गठित कमेटी ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव पर जो सुझाव मिले हैं, उसके आधार पर मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गैर सरकारी संस्था सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस काम में अभी और वक्त लग सकता है। ऐसे में थोड़ा और समय दिया जाए। सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद पूरी जानकारी अदालत को दी जाएगी। मानव संसाधन मंत्रालय ने शपथपत्र में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ निजी स्कूलों की भी है। कमेटी ने अपने प्रस्ताव में नर्सरी से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। इसका लाभ तीन से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों को मिल सकेगा। इसके लिए सभी स्कूलों में बड़े क्लासरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल के मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें काफी खर्च भी आएगा और निजी स्कूलों को बढ़ा हुआ खर्च देना होगा। इस संबंध में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविदों से परामर्श किया गया है।

पुस्तक मेला

प्रगति मैदान में चार से 12 जनवरी के बीच आयोजित होगा 28वां विश्व पुस्तक मेला, हॉल नं. 7 में बनाया जाएगा थीम मंडप

बापू के किस्सों से सजेगी किताबों की दुनिया

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

पुस्तकों के महाकुंभ में इस बार पाठकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लेखन से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। पाठक उनके किस्सों से न केवल खुद को जुड़ा महसूस करेंगे, बल्कि उन पर लिखी किताबों के रूप में उन्हें अपने साथ सहेज भी पाएंगे। यह एहसास लगातार नौ दिन तक किया जा सकेगा।

जानकारी के मुताबिक प्रगति मैदान में चार से 12 जनवरी के बीच 28वां विश्व पुस्तक मेला आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (आइटीपीओ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मेले का थीम अबकी बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के तहत 'लेखकों के लेखक महात्मा गांधी' रखा गया है। हॉल नं. 7 में थीम मंडप बनाया जाएगा जहां गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकें प्रदर्शित होंगी और उन पर लिखी पुस्तकें भी रहेंगी। एनबीटी के मुताबिक मेले में गांधी जी पर केंद्रित एक ऐसा सेल्फी कॉर्नर भी बनाया जा रहा है, जहां दर्शक उनके साथ फोटो ले सकेंगे। इस मंडप में गांधी जी के प्रिय भजन और उनके चुनिंदा भाषण भी चलते रहेंगे।

मेले का आयोजन पिछली बार की ही तरह हॉल नं. 7 से 12ए तक में होगा। इसमें देश-विदेश के 700 से अधिक प्रकाशक शामिल होंगे। प्रगति मैदान में चल रहे नवीनीकरण कार्य के चलते मेला छोटे स्तर पर ही आयोजित हो रहा है, लिहाजा बहुत कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि बाल मंडप, लेखक मंच, ऑथर्स कॉर्नर सहित अन्य आकर्षण बरकरार रहेंगे। मेले में करीब 20 देशों का साहित्य मिलेगा। इनकी सूची में शारजाह, (यूएई), पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस सहित अनेक देश शामिल हैं। पाकिस्तान के भी एक-दो प्रकाशक मेले में आना चाह रहे हैं और एनबीटी के संपर्क में हैं। विदेशी प्रकाशकों के लिए हॉल नं. 7 में अलग से मंडप बनाया जा रहा है। मेले में डिजिटल पुस्तकें ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए कुछ बोलती किताबें भी प्रदर्शित होंगी।

एनबीटी अधिकारियों के मुताबिक मेले में प्रवेश निःशुल्क रहने की संभावना कम है। हालांकि इस पर अगले सप्ताह आइटीपीओ और एनबीटी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में निर्णय होना है। मेले में प्रवेश प्रगति मैदान के गेट नं. एक और 10 से ही होगा व इसका समय सुबह 10 से शाम सात बजे तक रखा गया है।

बापू पर केंद्रित सेल्फी कॉर्नर भी होगा। (फाइल)

पुस्तक मेले के लिए बहुत अधिक जगह तो हमें इस बार भी नहीं मिल सकी, लेकिन तब भी मेले में कोई कमी नहीं खलेगी। एक लेखक के तौर पर गांधी जी के साहित्य पर विशेष फोकस रहेगा। मेले का उद्घाटन कौन करेगा और टिकट दर को लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 2021 का विश्व पुस्तक मेला अब तक का सबसे खास होगा।
-गोविंद प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर होगा आसान

कुंदन तिवारी, नोएडा

▶ एक्वा की लिंक लाइन से ग्रेटर नोएडा वासियों को होगा अधिक लाभ

एक्वा लाइन मेट्रो की सुविधा को बेहतर करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए सेक्टर-142 मेट्रो स्टेशन से बोटेनिकल गार्डन तक नई लिंक लाइन को बिछाया जाएगा। इस रूट पर लाइट मेट्रो का संचालन होगा। इसकी संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) डीएमआरसी को तैयार करने के लिए सौंपी गई है। दिसंबर 2016 में इस रूट की डीपीआर नार्मल मेट्रो के अनुसार तैयार की गई थी। विस्तार के लिए 2826 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे, लेकिन अब सरकार ने लाइट मेट्रो संचालन की मंशा जता दी है, इसलिए एनएमआरसी ने डीपीआर को संशोधित कर लाइट मेट्रो के फीचर को शामिल करने को कहा है।

सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो की लिंक लाइन बनने से ग्रेटर नोएडा के लोगों को सबसे अधिक सहूलियत मिलेगी। एक्वा लाइन पकड़कर लोग मजेंटा लाइन आ सकते हैं। यहां से वे सीधे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आइजीआइ) तक आसानी से सफर कर सकते हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड के बगल खाली पड़ी ग्रीन बेल्ट पर एक्वा लाइन मेट्रो का रूट तैयार किया जाएगा। सेक्टर-142 से लेकर बोटेनिकल गार्डन तक आठ स्टेशन तैयार होंगे। इनमें केवल छह स्टेशनों को बनाया जाएगा। सेक्टर-44 के पास आकर एक्वा लाइन मेट्रो महामाया फ्ला5ईओवर के ऊपर से गुजारी जाएगी। इस जगह पर एक्वा लाइन मजेंटा लाइन के ऊपर से गुजारी जाएगी। जो रूट की सबसे ऊंची मेट्रो भी बन सकती है। यहां पर एक नया प्लेटफार्म तैयार होगा, जिस प्रकार से मजेंटा लाइन के लिए प्लेटफार्म बनाया गया है।

सर्वे के अनुसार करीब 10 लाख मुसाफिर प्रति माह इस लाइन में सफर करेंगे। प्रतिदिन 1.5 लाख सवारी डीपीआर में इस रूट से गुजारने के लिए शामिल है। एनएमआरसी इस लिंक को लेकर काफी उत्साहित है। इससे अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।

लाइट मेट्रो की विशेषता

- लाइट मेट्रो में तीन कोच होंगे
- एक कोच में सिर्फ 300 लोग सफर कर सकेंगे।
- लाइट मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी।
- लाइट मेट्रो चलाने में तीन गुना कम लागत यानी 100 करोड़ रुपये से भी कम आएगी।
- लाइट मेट्रो में टिकट ट्रेन के गेट पर लगे सेंसर पर स्वेप किया जाएगा।
- लाइट मेट्रो के अंदर जो भी बगैर टिकट पकड़ा जाएगा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डन तक लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। डीएमआरसी इस लाइन की डीपीआर को बना चुकी है, अब रिवाइज्ड करने को दी गई है। रिवाइज्ड डीपीआर में लाइट मेट्रो का फीचर शामिल होगा। इसके बाद प्रदेश सरकार मंजूरी के लिए भेज जाएगा।
-पीडी उपाध्याय, कार्यकारी निदेशक, एनएमआरसी

7.5 करोड़ किसान देश के ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छह हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पांच करोड़ किसान ऐसे हैं, जिन्हें आधार से भी लिंक कर दिया गया है।

लोकसभा में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी का अपमान

तल्खी ▶ मंत्री के बयान से उग्र कांग्रेस के दो सांसद बाहें चढ़ाते हुए वेल की ओर आए

संसदीय मंत्री ने दोनों सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का दिया नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महिला सुरक्षा और गरिमा को लेकर पिछले तीन चार दिनों में संसद के अंदर जो गुस्सा दिखा था, शुक्रवार को वह महिला के अपमान पर ही आकर खत्म हो गया। लोकसभा में गर्मागर्म माहौल के बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से बौखलाए कांग्रेस के दो सांसदों ने ऐसा आचरण कर दिया कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यहां तक कि ईरानी को कहना पड़ा कि उनकी गलती यही है कि वह भाजपा की महिला सांसद हैं और सदन में बोल रही हैं।

दरअसल, केरल से जीतकर आए टीएन प्रतापन और डीन कुरीकोज अपनी बाहें चढ़ाते हुए उग्र अंदाज में वेल की ओर बढ़े थे। भाजपा सदस्यों ने इसे एक महिला मंत्री का अपमान करार दिया और माफी की मांग की। अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है कि

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के दौरान बोलतीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। प्रेट्र

अगर दोनों सदस्य सदन के अंदर माफी नहीं मागते हैं तो उन्हें शीतकालीन सत्र के बाकी बचे पांच दिनों के लिए निलंबित किया जाए।

दरअसल, आग तभी भड़क गई थी जब शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, 'एक तरफ मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है और दूसरी ओर सीता जलाई जा रही है।' उन्होंने उन्नाव के संदर्भ में यह बात कही थी।

जब जवाब देने के लिए ईरानी आईं तो उन्होंने चेताया कि महिला सुरक्षा और गरिमा के मामले को सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, लेकिन तृणमूल सदस्यों को यह भी बताना चाहिए कि मालदा में हो रही घटनाओं पर क्यों चुप रह जाते हैं।

इस क्रम में माहौल इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस के दोनों सदस्य तेजी से वेल की ओर बढ़े। कुछ सदस्यों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उस वक्त आसन पर बैठीं मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता से कहा कि वह दोनों सदस्यों को माफी मांगने के लिए कहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हो गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी भाजपा सदस्य माफी की मांग पर डटे थे। आखिरकार पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई।

बताया जाता है कि सोमवार को प्रह्लाद जोशी नियम 374 का हवाला देकर दोनों सदस्यों को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पढ़ेंगे। उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई का आग्रह करेंगे।

कोई भारतीय अध्ययन नहीं बताता, प्रदूषण से कम होती है जिंदगी : जावडेकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में किए गए अध्ययनों में से किसी में भी यह बात सामने नहीं आई है कि प्रदूषण और कम होते जीवनकाल में कोई संबंध है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये बातें कहीं।

प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा कम होने संबंधी एक सवाल के जवाब में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री जावडेकर ने कहा, 'हमें लोगों के बीच डर की मनोवृत्ति नहीं पैदा करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी भारतीय अध्ययन में ये बातें सामने नहीं आई हैं कि प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा कम होने में कोई संबंध है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशभर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर एनसीएपी के तहत 102 ऐसे शहरों का चयन किया गया है, जहां वायु की गुणवत्ता ठीक नहीं है। इन शहरों की जरूरत के अनुरूप अलग-अलग विशेष कार्यक्रम तैयार और अनुमोदित किए जा चुके हैं। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए 11,254 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इनमें 8,562.73 करोड़ रुपये कॉम्पेनसेंट्री अफोर्सेटेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा) के माध्यम से जारी हुए हैं।

आरओ के इस्तेमाल को लेकर सभी पक्षों से हो रहा विमर्श

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा- पानी की एक बूंद भी नहीं होने देंगे बर्बाद, मिनरल भी सुरक्षित रखेंगे

लोकसभा में शुक्रवार को बोलते केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

पानी को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले आरओ को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से जुड़े सवाल पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने साफ किया है कि इस बारे में जो भी निर्णय होगा, उसमें एनजीटी के आदेश, वास्तविकता और लोगों की सेहत, तीनों को ध्यान में रखा जाएगा।

एनजीटी ने हाल ही में एक आदेश में आरओ का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं जगहों पर करने को कहा है, जहां पानी के टीडीएस (टोटल डिजॉल्वड सॉलिड) का स्तर प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से ज्यादा है।

लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान आरओ को लेकर पर्यावरण मंत्री जावडेकर से प्रो. सौगत राय, गोपाल शेट्टी, जगदंबिका पाल सहित कई सदस्यों ने सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा कि आरओ की मूल समस्या है कि इसमें सभी नेचुरल मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और पानी भी बर्बाद होता है। एनजीटी ने अपने आदेश में भी इसका जिक्र किया है। हालांकि, मुझे एक नई तकनीक के बारे में पता चला है, जिसमें पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी और उसमें नेचुरल मिनरल्स भी बचे रहेंगे। अगर ऐसा कोई विकल्प सामने आता है तो उस पर भी विचार होगा। जावडेकर ने कहा कि फिलहाल आरओ से जुड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सरकार से आरओ बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत करने और एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस पर काम कर रहा है।

महिला कर्मचारियों से रात में ड्यूटी नहीं कराएगा रेलवे

जागरण संवाददाता, अमृतसर : महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे ने महिला कर्मचारियों की रात की ड्यूटी पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए हैं। किसी भी महिला कर्मचारी से रात 10 बजे के बाद ड्यूटी नहीं कराई जाएगी।

रेलवे द्वारा जारी इस आदेश में डीआरएम (मंडल रेल प्रबंधक) स्तर पर सभी स्टेशनों पर तुरंत लागू करवाने को कहा गया है। अगर कहीं पर लापरवाही पाई जाती हैं या महिला कर्मचारियों से जबरन रात की ड्यूटी कराई जाती है, तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इन आदेशों के मुताबिक महिला कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही ड्यूटी करेंगी। यह आदेश खास तौर पर हैदराबाद में हुए सामूहिक दुष्कर्म को मुख्य रखते हुए जारी किए गए हैं।

चुनावी कर्जमाफी किसानों के साथ छलावा : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में चुनाव के दौरान कर्ज माफी के वादे को सरकार ने संसद के सामने रखा

▶ 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के वादे को फिर दोहराया

नरेंद्र सिंह तोमर फाइल फोटो

मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में चुनावों के दौरान किसानों से किए गए कर्ज माफी के वादे को केंद्र सरकार ने छलावा बताया है। साथ ही इसके लिए राज्यों को ही जिम्मेदार ठहराया है जो वादा करने के बाद अब उसे पूरा नहीं कर रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आम तौर पर यह माना जाता है, कि कर्ज माफी से किसान खुश हो जाएंगे, लेकिन इतिहास देखें तो इससे किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय भी कर्ज माफी की गई थी। उसके बाद भी कर्ज माफी की बात की जा रही है।

केंद्रीय कृषि ने शुक्रवार को यह जवाब राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिया। भाजपा सांसद प्रभात झा ने सरकार से पूछा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में चुनाव से पहले किसानों के कर्ज को माफ करने की घोषणा की गई थी। अब तक तीनों राज्यों में कितना कर्ज माफ किया गया है।

इसका जवाब पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया जिसमें उन्होंने कर्जमाफी को छलावा बताया। बाद में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हमारी सरकार कर्ज माफी के बजाय किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल इस दिशा में पीएम-किसान योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद दी जा रही है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने इस दौरान यह भी साफ किया कि कर्ज माफी की जरूरत अमूमन तब होती है, जब कोई आपदा आती है, लेकिन आपदा आने पर राज्य सरकारें कर्ज माफी नहीं करती हैं। वे सिर्फ चुनाव के दौरान ही कर्ज माफी करती हैं। अब तक दस बार ऐसा हुआ है।

बंगाल को छोड़कर सभी राज्य ले रहे है पीएम किसान का लाभ : तोमर ने कहा, बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में पीएम-किसान योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मप्र, राजस्थान और पंजाब भी इससे जुड़ गए हैं। इसके तहत अभी साढ़े सात करोड़ किसानों को यह राशि दी जा रही है। साथ ही पांच करोड़ किसान ऐसे हैं, जिन्हें आधार से भी लिंक कर दिया गया है। इस महीने से ही उन्हें यह राशि प्रदान की जाएगी।

किस राज्य में कितना हुआ कर्जमाफ

मध्य प्रदेश : माफ की जाने वाली कुल राशि- करीब 36500 करोड़। कर्ज माफ हुआ सिर्फ 7154 करोड़। 20 लाख किसानों को मिला फायदा जबकि प्रदेश में हैं कुल 80 लाख किसान।

पंजाब : माफ की जाने वाली कुल राशि- दस हजार करोड़। माफ हुआ सिर्फ 4501 करोड़। साढ़े पांच लाख किसानों को फायदा। कुल किसान हैं 34 लाख।

राजस्थान : माफ की जाने वाली कुल राशि- 18 हजार करोड़। माफ हुआ सिर्फ साढ़े सात हजार करोड़। करीब 20 लाख किसानों को फायदा। कुल किसान हैं 79 लाख।

सेना की गोला-बारूद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे आयुध कारखाने

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश के आयुध कारखानें सेना की अहम गोला-बारूद की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे सेना की परिचालन संबंधी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। आयुध कारखाने अपने 80 फीसद उत्पाद सेना को सप्लाई करते हैं। संसद में पेश रक्षा सेवाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

कैग ने कहा है कि आयुध फैक्ट्रियां आधे से भी कम यानी 49 फीसद सामग्रियों में उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर पाती हैं। यही नहीं, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में आयुध कारखानों के निर्यात में भी 39 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि 31 मार्च, 2018 तक आयुध फैक्ट्रियां सेना की प्रमुख मांगों को पूरा नहीं कर सकी थीं। रिपोर्ट में आयुध कारखाना संगठन के वित्तीय लेन-देन के ऑडिट रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुध कारखाना बोर्ड को साल 2017-18 में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए क्रमशः 14,793 करोड़ रुपये और 804 करोड़ रुपये का बजटीय अनुदान मिला था। उपरोक्त साल में बोर्ड ने 14,251 करोड़ रुपये की सामग्रियां सप्लाई की।

कैग ने कहा कि आयुध फैक्ट्रियां गोला-बारूद को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से छोड़े जाने के लिए जरूरी अहम खाली और भरे हुए फ्यूज का उत्पादन भी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पा रही हैं। सामग्रियों की कमी और गुणवत्ता की समस्या के चलते आठ तरह के खाली फ्यूज के उत्पादन में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। फ्यूज की कमी के चलते सेना के 403 करोड़ से ज्यादा के गोला-बारूद बेकार पड़े हैं। खराब फ्यूज के चलते 18 बड़े हादसे भी हुए हैं। 2011 से लागू ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का भी सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है।

नागरिकता विधेयक पर सरकार को मिला आरएसएस का साथ

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▶ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क्रियान्वयन में मिलेगा पूरा साथ

▶ संघ ने कहा, संशोधित बिल में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी नहीं

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) 2019 को लेकर हमलावर विपक्ष का सामना कर रही केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मजबूत साथ मिला है। संघ ने कहा है कि 70 सालों की ऐतिहासिक गलती को सुधारने का वक्त आ गया है और वह इसके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार का पूरा साथ देगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि यह भारत की मानवीय और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि पड़ोसी इस्लामिक देशों से धार्मिक आधार पर हिंसा से जान बचाकर आए वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिख, बौद्ध व ईसाइयों को अपना नागरिक माने। पदाधिकारी ने विपक्षी दलों के विरोध को तत्कालिक बताते हुए उम्मीद जताई कि अधिकांश दल इसके पक्ष में आएंगे, क्योंकि यह सियासत का नहीं मानवता का मामला है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी समेत अन्य दलों के नेता भी इसकी मांग करते रहे हैं। संसद से लेकर चुनावी सभाओं में यह मुद्दा उठाया है।

संघ ने इसके लिए एक वेबसाइट सीएबी.जीईटीएफएसीटीएस.इन (cab.getfacts.in) भी बनाई है, जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ असम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र भी जिसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख व इसाई के नागरिकता के मुद्दे के समाधान का वादा किया था।

आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी भी प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पर उनका आना अपने देश में प्रताड़ना से नहीं है। जो आए हैं वह घुसपैठ कर आए हैं। किसी इस्लामिक देश में धर्म के आधार पर मुस्लिमों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। लिहाजा मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अन्य वजहों से यदि कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में शरण लेना चाहता है तो इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। वह वैध तरीके से देश में आएं। वीजा व शरणार्थी के तौर पर आवेदन करें। वैध तरीके से आने पर अदनान सामी जैसे लोगों को भी देश की नागरिकता मिली है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह ऐसा कानून बनाएंगे जिससे दूसरे देशों में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण मिल सके।

संसद में मंत्रियों की भी लग रही है क्लास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवस्था बनाने की जो परंपरा शुरू की है उसमें मंत्रियों के लिए भी छूट नहीं है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें इनकी ओर से मंत्रियों को ताकीद की जा रही है।

शुक्रवार को लोकसभा में उस वक्त बिरला ने पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो को टोक दिया जब वह आगे आकर अपने सीनियर मंत्री प्रकाश जावडेकर से बातचीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव को टोका था और नाराजगी जताई थी कि वह प्रश्नकाल में पूरा ध्यान नहीं लगा रहे हैं।

दूसरी ओर राज्यसभा में मंत्रियों की गैरहाजिरी का भी मुद्दा उठा। सभापति वैंकेया नायडू ने नाखुशी जताई और कहा, यह गंभीर मामला है। वह इसे लेकर बात करेंगे। सभापति इससे पहले सांसदों की गैर-हाजिरी को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सवाल पूछकर गायब रहने वाले सांसदों के नाम का भी जिक्र किया था। राज्यसभा में यह मुद्दा शुक्रवार को शून्यकाल शुरू होने के दौरान तब उठा, जब सभापति ने कार्यसूची के मुताबिक, दस्तावेजों को पेश करने के लिए मंत्रियों के नाम पुकारे। इनमें पहला नाम आरके सिंह का था जो सदन से अनुपस्थित थे। दूसरा नाम अनुराग सिंह ठाकुर का था। सदन में मौजूद मंत्री सोम प्रकाश ने खड़े होकर उसके दस्तावेज पेश करने की कोशिश की, पर सभापति ने अनुमति न लेने का मुद्दा खड़े करते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया।

2018 में देश में थे कैंसर के 15.86 लाख मरीज

▶ हर्षवर्धन बोले, हेल्थ केयर सिस्टम में है विभिन्न स्तरों पर जांच-इलाज की सुविधा

▶ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बीमारी के नियंत्रण के चल रहे कार्यक्रम

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन। इस दौरान सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (दाएं) भी मौजूद रहे। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2018 में देश में कैंसर के 15.86 लाख मरीज थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में विभिन्न स्तरों पर कैंसर की जांच की जाती है और उसका इलाज किया जाता है। इस बीमारी का इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रोग दबाने वाली दवाओं से किया जाता है।

प्रश्नकाल के दौरान एक लिखित उत्तर में हर्षवर्धन ने कहा, 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार, 2018 में कैंसर के 15,86,571 मामले थे।' उन्होंने कहा कि डीएम (मेडिकल ओन्कोलॉजी), एमसीएच (सर्जिकल ओन्कोलॉजी) और एमडी (रेडिएशन ओन्कोलॉजी) के साथ डॉक्टर उच्चस्तरीय तृतीय केयर अस्पतालों में कैंसर रोगियों की चिकित्सा करते हैं। जनरल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन आदि जैसे अन्य डॉक्टर भी सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करते हैं। कैंसर के प्रकार और उसकी जगह पर इलाज निर्भर करता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के संबंध में केंद्रीय स्तर पर सूचना दर्ज नहीं की जाती है। स्वास्थ्य राज्य का विशेष है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार कैंसर समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करती है।

हर्षवर्धन ने कहा, 'भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है।' उन्होंने कहा कि इस प्रयास में कैंसर रोकथाम, जांच, शीघ्र पता लगाना और इलाज के लिए उपयुक्त स्तर के संस्थान में भेजने के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।

देश के 10 फीसद से अधिक वयस्कों में मनोविकार : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 10 फीसद से अधिक लोग मनोविकार से पीड़ित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के जरिये सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाया था। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के 10.6 फीसद लोग मनोविकार से पीड़ित मिले। जिन राज्यों में सर्वेक्षण किया गया, उनमें मणिपुर को छोड़कर सभी 12 राज्यों में कम-से-कम एक मानसिक अस्पताल है। सभी राज्यों के अस्पतालों में एक मनोरोग विभाग है और सामान्य अस्पतालों में मनोरोग इकाई है। कुछ अस्पतालों में नशामुक्ति केंद्र भी हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए राज्यों में 450 सचल मानसिक इकाइयां और 249 नशामुक्ति केंद्र भी हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि हालांकि जन स्वास्थ्य और अस्पतालों की स्थापना मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस काम में राज्यों की मदद करती है।

डेंगू के डंक का होगा खात्मा, विकसित की जा रही वैक्सीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आने वाले कुछ सालों में डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से निपटना मुश्किल नहीं होगा। भारत में इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन का विकास किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि एक बार डेंगू का वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद इसके मरीजों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी।

दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में लोगों के बड़ी संख्या में डेंगू से पीड़ित होने का मुद्दा उठाया था। वे जानना चाहते थे कि केंद्र सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? जवाब देते हुए हर्षवर्धन ने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर काटने के कारण होता है, जो साफ पानी में ही पैदा होता है। स्वास्थ्य राज्यों का विषय होने के कारण इसकी रोकथाम व आम लोगों में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके लिए केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पर्याप्त सहायता मुहैया करा रही है। उन्होंने सदन को डेंगू के वैक्सीन विकसित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा, वैक्सीन का विकास भारत में ही किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। उनके अनुसार जल्द ही इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रणनीति

कांग्रेस नागरिकता संशोधन विधेयक के मामले में सरकार को चुनौती देने की रणनीति बना रही है, उसने इसके प्रयास भी तेज कर दिए हैं, आठ साथी दलों के आश्वासन से वह काफी उत्साहित है

नागरिकता बिल के विरोध की गोलबंदी में जुटी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▶ विधेयक को रास की प्रवर समिति के पास भेजने का करेगी प्रयास, शिवसेना देगी सरकार का साथ

▶ सरकार की राह रोकने के साथ पार्टी के अंदर से उलटे सुर को रोकना कांग्रेस की दोहरी चुनौती

कांग्रेस ने बहुचर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने का फैसला करते हुए उसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सियासी गोलबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, सपा, माकपा, भाकपा, द्रमुक और राजद समेत करीब आठ राजनीतिक दलों ने भी विधेयक का विरोध करने का इरादा जाहिर कर दिया है। विपक्षी खेमे के इस रुख को देखते हुए ही कांग्रेस राज्यसभा में विधेयक पर सरकार के संख्या बल को चुनौती देने की रणनीति बना रही है।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर काफी विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल बताते हुए विरोध करने का फैसला किया है। हालांकि अंदरखाने कांग्रेस में इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा कि अनुच्छेद 370 की तरह नागरिकता विधेयक पर भी पार्टी के भीतर से समर्थन के मुखर सुर निकल सकते हैं। इसी आशंका के चलते नागरिकता विधेयक पर पार्टी में पिछले कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी और पी चिदंबरम ने गुरुवार को साफ कर दिया कि विधेयक का मौजूदा स्वरूप धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी।

कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान की भावना के खिलाफ है और हम इसका विरोध करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि इसमें एक धार्मिक समुदाय को बाहर किया जाना सभी को बराबर मानने की संविधान की भावना के खिलाफ है। लोकसभा में राजग सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और विपक्ष संख्या बल के हिसाब से विधेयक का रास्ता नहीं रोक पाएगा।

कांग्रेस इसीलिए राज्यसभा में अधिक से अधिक दलों को साथ जुटाकर विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के सियासी दांव से सरकार को घेरना चाहती है। मगर आंकड़ों की कसौटी पर बहुमत न होते हुए भी राज्यसभा में राजग का पलड़ा भारी दिख रहा है। राजग और उसके समर्थक दलों का आंकड़ा मिला दिया जाए तो 240 सदस्यीय सदन में सरकार का संख्या बल 128 तक पहुंच जाएगा जबकि विपक्षी खेमा 105 के आंकड़े तक ही पहुंचता दिख रहा है। राजग को बीजद, वाइएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है जबकि कांग्रेस की अगुआई वाले विपक्षी संग्रग को नागरिकता बिल पर तृणमूल, वामदल, सपा और बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलने के पुख्ता संकेत हैं। हालांकि कांग्रेस की नई सियासी दोस्त बनी शिवसेना ने अपने वैचारिक एजेंडे से पीछे नहीं हटने के इरादे जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी। शिवसेना ने अपने इस रुख को लेकर कांग्रेस और राकांपा को रूबरू कराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इसका महाराष्ट्र की सियासत और सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक : सोमवार को संसद में पेश होने जा रहा नागरिकता संशोधन विधेयक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ करेगा। विधेयक में इन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और इसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

सरकारी आवास खाली करने के लिए तीन पूर्व सांसदों को नोटिस

नई दिल्ली, एएनआइ : लोकसभा की आवासीय समिति ने विभिन्न दलों के तीन पूर्व सांसदों को नोटिस जारी कर सरकारी आवास तुरंत खाली करने को कहा है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिन तीन पूर्व सांसदों को सरकारी आवास तुरंत खाली करने का नोटिस भेजा गया है उनके नाम क्रमशः तेदेपा के मुरली मोहन मगंती, भाजपा के मनोहर उटवाल और अन्नाद्रमुक के गोपाल हैं। तीनों ही पूर्व सांसदों ने अपने आवासों पर ताला लगा रखा है। आवासीय समिति ने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने सरकार आवास खाली नहीं किए तो दिशा निर्देशों के मुताबिक पंचनामा के बाद आवासों को जब्त कर लिया जाएगा।

ज्ञात हो, मुरली मोहन मगंती दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी, मनोहर उटवाल मध्य प्रदेश के देवास और गोपाल के. तमिलनाडु में नागपट्टिनम सीट से सांसद थे। बता दें कि आवासीय समिति में अधिकतम 12 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी

9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे। वह बोकारो और बरही में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बोकारो से भाजपा के प्रत्याशी विरंची नारायण, जबकि बरही से भाजपा के प्रत्याशी मनोज यादव हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 7 दिसंबर 2019

झारखंड में मतदान के उल्लास के बीच लोकतंत्र के जश्न के अहम भागीदार मतदानकर्मी इन दिनों खासे उत्साह में हैं। शुक्रवार को जमशेदपुर में को-ऑपरेटिव कॉलेज से चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना होती महिला मतदानकर्मी अर्चना (बाएं) और पूजा का उत्साह भी देखने लायक था। रवि चौधरी

20 सीटों पर विरोधियों से 'बीस' होने की सियासी जंग

दूसरा चरण ▶ सीएम, स्पीकर, मंत्री सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

आज सुबह सात बजे से पड़ेंगे वोट, मतदाता तय करेंगे 260 प्रत्याशियों का भविष्य

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 13 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब बारी दूसरे चरण के सबसे बड़े सियासी दंगल की है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस चरण में सबसे अधिक 20 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्पीकर डॉ. दिनेश उरांव, भाजपा के बागी नेता सरयू राय, मंत्री रामचंद्र सहिस, नीलकंठ सिंह मुंडा जैसे दिग्गजों सहित कुल 260 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इस चरण की 20 में 16 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं, जहां लगभग 50 फीसद आदिवासी मतदाता हैं।

दूसरे चरण की इन 20 सीटों के 6,066 मतदान केंद्रों पर 48,25,038 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,016 मतदान शहरी तथा 5,050 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चुनाव आयोग तथा जिला प्रशासन ने इन सीटों पर शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त मतदान कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतदान कर्मी सुरक्षित अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। चूंकि इस चरण में कई विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुर्गम व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुल 101 बूथों पर पोलिंग पार्टियां हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गईं। इसमें चार हेलीकॉप्टर लगाए गए। शनिवार को इन हेलीकॉप्टर से निगहबानी की जाएगी, जबकि आपात स्थिति के लिए जमशेदपुर एयरपोर्ट पर एक एयर एंबुलेंस तैनात किया गया है। इस चरण में नक्सल दृष्टिकोण से 949 अति संवेदनशील तथा 762 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इनके अलावा अन्य कारणों से 762 संवेदनशील तथा 2005 अति संवेदनशील मतदान केंद्र निर्धारित हैं। सिर्फ 1,586 सामान्य मतदान केंद्र हैं। इधर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराने के लिए लगभग 30 हजार चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मतदान होना है, वहां सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

कुल सीट 20 | कुल प्रत्याशी 260 | महिला प्रत्याशी 29

इन सीटों पर होना है मतदान

सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक : जमशेदपुर पूर्वी तथा जमशेदपुर पश्चिमी

सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक : बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, तमाड़, मांडर, तोरपा, खूंटी, सिसई, सिमडेगा तथा कोलेबिरा

सुरक्षा कारणों से अंतिम समय में बदले गए 101 बूथ : चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों से अंतिम समय में 101 बूथ बदल दिए हैं। घाटशिला, सरायकेला तथा सिमडेगा में एक-एक, पोटका में दो, चक्रधरपुर में सात खरसावां में नौ, चाईबासा में छह, तमाड़ में 10, जगन्नाथपुर में 19 तथा मनोहरपुर में सबसे अधिक 45 बूथ बदले गए। इन बूथों पर मतदाताओं को ले जाने तथा वापस पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है।

खास बातें

- 20 सीटों में नौ सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं। ये सभी एसटी सीटें हैं। इनमें घाटशिला, पोटका, खरसावां, चाईबासा, मझगांव मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खूंटी तथा सिमडेगा शामिल हैं।
- जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी तथा चाईबासा के वोटर बूथ एप के माध्यम से देख सकेंगे कि मतदान केंद्रों पर कितनी लंबी लाइन है। मतदाता टोकन नंबर के हिसाब से अपना क्रम आने पर सुविधापूर्ण तरीके से मतदान कर सकेंगे। यह प्रयोग पहली बार राज्य के सात विस क्षेत्रों में हो रहा है।

भाजपा के लिए विपक्ष से ज्यादा अपने बने खतरा

- भितरघात की बनी हुई है आशंका, पार्टी नेतृत्व सतर्क
- अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ खुले मोर्चे से केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं है अनजान

राज्य ब्यूरो, रांची

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत पांच दिसंबर की अपनी जमशेदपुर की रैली में साफ कहा था कि जहां कमल है, वहां मोदी है। यह संदेश सिर्फ जमशेदपुर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भाजपा कैडरों के लिए था। स्पष्ट है कि चुनाव में बागियों के उतरने और भितरघात की आशंका से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अंजान नहीं है। भाजपा को इस चुनाव में विपक्ष से ज्यादा खतरा अपनों से है।

जमशेदपुर पूर्वी की विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा सरकार में मंत्री रहे सरयू राय चुनौती दे रहे हैं। यह सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जमशेदपुर सीट इकलौती सीट नहीं है, जिस पर भाजपा को किसी अपने से ही चुनौती मिल रही है। इस चुनाव में करीब एक दर्जन सीटों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं बागी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, तो कहीं दूसरे दलों में शामिल हो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहले चरण के चुनाव में राधाकृष्ण किशोर और बैद्यनाथ राम जैसे नेताओं ने भाजपा छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कीं। दूसरे चरण के चुनाव में सरयू राय के अलावा बहरागोड़ा से समीर मोहंती भी बागी हो मैदान में खड़े हैं। वे झामुमो में शामिल हो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार कुणाल षड़ंगी को चुनौती दे रहे हैं। कोडरमा से शालिनी गुप्ता को टिकट की आस थी, टिकट नहीं मिला तो वे आजसू में शामिल हो गईं और मंत्री नीरा यादव के खिलाफ उतर गईं। बरकट्ठा से अमित यादव भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जानकी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बोरियो से ताला मरांडी, गोमिया से माधव लाल सिंह, बरही से उमाशंकर अकेला जैसे तमाम नेता हैं, जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये वे चेहरे हैं, जो सामने हैं। इनके मददगार के रूप में खुलकर और छिपकर काम करने वाले भी भाजपा के ही कैडर हैं। स्थिति यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष अब खुद बूथ स्तर की समीक्षा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनकी तमाम शिकायतों को चुनाव बाद दूर करने का भरोसा भी दिला रहे हैं।

पार्टी ने लिया कड़ा फैसला

भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ उतरने वालों और अधिकृत प्रत्याशी का विरोध करने वालों को लेकर भाजपा ने हाल ही में कड़ा फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा की ओर से जारी संदेश में साफ कहा गया है कि भाजपा झारखंड प्रदेश के वैसे नेता जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं या प्रत्याशी का सार्वजनिक विरोध कर रहे हैं, अथवा संगठन के निर्देश के विपरीत कार्य करते हुए अनुशासन तोड़ रहे हैं, ऐसे सभी लोग पार्टी से स्वत: निष्कासित माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के साथ बना झारखंड विकास में पीछे क्यों : बघेल

जागरण संवाददाता, रामगढ़

- छग के मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के दुलमी में की चुनावी सभा

छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य एक साथ बने, तो झारखंड विकास में पीछे क्यों रह गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात शुक्रवार को झारखंड के रामगढ़ के दुलमी में चुनावी सभा में कही। उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में किसानों से किए वादे को पूरा करते हुए दो लाख तक का कर्ज माफ कर दिया। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को चार गुना मुआवजा देने का कानून बनाया जाएगा।

बघेल ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही। उसके बाद भी किसान आत्महत्या करते रहे, बेरोजगारी सिर चढ़कर बोलती रही। आखिर ऐसा क्यों। बघेल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग काफी सीधे-साधे और भोले होते हैं। आप झारखंड में छत्तीसगढ़ का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं। कहा कि रघुवर दास को इस बार वह अपने साथ छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे।

इस दौरान उन्होंने कुछ वादे भी किए। कहा, महागठबंधन की सरकार बनते ही हर घर को 35 किलो अनाज, बेरोजगारों को नौकरी, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लोगों से अपील की कि महागठबंधन प्रत्याशी को हर हाल में जीत दिलाकर परिवर्तन की बयार को तेज करें।

मेरी जमानत का आदेश ठीक से पढ़ें भाजपा नेता : चिदंबरम

राज्य ब्यूरो, रांची

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर छूटे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत शर्तों के उल्लंघन के भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं को आरोप लगाने के पहले सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। एक दिन पहले चिदंबरम द्वारा खुद को पाक-साफ बताने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा था कि इस तरह से सार्वजनिक बयान देना जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। इसके बाद भाजपा के कई नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए। चिदंबरम ने हैदराबाद मुठभेड़ की घटना को जांच का मसला बताते हुए कहा कि तफ्तीश से ही पता चलेगा कि मुठभेड़ असली है या फर्जी।

यहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए शुक्रवार को वोट की अपील करने पहुंचे चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कई सवालों से पीछा छुड़ाते भी नजर आए। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को चुनाव के इर्दगिर्द ही रखने का आग्रह किया। दावा किया कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के साथ मिलकर झारखंड में एक काबिल सरकार देगी, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिरकार कैसे कांग्रेस जेल में बंद लालू प्रसाद और कभी भाजपा की सहयोगी रही झामुमो के साथ काबिल सरकार का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेसियों 'बेल-गाड़ी' पर सवार बताए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि झारखंड में कितने रोजगार पैदा किए। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। सरकार ने 4000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं।

हरियाणा में डेंट किया, झारखंड में डिफीट करेंगे: हरियाणा-महाराष्ट्र के हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों से चिदंबरम उत्साहित दिखे। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में हमने भाजपा को डेंट किया (नुकसान पहुंचाया), महाराष्ट्र में डिनाई किया (रास्ता रोका) और अब झारखंड में भाजपा को डिफीट कर सत्ता से बाहर करेंगे।

झारखंड के रांची में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता करते पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (दाएं), साथ में सुबोधकांत सहाय (मध्य में) और आरपीएन सिंह। जागरण

देश की विकास दर पांच प्रतिशत के नीचे जाएगी

चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था भारी संकट में है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास दर पांच प्रतिशत के भी नीचे जाने की आशंका जताई। कहा कि रिजर्व बैंक ने इसी वर्ष फरवरी में देश का विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था और सिर्फ दस माह बाद दिसंबर में पांच प्रतिशत विकास दर की बात कही है। 10 माह के भीतर इतनी अधिक गिरावट विकास दर में कभी नहीं देखी गई। देश की अर्थव्यवस्था नाकाबिल लोगों के हाथ में है। सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर पांच प्रतिशत से नीचे खिसक गया है। यह देश के लिए गंभीर स्थिति है।

विदर्भ सिंचाई घोटाले में एसीबी ने अजीत पवार को बताया निर्दोष

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राकांपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को करोड़ों रुपये के विदर्भ सिंचाई घोटाले में निर्दोष करार दिया है। बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को सौंपे गए शपथपत्र में एसीबी ने राज्य में सिंचाई परियोजना की मंजूरी और लागू करने में हुई अनियमिता में राकांपा नेता की संलिप्तता से इन्कार किया है। एसीबी ने कहा है कि मामले में जांच बंद नहीं की गई है।

- बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने जांच एजेंसी से राकांपा नेता पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था
- एसीबी ने कहा, अभी बंद नहीं की गई है मामले की जांच

अजीत महाराष्ट्र में 1999 से 2009 के बीच जल संसाधन विकास मंत्री थे। फाइल

एसीबी ने यह शपथ पत्र शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी सरकार के 28 नवंबर को शपथ लेने से एक दिन पहले 27 नवंबर को दाखिल किया था। कोर्ट ने एसीबी से अजीत की भूमिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। पुणे जिले में बारामती से राकांपा विधायक अजीत महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा सरकार में 1999 से 2009 के बीच जल संसाधन विकास मंत्री थे। इसी कार्यकाल में सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दी गई थी जिसमें अनियमितता का आरोप लगाया गया है।

शपथपत्र में कहा गया है कि आवंटित काम को लागू करने वाली एजेंसियों की ओर से चूक हुई है। इसमें इंजीनियर, डिविजनल अकाउंटेंट और इन परियोजनाओं के ठेकेदार शामिल हैं। इसमें कहा गया है, 'लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज के लिए वीआइडीसी चेयरमैन जल संसाधन विकास (डब्ल्यूआरडी) मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कानूनी कर्तव्य उनके दायरे में नहीं आता है।'

बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में वीआइडीसी की 45 परियोजनाओं से संबंधित कुल 2,654 टेंडरों को लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं। एक पीआइएल अतुल जगताप ने अमरावती में सिंचाई परियोजना के लिए टेंडर आवंटित किए जाने को लेकर दायर की है जिसमें अजीत को प्रतिवादी बनाया गया है।

25 नवंबर को एसीबी ने कहा था कि उसने सिंचाई परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के नौ मामलों की जांच बंद कर दी है। साथ ही यह स्पष्ट किया था कि इनमें से एक भी मामला अजीत से जुड़ा नहीं है।

27 नवंबर के शपथपत्र के बारे में एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने एजेंसी से 28 नवंबर से पहले स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। पूर्व के शपथपत्र में सरकार से राय मांगने की जानकारी दी थी। अब सरकार से हमें राय मिल चुकी है कि अजीत पवार इसमें शामिल नहीं हैं और कुछ दिनों पहले यही हम कोर्ट को बता चुके हैं।

मप्र में अज्ञात किसानों के नाम पर दर्ज प्रकरण वापस लेगी सरकार

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसान आंदोलन के वक्त अज्ञात किसानों के नाम पर दर्ज प्रकरणों को वापस लेगी। बताया जाता है कि करीब 45 हजार अज्ञात किसानों को आरोपित बनाया गया था। वहीं, यह भी तय किया गया है कि गंभीर अपराध के मामलों में जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा।

यह निर्णय गृह मंत्री बाला बच्चन, विधि मंत्री पीसी शर्मा के साथ विधायक, पूर्व विधायक और किसान नेताओं की बैठक में लिया गया। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि करीब 45 हजार अज्ञात किसानों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुछ मामलों में सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। यदि प्रकरण वापसी पर निर्णय जल्द नहीं हुआ तो फिर इस प्रक्रिया का फायदा नहीं होगा। किसान नेताओं ने बताया कि प्रशासन ने बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए झठे मामले दर्ज किए थे।

बैठक में गृह मंत्री और विधि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी किसानों के प्रकरण वापस लिए जाएंगे। अज्ञात किसानों के नाम पर दर्ज प्रकरणों को सबसे पहले वापस लिया जाएगा। गंभीर मामलों का परीक्षण करने के बाद निर्णय होगा।

उद्धव ने की पीएम मोदी की अगवानी...

पुणे में शुक्रवार को हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (दाएं से दूसरे) ने की। भाजपा से नाता टूटने और राकांपा तथा कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना की अगुआई वाली सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (कतार में बाएं), राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (दाएं से तीसरे) और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (दाएं) भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी पुणे में हो रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रेट्र

सुलह के संकेत

बंगाल के राज्यपाल ने कहा, संविधान में बातचीत ही एकमात्र रास्ता, एक दिन पहले ही विधानसभा में प्रवेश को लेकर दिखी थी टकराव की स्थिति

सीएम से हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार : धनखड़

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में राज्य सरकार और राजभवन के बीच जारी टकराव के बीच शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह विवाद को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हैं। शुक्रवार को डॉ. बीआर आंबेडकर की पुण्यतिथि पर विधानसभा परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा-'मेरा मानना है कि संविधान में बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मैं मुख्यमंत्री के साथ राजभवन या राज्य सचिवालय नवान्न कहीं भी किसी भी मुद्दे पर बातचीत को तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूं। गत मंगलवार को मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, लेकिन आज तक राज्य सरकार की ओर से मुझसे संपर्क नहीं किया गया।'

गौरतलब है कि गुरुवार को भी राज्यपाल विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित रहने के कारण वीवीआइपी गेट पर ताला लगा था। राज्यपाल बाद में तीन नंबर गेट से अंदर गए। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि यह उनका नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अपमान है। इसके बाद शुक्रवार को राज्यपाल फिर विधानसभा पहुंचे। राज्यपाल के साथ उनकी पत्नी भी थीं।

राज्यपाल ने अपने लिए निर्धारित गेट से विधानसभा में प्रवेश किया, जहां मार्शल, अन्य अधिकारियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी उनका स्वागत करने नहीं पहुंच सके क्योंकि वह कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक में थे।

हालांकि, राज्यपाल धनखड़ ने विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि गुरुवार को जब उन्होंने अध्यक्ष को अपने यहां आने की जानकारी दी थी तो उन्होंने काफी जल्दी उसका जवाब दिया था। अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि वह समिति की एक बैठक में व्यस्त होंगे इसलिए उनकी अगवानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका ध्यान रखा जाएगा।

ममता बनर्जी फाइल

जगदीप धनखड़ फाइल

एनआरसी और सीएबी एक ही सिक्के के दो पहलू : ममता बनर्जी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फिर दो-टूक कहा कि इसे बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा।

कोलकाता में तृणमूल समर्थकों की सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा-'तृणमूल एक और आजादी की लड़ाई लड़ेगी। आप तैयार रहें। आजादी के 72 साल बाद अचानक से नागरिकता निर्धारित नहीं की जा सकती। मैं एनआरसी को नहीं मानती।'

भाजपा के पूरे देश में एनआरसी लागू करने के प्रस्ताव पर ममता ने कहा-'यह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर आप सभी समुदायों के लोगों को नागरिकता देंगे तो हम इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर आप धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे।

पीएम मोदी के चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- चुनाव अधिकारी की कार्यवाही वैधानिक, याचिकाकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। वह न तो वाराणसी का मतदाता है और न लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहा है। उसे पीड़ित पक्ष नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याची तेजबहादुर को 24 घंटे में आपत्ति दाखिल करने का अधिकार था, किंतु याचिका में यह आधार लिया गया है कि उसे आपत्ति करने का 24 घंटे का समय नहीं दिया गया।

दरअसल, वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव ने पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में तेज बहादुर ने पीएम मोदी का चुनाव रद करने की मांग की थी। चुनाव अधिकारी पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी के दबाव में गलत तरीके से चुनाव अधिकारी ने नामांकन रद किया था, जबकि गलत तथ्य देने व सही तथ्य छिपाने के आधार पर नामांकन निरस्त किया गया था। तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। याचिका पर कई तारीखों पर चली बहस और सभी पक्ष सुनने के बाद 23 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

पीएम मोदी के वरिष्ठ अधिवक्ता एडिशनल सालीसिटर जनरल एवं लॉ कमीशन के सदस्य सत्यपाल जैन के मुताबिक कोर्ट ने उनकी इस दलील को मानते हुए तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज कर दी है कि वह वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं हैं। साथ ही नामांकन खारिज होने के बाद वह वाराणसी सीट से प्रत्याशी भी नहीं थे। लिहाजा निर्वाचन को वही व्यक्ति चुनौती दे सकता है जो कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का वोटर और प्रत्याशी भी रहा हो।

मुठभेड़ का समर्थन, विरोध में भी सुर

आम लोगों के साथ-साथ राजनेता भी समर्थन में, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश का नतीजा है कि हैदराबाद में आरोपितों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का लोगों ने खुलकर समर्थन किया। वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत कुछ राजनेताओं ने आरोपितों को इस तरह सजा देने पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग भी उठाई। यही नहीं, इस मुद्दे पर एक ही पार्टी के अलग-अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी अलग-अलग देखने को मिली। यहां तक कि इस मुद्दे पर महिला सांसदों की राय भी बंटी दिखी।

हैदराबाद में सुबह पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर तेलंगाना पुलिस के लिए बधाइयों का तांता लग गया। राज्यसभा में पहले ही आरोपितों की लिंचिंग (भीड़ के हवाले करना) की मांग करने वाली सपा सांसद जया बच्चन ने मुठभेड़ का समर्थन करते हुए कहा, 'देर आए, दुरुस्त आए।' लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती भी मुठभेड़ के पक्ष में खुलकर सामने आए। भाजपा की ओर से मीनाक्षी लेखी ने मुठभेड़ का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस के पास हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए भी होते हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और राकांपा के साथ-साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मुठभेड़ में आरोपितों के मार गिराए जाने को गैरन्यायिक प्रक्रिया बताते हुए इसकी जांच की मांग की। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने संसद परिसर में कहा, 'जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए।' उन्होंने कहा कि यदि कानूनी प्रक्रिया पूरा किए बिना ही उन्हें मार देते हैं तो फिर देश में अदालत, कानून और पुलिस की क्या जरूरत है।

पी. चिदंबरम ने मुठभेड़ की जांच की मांग करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वह इसकी विस्तृत जांच चाहते हैं ताकि यह साफ हो सके यह मुठभेड़ असली थी या फिर फर्जी। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर मुठभेड़ पर सवाल उठाने से बचते दिखे। उन्होंने गैरन्यायिक हत्या का विरोध करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने तक हमें इसकी आलोचना करने से बचना चाहिए। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुठभेड़ में आरोपितों के मारे जाने पर आम लोगों में खुशी को दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आक्रोश का नतीजा बताया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि लोगों का अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं रह जाना, चिंता का विषय है। घटना के बाद आरोपितों को जल्द से जल्द और कड़ी सजा की मांग करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुठभेड़ पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचने का प्रयास किया। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वह आरोपितों की मौत की सजा का समर्थन करती हैं, लेकिन यह अदालत की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर लोग बंटे दिखे। कई ने तेलंगाना पुलिस को बधाइयां दीं तो कुछ ने इस तरह आरोपितों को सजा देने का विरोध करते हुए इसे लंबे समय में कानून-व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। वैसे मुठभेड़ के समर्थक विरोधियों पर भारी दिखे।

तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शादनगर में शुक्रवार को पुलिस ने महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपितों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके बाद मौके पर साक्ष्य जुटाते फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जुटे लोग। ● प्रेट्र

संस्कारों की कमी है घटनाओं की वजह

दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण युवाओं में संस्कारों की कमी और खुद पर संयम न होना है। यदि खुद पर संयम नहीं है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वह सही या गलत में अंतर कर सके। इसी मानसिक स्थिति के दौरान वह दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसके बाद स्वयं को बचाने और सुबूत खत्म करने के उद्देश्य से हैदराबाद और उन्नाव जैसी वीभत्स घटनाएं सामने आती हैं। अगर आरोपित यह मानते हैं कि वे दुष्कर्म के बाद पीड़ित को जलाकर बच सकते हैं तो उनकी गलतफहमी है। युवाओं में अशिक्षा, परिवार से अलग रहना और अकेले रहना भी दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने का कारण है। इसके साथ ही जब व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो संयम खोने की स्थिति में वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाया जाए। सीसीटीवी कैमरों के जरिये लगातार और अधिक से अधिक स्थानों पर मॉनीटरिंग की जाए। विशेष रूप से ऐसे स्थान, जहां रात में लोगों की आवाजाही कम हो जाती है, वहां अगर सीसीटीवी से निगरानी संभव नहीं है तो वहां पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी होने से इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के मन में एक डर रहता है। इसके अलावा, ऐसी घटनाएं होने के बाद पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी और कड़ी सजा दोषियों को मिलेगी, उससे अपराधियों के मन में ऐसी घटनाएं न करने का डर पैदा होगा, जो बहुत जरूरी है। कानून का डर होने से अन्य अपराधों की तरह दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। अश्लील साहित्य को लेकर अब तक ऐसा कोई सर्वे या अध्ययन सामने नहीं आया है कि ऐसा देखने या पढ़ने वालों ने दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया हो। यह एक वजह तो हो सकती है, लेकिन यहां सवाल फिर से मानसिक स्थिति और संयम का ही खड़ा होता है। संयमित, संस्कारित और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी भी दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता।

(लोकेश चौहान से बातचीत पर आधारित)

नीरज कुमार
पूर्व पुलिस आयुक्त, दिल्ली

इस तरह ढेर हुए आरोपित

पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस में एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। पुलिस ने कहा कि वह आरोपितों को घटनास्थल पर लेकर गई थी। इसी दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और फरार होने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में सभी आरोपित मारे गए। साइबराबाद पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस वहीं की जहां पर आरोपितों को मौत घाट उतारा गया। आइये तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं कि तेलंगाना पुलिस ने यह एनकाउंटर कैसे अंजाम दिया।

1 पुलिस ने आरोपितों को घटनास्थल पर ले जाने के लिए बस में बैठाया।

2 घटनास्थल की ओर चली बस।

3 घटनास्थल पर पहुंचते ही आरोपितों ने पुलिस पर हमला बोल दिया।

4 दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

5 मुठभेड़ में चारों आरोपित मारे गए।

इलस्ट्रेशन: अवधेश

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वीसी सज्जानार

वारंगल में एसिड फेंककर महिला की हत्या के तीन आरोपितों का एनकाउंटर करने के ग्यारह साल बाद, तेलंगाना पुलिस ने अब हैदराबाद में पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर जला देने के आरोपितों का एनकाउंटर किया है। जिस अधिकारी ने इन दोनों एनकाउंटर में अहम भूमिका निभाई, वह 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी वीसी सज्जानार हैं। वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं।

कौन हैं सज्जानार : वीसी सज्जानार कर्नाटक के रहने वाले हैं और भारतीय पुलिस सेवा के 1996 बैच के हैं। 2008 में वह वारंगल के पुलिस अधीक्षक थे, जब दो लड़कियों पर तेजाब फेंकने के आरोपित तीन युवकों को पुलिस ने गोली मार दी थी। बाद में दोनों लड़कियों ने दम तोड़ दिया था। सज्जानार को एक नायक के रूप में सराहा गया, जबकि उन परिस्थितियों की जांच के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया, जो मुठभेड़ का कारण बनीं।

कई पद संभाले: साइबराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात होने से पहले, सज्जानार ने नक्सल विरोधी इकाई और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के आइजी के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में कई शीर्ष माओवादियों की गिरफ्तारी हुई और कइयों ने आत्मसमर्पण किया।

इसलिए भी किया जाता है याद: तेलंगाना के मेदक जिले के एसपी रहते हुए उन्होंने अफीम तस्कर का एनकाउंटर किया था, जिन पर पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या के आरोप थे। उनको नक्सल नेता नइमुद्दीन की हत्या के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने नइमुद्दीन की हत्या तब की थी जब वो आइजी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच थे।

सोशल मीडिया पर छाये: सोशल मीडिया पर एनकाउंटर के लिए जहां लोग एक ओर सज्जनार को हीरो बता रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कानून के राज में इस तरह की घटना को अंजाम देना ख़तरनाक साबित हो सकता है।

वीसी सज्जानार ● फाइल फोटो

जनमत

मुद्दा

क्या इंटरनेट पर सर्व सुलभ पोर्नोग्राफी हैदराबाद या निर्भया कांड जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

25% देश में दर्ज दुष्कर्म के अपराधों में से औसतन इतने मामले में हो पाती है दोष सिद्धि। बाकी मामलों किसी न किसी आधार पर आरोपित सजा पाने से दूर रह जाते हैं।

पूरा मामला एक नजर में

27 नवंबर 2019: हैदराबाद के शादनगर में घर जा रही पशु चिकित्सक के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे जला दिया।

28 नवंबर: पशु चिकित्सक का अधजला शव शादनगर में एक पुलिया के नीचे मिला।

29 नवंबर: तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की छानबीन के दौरान 20 से 24 साल के उम्र के चार लोगों को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इस घटना को लेकर देश भर में लोगों ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। पुलिस ने टोल प्लाजा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस को जानकारी मिली कि एक ट्राला यहां करीब 8 घंटे तक खड़ा रहा। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और ट्राले के ड्राइवर और 3 हेल्परों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यहां इन आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया।

इसी दिन तेलंगाना के गृह मंत्री ने महमूद अली ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर बहन को फोन करने की बजाय 100 नंबर पर फोन करती तो उसे बचाया जा सकता था।

30 नवंबर: कोर्ट ने आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

01 दिसंबर: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की घोषणा की। इससे ये उम्मीद जगी कि इस दुस्साहसिक घटना के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी।

तेलंगाना पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम महेंद्र रेड्डी ने इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया।

02 दिसंबर: तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। सांसदों ने एक सुर में ऐसे मामलों में सख्त सजा के निर्धारण की मांग की। साथ ही त्वरित न्याय मिलने के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सदस्यों ने दुष्कर्म के दोषियों को भीड़ के हवाले करने और उन्हें नपुंसक बनाने तक के सुझाव दे डाले।

03 दिसंबर: चेरलापल्ली जेल में बंद चार आरोपितों में से एक ने किडनी की बीमारी का इलाज मुहैया कराने की मांग की है।

04 दिसंबर: मामले की सुनवाई के लिए महबूबनगर जिला अदालत में विशेष कोर्ट का गठन किया गया ताकि त्वरित न्याय हो।

06 दिसंबर: मामले के चारों आरोपितों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया।

हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आम तौर पर खुशी जताने वाली थी। ऐसा ही एक नजारा पटना में भी देखने को मिला, जहां छात्राओं ने इस तरह अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। ● प्रेट्र

कानूनी विशेषज्ञों ने की तत्काल जांच की मांग

नई दिल्ली, आइएएनएस : कानूनी विशेषज्ञों ने हैदराबाद में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के आरोपितों के एनकाउंटर में मारे जाने की तत्काल जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि न्याय प्रणाली और नागरिकों के मानवाधिकार में एक संतुलन होना चाहिए। प्रशासन को तत्काल घटना की जांच शुरू कर देनी चाहिए। प्रशासन को इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि यह सही में मुठभेड़ थी या पुलिस ने कोई खेल किया।

वरिष्ठ वकील पुनीत मित्तल ने कहा कि इस रहस्यमय मुठभेड़ की सच्चाई जानने के लिए घटना की तत्काल न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। मुठभेड़ का क्या कारण था, इसका पता लगाया जाना चाहिए। आरोपितों का परिवार भी मामले की जांच के लिए अदालत जा सकता है। एक और वरिष्ठ वकील संजय पारेख ने कहा कि कानून की नजर में एनकाउंटर को हत्या की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने कथित एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आम तौर पर आत्मरक्षा की बात सुनवाई के दौरान सामने आती है। लेकिन, इस परिस्थिति में मुठभेड़ की सत्यता जानने के लिए तत्काल जांच जरूरी है।

दुष्कर्म के इन मामलों ने देश को झकझोरा

निर्भया कांड के बाद अब तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने चारों आरोपितों को गोली मार दी है, लेकिन भारत में दुष्कर्म की यह कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। देश भर से दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो स्थिति भयावह है। जागरूकता के साथ कानून और सजा के प्रावधानों में सख्ती इस समस्या से निजात दिला सकती है।

32,500 देश भर में दुष्कर्म के दर्ज मामले

90 रोजाना सामने आए मामले

18,300 2017 में इतने मामले अदालतों ने निपटाए

1,27,800 लंबित मामलों में नहीं हो सका फैसला

(2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार)

भारत में दुष्कर्म के मामले

भारत में 1,28,000 से ज्यादा दुष्कर्म मामले 2017 के आखिर में अदालत में लंबित थे। अदालतों में लंबित मामलों के चलते पीड़ितों को न्याय पाने में सालों साल लग जाते हैं।

आयु अनुसार महिला पीड़िताओं की दर (फीसद में)

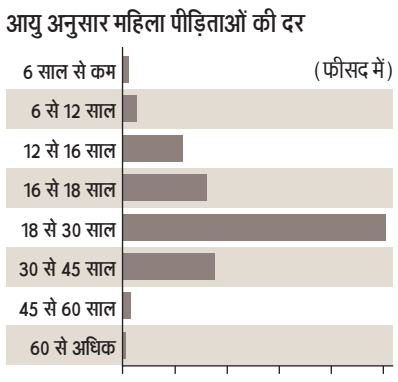

दुष्कर्म पीड़िताओं की संख्या प्रति एक लाख महिलाओं पर

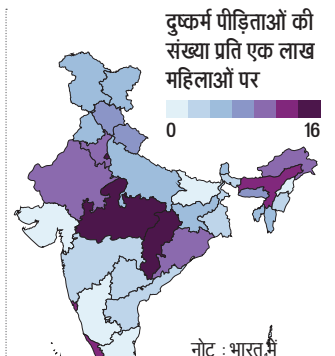

साल भर में कुल दुष्कर्म मामले (हजार में)

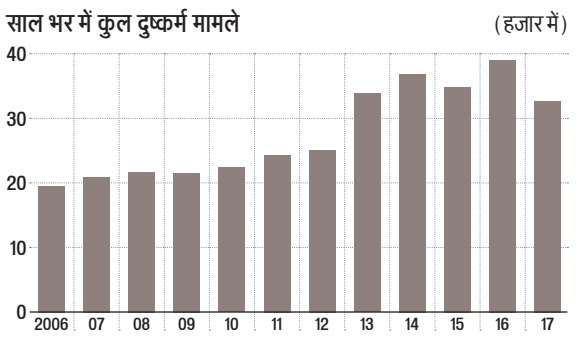

नोट: भारत में अपराध के आंकड़े प्राथमिक अपराध नियम के अनुसार हैं। यदि किसी मामले में जहां पर पीड़ित के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है, वहां पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार 'सबसे जघन्य अपराध' को प्राथमिक अपराध मानती है। इस मामले में दुष्कर्म मामले के आंकड़े नहीं होते हैं। (स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो)

चर्चित मामले

महिलाओं के खिलाफ क्रूर दुष्कर्म और हिंसा के मामले दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही देश को महिलाओं के प्रति असुरक्षित समझा जा रहा है। दुष्कर्म के ऐसे कई मामले हैं जो हाल ही में काफी चर्चित रहे हैं।

दिसंबर 2012: नई दिल्ली में एक 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। जिसकी बाद में मौत हो गई। पांच लोग और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक ने ट्रायल के दौरान आत्महत्या कर ली और चार को फांसी की सजा सुनाई गई। नाबालिग को तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महिला यौन हिंसा के खिलाफ लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो महिलाओं ने भी सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज बुलंद की। इसके बाद यौन अपराधों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया और साथ ही ऐसे मामलों में तेजी से ट्रायल चलाने की बात कही गई और पीछा करने को भी अपराध माना गया।

जनवरी 2018: जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामले सामने आया। इस मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया गया। इसमें तीन पुलिस वाले भी थे।

जुलाई 2019: उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक महिला ने 2017 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला के वकील एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जब ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी जिसमें वह यात्रा कर रहे थे। कार में महिला की दो रिश्तेदार भी थीं, जिनकी मौत हो गई। सेंगर ने दुष्कर्म और दुर्घटना में किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया।

20 सितंबर 2019: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर कानून की छात्रा ने दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

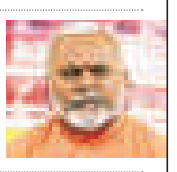

28 नवंबर 2019: हैदराबाद के नजदीक महिला पशु चिकित्सक की जली हुई लाश एक फ्लाईओवर के नीचे से मिली। चार लोगों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

5 दिसंबर 2019: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 23 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को कुछ लोगों ने मिलकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इनमें दुष्कर्म का आरोपी भी था। पीड़िता दुष्कर्म मामले की सुनवाई के लिए अदालत जा रही थी।

सोशल मीडिया के संदेशों में पुलिस दिखी हीरो

मुठभेड़ के बाद ट्रेंड करने लगे जस्टिसफॉर..., एनकाउंटर, हैदराबादहॉरर जैसे हैशटैग

कुछ ही घंटों में चार लाख से ज्यादा किए गए ट्वीट। दोपहर बाद मुठभेड़ के विरोध में भी सुनाई दिए सुर

नई दिल्ली, प्रेट्र : हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ बर्बरता के चारों आरोपितों की एनकाउंटर में मारे जाने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़े संदेशों की बाढ़ आ गई। शुक्रवार को सुबह के कुछ ही घंटों में इससे जुड़े चार लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। इस जघन्य वारदात के आरोपितों के इस तरह से मारे जाने पर कुछ लोग जहां खुशी व्यक्त कर रहे थे, वहीं कुछ ने इस तरीके पर चिंता व्यक्त की।

एनकाउंटर के बाद जस्टिसफॉर..., एनकाउंटर, हैदराबादहॉरर जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर तारीफों और मुखालफत के संदेशों के बीच कई यूजर्स ने साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानार की भी जमकर तारीफ की। वह वर्ष 2008 में इसी तरह की एक मुठभेड़ में शामिल थे, जिसे यूजर्स ने याद किया।

शुक्रवार सुबह जहां लाखों की संख्या में ट्विटर यूजर्स इस एनकाउंटर की तारीफ कर रहे थे, वहीं दोपहर को हैशटैग ह्यूमनराइट भी ट्रेंड करने लगा। 20 हजार से ज्यादा ट्वीट इस संबंध में किए गए और इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए जाने लगे। 'क्या मानवाधिकार दुष्कर्मियों के लिए नहीं हैं?' जैसे सवालों की बौछार भी लोगों ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर कर दी। इस पर एक यूजर ने लिखा, 'जब आतंकवादी और माओवादी बिना किसी अदालती कार्यवाही के एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो दुष्कर्मियों को क्यों बख्शा जाए।' हैशटैग एनकाउंटरनिर्भया से एक यूजर ने लिखा, 'निर्भया के दुष्कर्मी तिहाड़ जेल में सुअरों की तरह खा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर उनका भी एनकाउंटर पागल कुत्तों की तरह कर देना चाहिए। मानवाधिकार सिर्फ इंसानों के लिए हैं, दरिंदों के लिए नहीं।' एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, 'मानवाधिकार सिर्फ मानवों के लिए बने हैं, हैवानों के लिए नहीं। दुष्कर्मी=हैवान। ये केवल एनकाउंटर के लायक हैं।'

सोशल मीडिया पर कई ऐसे भी थे, जो पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते दिखे। सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने मुठभेड़ को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' करार देते कहा कि महिलाओं के नाम पर इस तरह की कार्रवाई गलत है। बिना जांच और अभियोग के इस तरह की हत्याएं जनता को विचलित करती हैं और पुलिस और राज्य को किसी भी तरह की जवाबदेही से बचाती हैं।'

महिला अधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने ट्विटर और फेसबुक दोनों पर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमेंस एसोसिएशन (एआइपीडब्ल्यूए) के बयान को साझा किया, 'हैदराबाद फर्जी मुठभेड़ : हमारे नाम पर हिरासत में हत्याएं न हों।' बयान में कहा गया, 'मुठभेड़ में हिरासत में हत्या के सभी संकेत हैं, इसे एक एनकाउंटर के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है।'

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भले ही मिली-जुली रही हों, लेकिन ज्यादातर ने हैदराबाद पुलिस की कारवाई को सही ठहराया और लोगों को यह सलाह भी दी गई कि वे मुठभेड़ में व्यर्थ के सवाल न खड़े करें। जिन लोगों ने इस मुठभेड़ को सही ठहराया उनमें से ज्यादातर ने यह भी रेखांकित किया कि अपने देश में न्यायिक सिस्टम की रफ्तार बहुत धीमी है।

हैदराबाद का इंसाफ!

> हैदराबाद पुलिस ने सही कदम उठाया है। अब मैं उम्मीद कर सकती हूं कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे लोग अपराधियों को सबक सिखाने के रास्ते निकालेंगे। आपराधिक तत्वों के मन में भय पैदा करना जरूरी है।
> **– साध्वी उमा भारती, भाजपा नेता**

> हैदराबाद पुलिस के इस निर्णय से आज पूरा देश खुशी मना रहा है। देश की महिलाओं में आज एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का उदय हुआ है।
> **–बबीता फोगाट, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान व भाजपा नेता**

दुष्कर्म पीड़ितों के परिवार बोले–सही है मुठभेड़

सदमे में हैं आरोपितों के घरवाले

हैदराबाद, प्रेट्र : पुलिस मुठभेड़ में चारों आरोपितों के मारे जाने से जहां लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं उनके घरवाले गहरे सदमे में हैं। उन्हें ये तो लग रहा था कि उनके बच्चों को सजा मिलेगी, लेकिन इस तरह वो मारे जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी।

मुख्य आरोपित मोहम्मद आरिफ की मां इस खबर के बाद से ही सदमे में है। वह सिर्फ इतना ही कह पा रही है कि उसका बेटा चला गया। उसके पिता ने पहले कहा था कि अगर उनके बेटे ने अपराध किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

आरोपितों में से एक केशवुलू की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी रेनूका गहरे सदमे में है। उसने पत्रकारों से कहा कि उसे भी उसके पति के पास लेकर पुलिस मार डाले। रेनूका ने कहा कि उससे कहा गया था कि उसके पति को कुछ नहीं होगा और वो वापस आ जाएगा।

जोलू शिवा के पिता ने कहा कि हो सकता है कि उनके पुत्र ने अपराध किया हो, लेकिन वो ऐसे अंत का हकदार नहीं था। कई लोग दुष्कर्म और हत्याएं करते हैं, लेकिन वे इस तरह से नहीं मारे जाते। दूसरों को भी इसी तरह से क्यों नहीं मारा जाता। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना था कि गरीब परिवार से संबंध रखने वाले चारों आरोपित अच्छा कमाते थे। लेकिन अपनी कमाई शराब पर उड़ा देते थे। उन्होंने बताया कि आरिफ ट्रक चलाने से पहले एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। लोगों ने बताया कि केशवुलू किडनी की बीमारी से पीड़ित था।

राय ▸ एक स्वर में कहा–हर केस में न्याय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए

कहा–सजा ऐसी हो जिससे सभी को सबक मिले

जेएनएन, नई दिल्ली

हैदराबाद एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां देश में इसके सही और गलत होने की बहस छिड़ गई है। वहीं, जम्मू के कठुआ में दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई आठ साल की बच्ची के माता-पिता ने हैदराबाद में हुई मुठभेड़ पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़िता के परिजनों को कोर्ट में लंबे ट्रायल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा।

पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर ये सभी आरोपी दुष्कर्म में शामिल थे, तो पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिल गया है। उन्होंने जो किया था, उसके लिए उन्हें मौत ही मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सुबूतों के अभाव में कई बार आरोपितों के बरी होने की भी आशंका बनी रहती है।

हैदराबाद एनकाउंटर के बाद निर्भया के गांव में जश्न : हैदराबाद में दुष्कर्म के दोषियों को पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जश्न का माहौल रहा। यह सूचना मिलते ही सात साल पहले दिल्ली में रेप का शिकार हुई पीड़िता के गांव के लोग भी काफी खुश हुए। गांव के लोगों को याद है 16 दिसंबर 2012 का वह काला दिन जब दिल्ली में भी भयानक और घिनौने अपराध को दरिंदों ने अंजाम दिया था। तब भी देश की सभी बेटियां जाग उठी थीं। हलांकि निर्भया के दोषी अब अभी जेल हैं, लेकिन हैदराबाद घटना में शामिल दोषियों के मरने की खबर से सबको सुकून मिला है। अब हमें उम्मीद हैं कि जल्द ही निर्भया के दोषियों को भी फांसी मिलेगी।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच संघर्ष कर रही बेटी के स्वजन हैदराबाद पुलिस के एनकाउंटर से सहमत हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी भी इन्हीं हालात से गुजरी है। उसके गुनहगारों को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा कि ऐसा सबक सिखाने से ही हैवानियत रुकेगी।

मंदसौर की मासूम बोली–काश! ऐसे पुलिस अंकल यहां भी होते

मध्य प्रदेश के मंदसौर की आठ वर्षीय मासूम भी अब कह रही है कि काश! ऐसे पुलिस अंकल यहां भी होते, तो हम चैन की नींद सो पाते। गौरतलब है कि मंदसौर में 26 जून 2018 को एक स्कूल के बाहर से आठ वर्षीय मासूम का अपहरण कर इरफान व आसिफ ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। दोनों दोषियों को 21 अगस्त 2018 को फांसी की सजा सुना दी गई थी, पर करीब डेढ़ साल बाद भी उन्हें सजा नहीं मिल सकी है। दोषियों की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

फिल्मी सितारों ने भी सराहा

नई दिल्ली, एएनआइ : बॉलीवुड के कई सितारों ने भी हैदराबाद पुलिस की सराहना की है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट के जरिये अपनी खुशी व्यक्त की है। खेर ने हैशटैग जयहो और तेलंगनापुलिस के जरिये आरोपितों को मार गिराने वाली हैदराबाद पुलिस को बधाई दी है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बेटीबचाओ हैशटैग से ट्वीट किया कि यह सिर्फ अभियान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर इसे एक्शन में नहीं बदला जाता तो इसका कोई मतलब नहीं है। जाने–माने अभिनेता ऋषि कपूर ने भी तेलंगाना पुलिस की सराहना करते हुए बधाई दी है। अभिनेत्री कंगना रनौत की पहन रंगोली चंदेल ने हैदराबाद पुलिस की सराहना करते हुए लिखा है, 'यह नया भारत है, घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी।'

विश्व मीडिया में भी छाई खबर

▸ **वाशिंगटन पोस्ट से लेकर बीबीसी और द टाइम्स ने प्रमुखता से दी जगह**

वाशिंगटन, प्रेट्र : दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या के आरोपितों को हैदराबाद पुलिस द्वारा मार गिराने की खबर को विश्वभर की मीडिया में भी प्रमुख स्थान मिला। ज्यादातर खबरों में पुलिस कार्रवाई की सराहना की गई, लेकिन कुछ खबरों में इसको लेकर सवाल भी उठाए गए।

दैनिक 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने विस्तृत खबर में लिखा कि भारत में आम लोगों ने चारों आरोपितों के मारे जाने पर खुशी जताई है। लेकिन कार्यकर्ताओं और वकीलों ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए हुए इसे गैर न्यायिक प्रक्रिया बताया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पुलिस ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस आत्मरक्षा की कहानी बताकर बच जाती है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को हाल के दिनों की सबसे गंभीर घटना बताते हुए कहा है कि शुक्रवार की सुबह इस झकझोर देने वाली घटना का स्तब्धकारी अंत हो गया। अखबार आगे लिखता है कि मुठभेड़ को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों को हीरो बताया जा रहा है, उनकी सराहना हो रही है, उन पर फुल बरसाए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर खुशियां मना रहे हैं।

सीएनएन ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या और उसको लेकर देश भर में पनपे आक्रोश के बारे में बताते हुए सीएनएन ने कहा है कि रैलियों में शामिल लोग आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे।

बीबीसी ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर खबर दी है। लोग पुलिस की सराहना करते हुए कह रहे हैं कि न्याय हो गया। निर्भया की घटना का जिक्र करते हुए बीबीसी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर तब बहुत आवाज उठी थी, लेकिन अपराध में कोई कमी नहीं आई।

ब्रिटिश समाचार पत्र 'द गार्जियन' और 'द टेलीग्राफ' ने भी एनकाउंटर को प्रमुखता के साथ जगह दी है। द टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला चिकित्सक के साथ बर्बरात के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। लोगों के गुस्से के चलते आरोपितों को कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा सका था।

किसने क्या कहा

> अब एनकाउंटर क्यों हुआ, क्या परिस्थितयां थी, यह सब तो पुलिस बताएगी, लेकिन जो कुछ भी वर्तमान में देश में हो रहा है, वह अच्छा नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाया जा रहा है। समय रहते हुए केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए।
> **–अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान**

> सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड के चारों आरोपितों का पुलिस एनकाउंटर करना गलत है। किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने का अधिकार नही है। यह न्यायपालिका के अस्तित्व पर चुनौती की तरह है।
> **–ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, बंगाल**

> कोई भी अपराधी अगर भागने की कोशिश करे तो पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं होता है। मुझे लगता है इस मामले में न्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने मुख्य सचिव को महिला सुरक्षा के लिए दो सप्ताह के भीतर इंटीग्रेटेड प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने कहा है।
> **– भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़**

> हैदराबाद में पुलिस ने जो किया है, वैसी कार्रवाई देश भर में होनी चाहिए। मैं नेता से पहले एक मां हूं। बक्सर और समस्तीपुर में महिलाओं को जिंदा जला दिया गया है। इन मामलों में अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। अभी तक मुजफ्फरपुर कांड के आरोपियों को भी सजा नहीं मिल रही है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है।
> **–राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता**

> हैदराबाद केस की पीड़िता के परिवार को न्याय मिला, लेकिन जब तक केंद्र सरकार कठोर कानून नहीं बनाती, कुछ नहीं होगा। निर्भया के दोषी अभी भी सरकारी मेहमान हैं। दोषियों को हर हाल में छह माह में सजा मिलनी चाहिए।
> **स्वाति जयहिंद, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग**

> इसको कानूनी प्राविधान देने पर भी प्रशासन और कानून के क्षेत्र में कार्य करने वालों को विचार करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए ज्यादातर घुसपैठिए ही जिम्मेदार हैं।
> **–कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा**

> हैदराबाद के अंदर दरिंदों को तो पुलिस ने मार गिराया, अब आवश्यकता है उन्नाव के दरिंदों को सजा देने की। इन दरिंदों को भी सरेआम चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए। मानवाधिकार आयोग को हैदराबाद जाना चाहिए और पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए।
> **–साध्वी प्राची**

पुणे की पीड़िता के पति ने हैदराबाद पुलिस को दी बधाई

▸ **दस साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा है महिला का परिवार**

▸ **दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में तीन दरिंदों को हुई है फांसी की सजा**

पुणे, प्रेट्र : हैदराबाद की बेटी की तरह ही लगभग दस साल पहले दरिंदों की शिकार हुई पुणे की पीड़िता के पति ने साइबराबाद पुलिस की एनकाउंटर के लिए सराहना की है।

महिला के पति ने कहा, 'मुझे लगता है कि इससे दुष्कर्मियों को स्पष्ट संदेश जाएगा। मैं हैदराबाद पुलिस को बधाई देना चाहूंगा।' पुणे में सात अक्टूबर, 2009 को आइटी कंपनी में काम करने वाली महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

पुणे की अदालत ने 2017 में इस मामले में तीन आरोपितों योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन तब से ये मामला बांबे हाई कोर्ट में लंबित है।

महिला के पति ने कहा कि अदालत ने सजा सुना दी है। लेकिन इतने वर्ष बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। वह महाराष्ट्र सरकार से प्रक्रिया तेज करने के लिए कहने वाले हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

बता दें कि पीड़िता पुणे के बाहरी इलाके खराड़ी में आइटी कंपनी में काम करती थी। घटना वाले दिन वह घर लौटने के लिए खराड़ी में बस का इंतजार कर रही थी, जहां से उसे अगवा कर लिया गया था। दो दिन बाद पुणे जिले के खेड़ तहसील के जारेवडी के जंगल में उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम से पता चला था कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर महिला की हत्या कर दी गई थी।

एनकाउंटर से खुश होकर पुलिसकर्मियों को एक–एक लीटर पेट्रोल मुफ्त

नईदुनिया, विदिशा : तेलंगाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपितों का एनकाउंटर करने से खुश होकर मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंजबासौदा में एक पेट्रोल पंप संचालक स्थानीय पुलिसकर्मियों को एक–एक लीटर पेट्रोल मुफ्त दे रहा है। इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन शुक्रवार को ही हुआ है। पंप संचालक ने शनिवार को दोपहर दो बजे तक पुलिसकर्मियों को पेट्रोल मुफ्त देने की घोषणा की है। पेट्रोल पंप संचालक रघुवीरसिंह रघुवंशी और ब्रजेश रघुवंशी के मुताबिक, शुक्रवार देर शाम तक 11 पुलिसकर्मियों को 11 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जा चुका था।

कुमार विश्वास बोले–कानून पर भरोसा बढ़ा

जासं, कुरुक्षेत्र : यहां चल रहे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हैदराबाद एनकाउंटर चर्चा में रहा। देश-विदेश से पहुंचे कवियों ने एनकाउंटर को सही ठहराया। कुमार विश्वास ने कहा कि हैदराबाद में चारों अपराधियों को मारना प्रशंसनीय कार्य है। इस घटना से आम आदमी का कानून पर भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सही ढंग से काम करने लगे तो दुष्कर्म के मामलों पर अंकुश लग जाए।

महोत्सव के तहत आयोजित कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज नई परिभाषा, नए तरीके से भगवान श्रीकृष्ण के मार्ग पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज अगर कहीं द्रोपदी चीरहरण होता है तो क्यों नहीं कोई भीम गदा उठाता, क्यों नहीं कोई अर्जुन गांडीव उठाता। कवि गजेंद्र सोलंकी ने भी प्रस्तुति दी।

...तो इन हालात में अपराधी को गोली मार सकती है पुलिस

कई लोगों ने हैदराबाद में हुए पुलिस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों का एनकाउंटर इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने पुलिस पर हमला किया था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि किसी अपराधी को किन परिस्थितियों में पुलिस एनकाउंटर कर सकती है?

विशेष मामले में अलग प्रावधान

उन्होंने कहा, किसी विशेष मामले में मुठभेड़ में मौत का कारण दो स्थितियों में से किसी एक के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उसे सिर्फ जांच से ही सही ठहराया जा सकता है अन्यथा नहीं।

क्या बोले न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचेलैया

29 मार्च, 1997 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में उस समय के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचेलैया ने कहा था कि केवल दो ही परिस्थितियों में पुलिस घातक बल का उपयोग कर सकती है।

पहली स्थिति : आपराधिक मामलों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक अहम एवं जरूरी अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति विशेष को अपना बचाव करने के लिए प्रेरित करता है और यह प्रावधान उसे आवश्यक बल का उपयोग करके अपने हमलावर पर अपनी जीत को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर के बचाव में साइबराबाद पुलिस आयुक्त यही दलील रख रहे हैं। भारत भर में मुठभेड़ों के अधिकांश मामलों में, पुलिस यही दलील देती है।

दूसरी स्थिति : सीआरपीसी की धारा 46 के तहत पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति की मौत के कारणों को सही ठहरा सकते हैं। न्यायमूर्ति वेंकटचैलया ने लिखा, यह प्रावधान पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

आरोपितों की सुरक्षा को लेकर दिनभर आशंकित रही पुलिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने के आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जेल गेट पर पुलिस वाहन से उतरते आरोपित। जागरण

दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा फूंकने की कोशिश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने कड़ी शुक्रवार को शाम पौने छह बजे उन्नाव कोर्ट पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हैदराबाद में डॉक्टर बेटी के गुनहगारों के एनकाउंटर के बाद पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकित थी और सुरक्षित जेल पहुंचाने की कवायद करती रही। आरोपितों को उन्नाव या पुरवा कोर्ट में पेश करने को लेकर भी पूरे दिन पुलिस ने भ्रम बनाए रखा। हैदराबाद मामले के आरोपितों के एनकाउंटर के बाद उन्नाव के इस जघन्य कांड को लेकर लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा था। पांचों आरोपितों के वकीलों व अन्य लोगों की हलचल काफी बढ़ गई थी। इसको लेकर जिला पुलिस एहतियात बरतती रही। कड़ी सुरक्षा के बीच शिवम त्रिवेदी, उसके पिता रामकिशोर, शुभम त्रिवेदी, उसके पिता हरिशंकर त्रिवेदी (प्रधान पति) और उमेश बाजपेई (पंचायत मित्र) को बिहार थाने से सुबह ले जाकर सुमेरपुर सीएचसी में मेडिकल परीक्षण कराया और वापस थाने लाई। इसके बाद पुलिस आरोपितों को कोर्ट में हाजिर कराने को लेकर बेहद चौकन्ना रही। वकीलों, मीडिया व आम लोगों को गुमराह करने के लिए पुरवा कोर्ट में पेश करने की बात बताई गई। 5 बजे कोर्ट बंद होने का समय होने के चलते वकील और अन्य लोग जाने लगे। उधर, पुरवा कोर्ट को समय पूरा होने के बाद भी खोले रखा गया। उन्नाव में भी कोर्ट देर तक खुला रहा। पुलिस शाम को कैदी वाहन से आरोपितों को कोर्ट लाई और पेशी कराकर जेल पहुंचा दिया गया।

पीड़िता के चाचा को धमकियां : मुख्य आरोपित शिवम त्रिवेदी ने पीड़िता के चाचा को जान से मारने की धमकी दी थी। यह बात जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अधिकारी हरकत में आ गए। पीड़िता के चाचा को बुलाकर डीएम-एसपी ने बात की हालांकि बाद में डीएम ने कहा कि धमकी जैसी कोई बात नहीं थी, आरोपित के एक रिश्तेदार को चाचा के साथ मध्यस्थता का रास्ता निकालने को कहा था। शुक्रवार को बात होनी थी, लेकिन उससे पहले घटना हो गई।

तीन और आरोपितों के नाम भी मुकदमे में शामिल : पीड़िता के भाई की तहरीर को आधार बनाकर बिहार थाना पुलिस ने शिवम और शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि पीड़िता ने मजिस्ट्रेटी बयान में एसडीएम, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को इन दोनों के अलावा शिवम के पिता रामकिशोर, शुभम के पिता हरिशंकर त्रिवेदी (प्रधान के पति), उमेश बाजपेई (पंचायत मित्र) के नाम बताए थे। इस पर विवेचना में उनके नाम भी बढ़ा दिए गए।

लालगंज पुलिस सतर्क होती तो बच सकती थी वारदात

रायबरेली : लालगंज पुलिस चेत जाती तो पीड़िता दरिंदगी से बच सकती थी। पीड़िता ने 2018 में थाने में शिकायत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने उन्नाव के बिहार थाना में चार मार्च 2019 को गुहार लगाई। बिहार पुलिस ने शिवम और शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो लालगंज पुलिस ने भी कोर्ट के आदेश पर अगले दिन ही 5 मार्च 2019 को दोनों आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज की। शिवम जेल गया और हाई कोर्ट से जमानत पर छूट गया, लेकिन लालगंज पुलिस ने उसके बारे में पता करना मुनासिब नहीं समझा और छूटकर आए शिवम ने साथियों संग वारदात को अंजाम दे दिया।

उन्नाव में अब तीन साल की मासूम से दरिंदगी

जागरण संवाददाता, उन्नाव

उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश के 28 घंटे बाद ही तीन साल की मासूम से दरिंदगी की गई। बच्ची के रोने-चीखने पर गांव के ही किशोर के दबोचकर घरवालों ने पुलिस के हवाले किया। बच्ची के पिता ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। किशोर न्याय बोर्ड ने 16 वर्षीय आरोपित को सुधारगृह भेजा है।

जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर माखी क्षेत्र के एक गांव में यह घटना शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे हुई। घरवाले घरेलू काम में व्यस्त थे। बच्ची के चाचा का घर सड़क पार खेत के पास है। वह वहीं जा रही थी। इस बीच, आरोपित पहुंचा और सड़क से बच्ची को गोद में ले लिया। करीब 100 मीटर दूर बच्ची को सरसों के खेत में ले गया और दरिंदगी की कोशिश की। बच्ची के रोने की गूंज घर में मौजूद चाचा के कान में पड़ी तो वह दौड़े। बचकर भागने की कोशिश कर रहे आरोपित को उन्होंने दबोच लिया। इस बीच, गांव वाले भी आ गए और आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित पड़ोस के गांव में अपने मामा के घर रह रहा था।

एसपी विक्रांतवीर ने बताया कि बच्ची के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट लिखी गई है। आरोपित को किशोर सुधार गृह भेजा गया है। बच्ची का जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया है। इसमें प्राइवेट पार्ट पर इंजरी नहीं मिली है।

छात्रा लापता नहीं लिखी रिपोर्ट

उन्नाव : देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गुस्सा भड़कने के बावजूद उन्नाव पुलिस ने दो दिन से लापता स्कूली छात्रा की गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की है। पिता ने तहरीर में अपहरण की आशंका जताई है जो जांच की टोकरी में ही पड़ी है। उन्नाव निवासी किशोरी पड़ोसी गांव स्थित स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा है। 4 दिसंबर को स्कूल के लिए निकली छात्रा दोपहर तक घर नहीं लौटी तो घरवाले स्कूल पहुंचे। पता लगा कि वह स्कूल नहीं पहुंची। नाते रिश्तेदारी में खोजने पर निराशा मिलने के बाद 5 दिसंबर को पिता ने तहरीर दी। कुछ मोबाइल फोन नंबर पुलिस को दिए, जिनसे किशोरी बात करती थी। पर, तीन दिन बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि किशोरी को खोज रहे हैं। जांच के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे।

केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्यों को लिखा पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यों को पत्र लिखते हुए उन्हें हरसंभव कदम उठाने के लिए कहा है। उसने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मामले में केंद्र सरकार कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी।

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वह हाल ही में महिलाओं एवं लड़कियों के साथ हुई यौन उत्पीड़न की जघन्य व दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर यह पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला विषय है। सरकार ने ऐसे अपराधों से सख्ती के साथ निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने वाले कदम उठाए हैं। प्रभावी प्रतिरोध के लिए यह जरूरी है कि लोग पुलिस तक आसानी से पहुंच सकें। पुलिस महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करे।' गृह सचिव ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में राज्यों को पूर्व में भेजे गए परामर्श का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है अगर कहीं कोई कोताही हुई तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

निर्भया के दोषियों पर 24 घंटे नजर रख रहा है जेल प्रशासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले के एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन इस मामले से जुड़े सभी दोषियों पर 24 घंटे नजर रख रहा है। इस मामले में अक्षय, मुकेश, विनय शर्मा और पवन को मौत की सजा मिली हुई है। अक्षय व मुकेश तिहाड़ के जेल नंबर दो में बंद हैं तो विनय शर्मा जेल नंबर चार में बंद है।

जेल सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को अक्षय और मुकेश की दिनचर्या अन्य दिनों की तरह ही रही, लेकिन वे किसी से बात करते नहीं देखे गए। इन दोनों ने किसी भी कार्य में भाग नहीं लिया। इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक जवान सेल के बाहर तैनात है। जेल नंबर चार में बंद विनय शर्मा पर भी जेल प्रशासन पूरी नजर रख रहा है। विनय शर्मा से मिलने के लिए जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को गए थे और उससे बातचीत की थी। विनय शर्मा पर नजर रखने के लिए एक वार्डर के साथ एक जवान को भी तैनात किया गया है। पवन मंडोली के जेल नंबर-14 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है।

इस बीच, निर्भया के माता-पिता ने राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा है कि यह दया याचिका न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने और मौत की सजा में देरी करने के लिए डाली गई है। उन्होंने लिखा है कि घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है और न्याय का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी दोषियों को जल्द फांसी की सजा दी जाए।

एनकाउंटर पर खुशी जताई

हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म के चारों आरोपितों का पुलिस की ओर से एनकाउंटर करने पर निर्भया के माता–पिता ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर ये चारों आरोपित भागने में सफल हो जाते तो सभी पुलिस से यही सवाल पूछते कि ये पुलिस हिरासत से भागने में कैसे कामयाब हो गए। ऐसे में एनकाउंटर के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सात वर्ष से न्याय के लिए इंतजार कर रही हूं। मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूं जिस पीड़ा से हैदराबाद में पीड़िता के माता–पिता गुजर रहे होंगे। उन्हें न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा।

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले लॉ छात्रा के मामले को नहीं लटकने देंगे

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ **लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई**

▸ **हेल्पलाइन नंबर सही से काम नहीं करने पर कोर्ट नाराज**

राजधानी रांची में लॉ छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने डोरंडा दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि इस मामले में वह खुद पल-पल का अपडेट ले रहे हैं। किसी भी हाल में मामले को लटकने नहीं दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने कहा कि इस मामले का डोरंडा जैसा हाल नहीं होने देंगे। पुलिस ने भी सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया कि जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी। घटना के बाद डीजीपी और रांची के एसएसपी ने उस इलाके में पुलिस की गश्ती बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन कुछ दिनों पहले गोलीबारी की घटना होना सवाल खड़े करती है।

डायल 100 पर रात दस बजे नहीं मिलता रिस्पांस : डायल 100 और महिला हेल्पलाइन (शक्ति एप) नंबर के तरीके से काम नहीं करने पर भी हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। लॉ छात्रा मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 100 नंबर डायल कर देखा जाए कि रिस्पांस आता है या नहीं। सुबह दस बजे तो कॉल करने पर रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन रात दस बजे के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसी तरह, महिला हेल्पलाइन भी काम नहीं कर रहा है।

हालांकि, सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति एप के जरिए शिकायत करने की व्यवस्था की है, लेकिन यह अभी कितना काम कर रहा है, इसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। इस पर अदालत ने कहा कि डायल 100 या फिर शक्ति एप को फूल प्रूफ बनाना होगा। अदालत ने महिला सुरक्षा के लिए प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, एनएच और स्टेट एनएच पर सीसीटीवी कैमरे अन्य उपायों पर सरकार से जानकारी मांगी है। इसके अलावा, सीआइडी के आइजी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

डॉ. रवि रंजन। फाइल

सरकार स्ट्रीट लाइट के लिए मांगती है पैसे, कोताही बर्दाश्त नहीं

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने कहा कि नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के पास की सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा इलाका अंधेरा में डूबा रहता है। जब संस्थान की ओर से सरकार के पास आवेदन भेजा जाता है, तो सरकार इसके बदले में संस्थान से पैसे की मांग करती है। अदालत ने कहा कि अगर कोई संस्थान के विकास में बाधक बनता है, तो कोर्ट उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कदम उठाएगी।

बिहार समेत देशभर में पोर्न साइट पर लगे रोक : नीतीश

कीर्ति पांडेय, गोपालगंज

▸ **प्रतिबंध के लिए लिखेंगे केंद्र को पत्र, हैदराबाद की घटना पर जताई चिंता**

▸ **कहा– सोशल साइट का कुछ लोग कर रहे हैं दुरुपयोग**

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि हमने तय किया है कि पोर्न साइट पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। लड़कियों के साथ गलत काम कर उनके वीडियो और तस्वीरों को पोर्न साइट पर पोस्ट किया जाता है। इसका असर युवाओं पर पड़ रहा है। इसलिए बिहार सहित पूरे देश में पोर्न साइट पर रोक लगाई जाए। हम एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें।

शुक्रवार को जल जीवन हरियाली मिशन यात्रा पर गोपालगंज के बरौली प्रखंड के देवापुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने 245.85 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने सवाल किया कि हैदराबाद जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, सहित तमाम राज्यों में आखिर क्यों हो रही हैं। यह बहुत खराब स्थिति है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लोग इसका अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं और तकनीक का लाभ उठा रहे हैं, पर कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देश का नाम खराब करने का काम हो रहा है, जिसका असर सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें जन जागरूकता की जरूरत है, इसमें मीडिया की भूमिका अहम है। अभियान चलाकर रिटायर्ड जज, शिक्षक और दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग से राय लेनी चाहिए, एक मजबूत संदेश दिया जाए ताकि देश का नाम और ऊंचा हो सके। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत नई जागृति लाने काम करेगी।

नीतीश कुमार। फाइल

377 जेंटलमैन कैडेट शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद देश-विदेश की सेना का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें 306 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थलसेना को मिलेंगे, जबकि 71 युवा सैन्य अधिकारी दस मित्र देशों की सेना का हिस्सा बनेंगे।

सेना शिक्षा कोर के गेट से फर्जी सैन्य अफसर ले गए दो राइफल

सुरक्षा में चूक ▶ मध्य प्रदेश में अलर्ट, होशंगाबाद की सीमाएं सील

सेना के किसी अधिकारी ने नहीं दिया बयान

नईदुनिया, होशंगाबाद

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर के गेट (बाहरी दरवाजा) से गुरुवार रात करीब तीन बजे दो युवक दो इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 20 कारतूस ले भागे। संदिग्ध युवक फर्जी सैन्य अधिकारी बनकर आए थे। मामला उजागर होते ही जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट है। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। हालांकि, सेना के किसी अधिकारी ने इस मामले में बयान नहीं दिया है।

पुलिस के अनुसार सेना शिक्षा कोर के शहीद दीपक स्मारक गेट पर रात करीब तीन बजे दो युवक पहुंचे। वहां तैनात जवान को उन्होंने अपना परिचय सेना के अधिकारी के रूप में दिया। जवान अपनी राइफल वहीं छोड़कर बगल में केबिन में लगे फोन से वरिष्ठ अधिकारियों से पुष्टि करने लगा, तभी वह गेट के पास रखी दो इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 20 कारतूस लेकर कुछ दूर खड़ी टैक्सी से भाग गए। केबिन से लौटकर जवान ने दोनों युवकों और हथियारों को लापता पाया। तब उसने वरिष्ठ अफसरों को जानकारी दी। सेना ने अपने स्तर पर उन्हें तलाश करने के बाद तड़के करीब चार बजे एसपी एमएल छारी को सूचना दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले की सीमाओं को सील कर तलाशी अभियान चलाया गया है। हालांकि, आरोपितों का पता नहीं चला।

टैक्सी से आए थे युवक : एसपी छारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों युवकों ने रात करीब दो बजे पिपरिया से टैक्सी ली और पचमढ़ी पहुंचे। संबंधित टैक्सी चालक ने पुलिस को बताया कि दोनों युवकों की कद-काठी सेना के अफसरों जैसी ही थी। वे ट्रैक सूट और कैप पहने थे। पंजाबी में बात कर रहे थे। पचमढ़ी जाते समय दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन लौटते समय क्रिकेट का बैट रखने वाले बैग में कुछ सामान था। उसने दोनों को जब पिपरिया स्टेशन पर छोड़ा, तब हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर जाने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस आने वाली थी। आशंका है कि वे इसी ट्रेन से जबलपुर की तरफ चले गए।

छारी ने बताया कि सेना से संबंधित रेजीमेंटल पुलिस के हवलदार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ पचमढ़ी थाने में चोरी का केस दर्ज किया है।

पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर का गेट। नईदुनिया

कड़ी सुरक्षा वाला है इलाका

पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है। आधिकारिक अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों संदिग्ध कोर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके थे। वे गेट पर जवान द्वारा छोड़ी गई राइफलें लेकर भागे हैं।

पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल और जबलपुर के रेलवे एसपी सहित सेंट्रल कंट्रोल रूम को भी सूचित कर दिया गया है। हर तरफ तलाश की जा रही है।
– आशुतोष राय, आइजी, होशंगाबाद

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को दी टीटीजेड में पर्यावरण मंजूरी देने की अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य अधिकारियों को ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) में पेयजल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज सिस्टम जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरियां प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

पिछले साल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरियां देने के संबंध में तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था जब तक उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल और उसके आसपास पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए विजन दस्तावेज दाखिल नहीं कर देती। टीटीजेड 10,400 वर्ग किमी का ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फीरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान के भरतपुर तक फैला हुआ है। शीर्ष अदालत पर्यावरणविद एमसी मेहता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें ताजमहल और उसके आसपास पर्यावरण के संरक्षण की मांग की गई है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस तथ्य पर संज्ञान लेते हुए अपने पूर्व में दिए आदेश में संशोधन कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन दस्तावेज दाखिल कर निर्देशों का पालन किया है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि अब सरकार और अन्य अधिकारियों को पर्यावरण मंजूरियां प्रदान करने की अनुमति दे दी जाएं।

छत्तीसगढ़ में एफआइआर से इन्कार पर थाने में आदिवासियों ने दिया धरना

अनिल मिश्रा, रायपुर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित सारकेगुड़ा नरसंहार मामले में शुक्रवार को बासागुड़ा थाने पहुंचे आदिवासियों की शिकायत पर पुलिस ने जिम्मेदारों पर एफआइआर दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इससे भड़के आदिवासी थाने में ही धरने पर बैठ गए। हालात को संभालने के लिए थाना प्रभारी ने दो टूक कह दिया कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, एफआइआर दर्ज नहीं होगी। यह बात आदिवासियों को नागवार गुजरी।

गौरतलब है कि 28 जून 2012 को बीजापुर व बासागुड़ा से निकले कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ जवानों ने सारकेगुड़ा गांव में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं थीं, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इसमें आठ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण मुठभेड़ को फर्जी बताकर इसकी जांच की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने मुद्दे को आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की जा चुकी है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार सुबह नौ बजे से ही कोट्टागुड़ा, राजपेंटा और सारकेगुड़ा के ग्रामीण एकत्र हुए। दोपहर करीब एक बजे चार किमी दूर स्थित बासागुड़ा थाने के लिए कूच किया। करीब 60 ग्रामीण थाने पहुंचे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। दिल्ली से आए मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार भी आदिवासियों के साथ थाने पहुंचे। सारकेगुड़ा मामले में जिम्मेदारों पर एफआइआर दर्ज करने को लेकर उनकी एसडीओपी विनोद मिंज से तीखी बहस भी हुई। मिंज ने कहा कि वे आवेदन जरूर लेंगे, लेकिन एफआइआर तभी दर्ज करेंगे, जब ऊपर से दिशानिर्देश मिलेगा। यही से बात बिगड़ी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। समाचार के लिखे जाने तक आदिवासी थाने में ही डटे हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक एफआइआर दर्ज नहीं होगी, वे नहीं हटेंगे।

रमन सिंह बोले-आयोग की अनुशंसा पर करें कार्रवाई : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ बासागुड़ा थाने में शिकायत की गई है, इस पर डॉ. रमन ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यायिक जांच आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला 2012 का है। तब सरकार में रहते हुए हमने ही न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ गई है। अब सरकार को आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। सारकेगुड़ा फर्जी मुठभेड़ मामले में डॉ. रमन सिंह, मुकेश गुप्ता, तत्कालीन बस्तर आइजी लांगकुमेर, एसपी प्रशांत अग्रवाल, थाना प्रभारी इब्राहिम खान और कोबरा जवानों के खिलाफ के पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने बासागुड़ा थाने में शिकायत पत्र दिया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला स्थित बासागुड़ा थाने में धरना देते समय सूत कातते मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु। उनके पीछे सफेद टीशर्ट में सारेगुड़ा गांव निवासी इरपा महेश, नीली शर्ट में सेंटी काका, शांता मरकाम, इरपा जानकी। (नईदुनिया)

भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्तिदेवी पुरस्कार डॉ. विश्वनाथ तिवारी को

नई दिल्ली, वि : 2019 का 33वां मूर्तिदेवी पुरस्कार हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और आलोचक डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। यह भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से दिया जाना वाला पुरस्कार है। मूर्तिदेवी पुरस्कार उन्हें उनकी कृति 'अस्ति व भवति' के लिए दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत डॉ. तिवारी को सरस्वती प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और चार लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 20 नवंबर 1940 को जन्मे डॉ. तिवारी लंबे समय तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वह साहित्यिक पत्रिका 'दस्तावेज' के संपादक हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके तिवारी को महापंडित राहुल सांस्कृत्यान पुरस्कार व्यास सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, पूश्किन सम्मान मिल चुका है।

डॉ. विश्वनाथ तिवारी। फाइल

'भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। संज्ञेय अपराध के संबंध में औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी प्रकार की सूचना मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त होगी। किसी भी मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव व हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस मामले में 24 दिसंबर 2018 को हैदराबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया था, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी।

तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई तय प्रारूप या शैली नहीं है, जिसके तहत प्रारंभिक जांच कराई जाए। मामला दर्ज करने से पहले जांच जरूरी है या नहीं, यह प्रत्येक मुकदमे की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा, 'इसलिए, हम मानते हैं कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में प्रारंभिक जांच का फैसला (2014) भ्रष्टाचार के सभी मामलों के लिए अनिवार्य नहीं है।' पीठ ने कहा, 'कोर्ट कई बार कह चुका है कि किसी भी मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत तथ्यों और महत्व पर निर्भर करेगी। ऐसा कोई मानक नहीं कि किस मामले में इस प्रकार की जांच के लिए कहा जाया और किसमें नहीं, इसलिए संज्ञेय अपराध के बारे में मिली किसी भी प्रकार की सूचना से अगर अधिकारी संतुष्ट है तो रिपोर्ट दर्ज कर सकता है।'

शीर्ष अदालत ने अधिकारी के तर्क को खारिज कर दिया कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भ्रष्टाचार के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी है। उसने कहा कि वर्ष 2014 में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया था।

अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए छह नई याचिकाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को छह नई याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें पांच मौलाना मुफ्ती हसबुल्लाह, मुहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी नहबूब तथा मिशबाहुद्दीन की तरफ से दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) का समर्थन प्राप्त है। छठी याचिका मुहम्मद अयूब की तरफ से दाखिल की गई है।

वकील एमआर शमशाद के माध्यम से दाखिल की गईं पांचों याचिकाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और जफरयाब जिलानी ने अंतिम रूप दिया है। हालांकि, अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे धवन ने तीन दिसंबर को फेसबुक पोस्ट में कहा था कि उन्हें आगे की सुनवाई से अलग कर दिया गया है, इसलिए पुनर्विचार याचिका में उनकी भूमिका नहीं होगी। बाद में धवन ने कहा था कि वह मुस्लिम पक्ष को बांटना नहीं चाहते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उम्मीद जताई थी कि आगे की सुनवाई में धवन मुस्लिम पक्ष की बात रखेंगे।

एक पुनर्विचार याचिका के अनुसार, 'हमारा उद्देश्य महान देश की शांति को भंग करना नहीं है, लेकिन कोई भी शांति न्याय के अनुकूल होनी चाहिए। यह याचिका न्याय की मांग के लिए है।'

हसबुल्लाह ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि जमीन के मालिकाना हक के इस विवाद में उनके समुदाय के साथ 'घोर अन्याय' हुआ है और कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पूरी विवादित जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्षकारों को इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि वह पूरी तरह उनके कब्जे थी। जमीन किसी भी अवसर पर हिंदुओं के पास नहीं थी। यह भी एक स्वीकार्य तथ्य है कि दिसंबर 1949 तक मुसलमान इस स्थान पर नमाज पढ़ते थे। याचिका में कहा गया है कि नौ नवंबर के फैसले में कानून का उल्लंघन करने वालों और मस्जिद को ढहाने वालों को माफ कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद-142 के अंतर्गत सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश देना भी गलत है, क्योंकि इस मामले में कभी ऐसी मांग की ही नहीं गई।

इसके पहले दो दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष तथा अयोध्या मामले में मूल पक्षकार रहे ए. सिद्दिक के वारिस मौलाना सैयद अशद रशीदी ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश दिए जाने से ही इस मामले में 'पूर्ण न्याय' होगा। उन्होंने फैसले के 14 बिंदुओं पर पुनर्विचार की अर्जी लगाई है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने नौ नवंबर को सर्वसम्मति से दिए ऐतिहासिक फैसले में पूरी विवादित जमीन (2.77 एकड़) रामलला को तथा अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख जगह पर पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इन्कार कर दिया था।

▶ **पांच याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन**

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

27 दिन पहले के फैसले से छटी 27 वर्ष की धुंध

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

27 वर्षों से जो तारीख शौर्य और गम की चादर में लिपटी रही। 27 वर्ष पहले (6 दिसंबर 1992) घटे घटनाक्रम के बाद जो गली संगीनों के सख्त साये में रही। जो भूमि चार सदी से ज्यादा वक्त से अपने सीने पर विवाद ढोती रही, वह इस 6 दिसंबर को ठीक 27 दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मानों स्वयं के बेदाग होने की मुनादी कर रही थी। 27 वर्ष पहले के 6 दिसंबर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के 6 दिसंबर का यह फर्क रामलला की ओर जाने वाली गली में कदम रखते ही महसूस होता है, तब जब आप निर्विवादित भूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन की कामना से पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पहली 6 दिसंबर को रामलला का दर्शन करने वालों की संख्या भी हजारों में रही। प्रथम व द्वितीय पाली में कुल मिला कर 6,244 दर्शनार्थियों ने रामलला के दर्शन किए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली 6 दिसंबर को रामजन्मभूमि की ओर जाने वाली गली में हिंदुस्तान की सांस्कृतिक, वेश-भूषागत और भाषाई विविधता के भी दर्शन होते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू, बिहार और देश के अलग-अलग राज्यों के लोग कदम-कदम पर नजर आते हैं। दशरथ महल से आगे बढ़ने पर यज्ञशाला मंदिर के बाद संत प्रयागराज मिलते हैं, लोगों से रामकोट की विशिष्टता साझा करते हुए...। दशरथ महल, रामजन्मभूमि व रामकोट के अन्य मंदिरों का समीकरण सुन श्रद्धालुओं के रोमांच में भरा होने का भाव उनके चेहरे से स्वतः झलक उठता है। वहीं से रामलला की ओर निहारते बिहार के छपरा से आए सुधीर सिन्हा कहते हैं हम पहले भी अयोध्या आए हैं, पर 6 दिसंबर को नहीं। रामजन्मभूमि के आग्नेयकोण पर विराजमान बजरंगबली का दर्शन कर रामलला की ओर बढ़ते गुजरात के अहमदाबाद से आए हरीश मेहता कहते हैं कि हमने 6 दिसंबर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इसीलिए जब फैसला आया, तभी तय किया कि इस साल रामलला का दर्शन 6 दिसंबर को ही करेंगे।

अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने जाते श्रद्धालु। जागरण

निर्मूल साबित हुई आशंकाएं

6 दिसंबर को लेकर सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। रामनगरी में पहरा कड़ा रहा, लेकिन जनजीवन पर इसका असर कम दिखा। अयोध्या में बाजार ग्राहकों से गुलजार रहीं। टेंपो-टैक्सी का संचालन भी सामान्य रहा। सुबह लोगों को पहचान पत्र देखने के बाद नगरी में प्रवेश दिया गया, लेकिन दोपहर बाद इसमें भी रियायत दे दी गई। रामकोट सहित संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो रामनगरी के अधिकतर इलाकों में पाबंदियों का असर नहीं दिखा। रामनगरी की आम जनता व्यवस्थाओं में पुलिस का सहयोग करती दिखी। अधिगृहीत परिसर की ओर जाने वाले मार्ग कड़ी निगरानी में रहा। पहचान पत्र देखकर ही वाहन चालकों को प्रवेश दिया गया। रामकोट की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरियर रहे। डीएम अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी दिनभर रामनगरी में भ्रमणशील रहे। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त ड्रोन की भी मदद ली गई। 6 दिसंबर के साथ जुमा की नमाज को लेकर भी प्रशासन और पुलिस काफी सतर्क रहे।

उत्तराखंड में मंत्री खुद भरेंगे आयकर, विधेयक पारित

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में अब मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। सदन में प्रस्तुत उत्तराखंड मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध)(संशोधन) विधेयक शुक्रवार को पारित कर दिया गया।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय सभी मंत्रियों का आयकर सरकार द्वारा चुकाए जाने की व्यवस्था आरंभ की गई थी। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अब तक, यानी पिछले 38 वर्षों से यह व्यवस्था यथावत चल रही थी। इस व्यवस्था की अप्रासंगिकता का मामला दैनिक जागरण ने गत 14 सितंबर के अंक में उठाया था। इसके बाद सरकार ने मंत्रियों का आयकर सरकार द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया।

बीते वर्ष सरकार ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध (संशोधन) विधेयक पारित कर विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की थी। सरकार ने मंत्रियों का वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार किया गया और मंत्री के रूप में मिलने वाले उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए। अलग-अलग मदों में मिलने वाले भत्ते 42 हजार से बढ़ाकर 84 हजार, 36 हजार रुपये से बढ़ाकर 72 हजार और 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किए गए।

रेलवे ने जबरन रिटायर किए 32 अफसर, कई पर लटकी तलवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **रिटायर किए जाने वालों में सीनियर ग्रेड के डायरेक्टर और उससे ऊपर रैंक के 22 अफसर शामिल हैं**

▶ **कुल 1780 अफसरों व कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को कमतर पाया गया**

खराब प्रदर्शन एवं कदाचार के आरोप में रेलवे बोर्ड ने अपने 32 अफसरों व कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। निकट भविष्य में रेलवे के कई अन्य अकुशल अथवा भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी संभव है।

जबरन रिटायर किए जाने वालों में सीनियर ग्रेड के डायरेक्टर तथा उससे ऊपर रैंक के 22 अफसर शामिल हैं। बाकी दस अफसरों व कर्मचारियों का संबंध रेलवे सचिवालय सेवा व रेलवे स्टेनोग्राफर सेवा से है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों के अनुसार, सरकार को रेलवे में असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन, अकुशलता अथवा कदाचार के आधार पर डायरेक्टर रैंक से ऊपर के अफसरों को 50 वर्ष की सेवा के बाद, जबकि उससे नीचे रैंक के अफसरों व कर्मचारियों को 55 वर्ष की सेवा के बाद जबरन रिटायर करने का अधिकार है।

रेलवे बोर्ड के अलावा जोनों में भी अकर्मण्य व भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एवं नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अफसर तथा उससे नीचे के कर्मचारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, यह कवायद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के तहत की जा रही है। विभाग ने सभी मंत्रालयों से अकुशल व भ्रष्ट अफसरों व कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सीनियर तथा उससे ऊपर के ग्रेड के 1410 अफसरों के कार्य प्रदर्शन को कमतर पाया। इनमें सबसे खराब प्रदर्शन वाले 22 अफसरों को समय से पहले रिटायर करने का फैसला किया गया। इसके अलावा इससे निचले ग्रेड तथा ग्रुप सी व डी के 370 अफसरों व कर्मचारियों की पहचान कर उनमें से 10 को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में भी रेलवे के चार अफसर समय से पहले रिटायर किए गए थे। उस समय 1824 अफसरों की समीक्षा की गई थी।

सांध्य दैनिक संचालक जीतू पर वेश्यावृत्ति का भी मुकदमा दर्ज

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी और लूट मामले में फरार सांध्य दैनिक संचालक जीतू (जितेंद्र) सोनी पर शुक्रवार को वेश्यावृत्ति में लिप्त होने और शिकायत करने वाली पीड़िताओं को धमकाने को लेकर भी केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने जीतू पर इनाम राशि 30 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा है।

एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र के मुताबिक, जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी और उसके बेटों अमित व विक्की सोनी, भतीजे लक्की, जिग्नेश, निखिल और भाई हुकुम सोनी पर 13 केस दर्ज हो चुके हैं। गुजरात, मुंबई सहित कई शहरों में तलाशने के बाद भी जीतू की जानकारी नहीं मिली है। उधर, एक युवती की शिकायत पर जीतू सोनी, राव साहब (अकाउंटेंट) और हुकुम सोनी (भाई) के खिलाफ गवाही और बयान देने पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया गया है। मूलतः कोलकाता निवासी युवती को पुलिस ने होटल माय होम से मुक्त कराया था। पुलिस ने शिकायत के लिए तीन सेल का गठन भी किया है। उधर, आयकर विभाग ने भी जीतू सोनी की संपत्ति का ब्योरा पुलिस से मांगा है।

अमित नौ तक रिमांड पर : सांध्य दैनिक अखबार 'संझा लोकस्वामी' के कर्ताधर्ता व जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी और होटल माय होम के मैनेजर जे. वर प्रसाद राव को जिला कोर्ट ने नौ दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पलासिया थाना पुलिस ने अमित सोनी और जे. वर प्रसाद राव के खिलाफ मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया है। चार दिन पहले पुलिस ने उन्हें जिला कोर्ट में पेश कर शुक्रवार तक रिमांड पर लिया था। शुक्रवार दोपहर रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था।

महिलाओं पर लुटाए रुपये इकट्ठा करते थे 'पति' : माय होम होटल से बरामद महिलाओं को उनके पतियों को सौंपने के संबंध में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पतियों की तरफ से दायर याचिका में एसएसपी द्वारा पेश शपथ-पत्र में कहा गया है कि महिलाएं डांस करती थीं और खुद को पति बताने वाले युवक ग्राहकों द्वारा महिलाओं पर लुटाए गए रुपये इकट्ठा करते थे। ये युवक तो खुद मानव तस्करी के मामले में लिप्त हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह शनिवार रात पुलिस ने माय होम होटल से 67 महिलाओं और युवतियों को बरामद किया था।

हर छात्रवृत्ति में 40 फीसद का हिस्सेदार था दलाल

जागरण संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड में हुए करीब पांच सौ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में 4.31 करोड़ रुपये डकारने वाले संस्थान एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने बाकायदा दलाल पाल रखे थे। दुस्साहस यह कि संस्थान ने दलाल से लिखित में समझौता भी कर रखा था। इसके अनुसार दलाल जितने भी दाखिले कराएगा, उसके नाम पर निकलने वाली छात्रवृत्ति में से 40 फीसदी हिस्सा उसे दिया जाएगा। बाकी रकम पर संस्थान का हक होगा। विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच में पाया गया कि दलाल को संस्थान ने इस समझौते के तहत करीब 26 लाख रुपये चेक के जरिये दिए।

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर गठित एसआइटी ने एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 4.31 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा है। संस्थान में यह घपला शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2015-16 के मध्य का है। फरवरी में प्रेमनगर थाने में इस आशय का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना में अभी तक संस्था के संयुक्त सचिव मानवेंद्र स्वरूप और एक दलाल राकेश तोमर की मिलीभगत के साक्ष्य मिले हैं। मानवेंद्र उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित दयानंद शिक्षण संस्थान के सचिव भी हैं। उन्हें बुधवार को कानपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि राकेश तोमर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना के दौरान एसआइटी को एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और राकेश तोमर के बीच किया गए समझौते के दस्तावेज भी मिले। इसमें उल्लेख है कि राकेश तोमर संस्थान को अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। वहीं, छात्रों का प्रवेश कराएगा और छात्रों के बैंक में खाता भी खुलवाएगा। इस आधार पर एसआइटी ने जब संस्थान से लेकर राकेश तोमर के बैंक खातों की डिटेल खंगाली तो पता चला कि संस्थान ने उसे चेक के जरिए 26 लाख 13 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

▶ **एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने दलाल राकेश तोमर से कर रखा था लिखित समझौता**

▶ **दलाली के करीब 26 लाख रुपये का भुगतान संस्थान ने चेक के जरिये किया**

संस्थान और राकेश तोमर के बीच हुआ समझौतानामा सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ। जांच के बाद भी सामने आया कि किस तरह संस्थान संगठित गिरोह के रूप में गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प रहा था।
–संजय गुंज्याल, आइजी एसआइटी

राकेश ने भी बना रखे थे एजेंट

जांच में यह भी सामने आया है कि संस्थान के पास राकेश के अलावा और भी कई दलाल हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का दाखिला कराते थे। राकेश खुद तो गांवों में जाकर लोगों से संपर्क करता ही था, इसके अलावा उसने कई युवकों को जोड़ रखा था।

समाज कल्याण विभाग के दो जेडी भी हो चुके हैं गिरफ्तार

घोटाले में मानवेंद्र स्वरूप के रूप में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग के दो संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल व अनुराग शंखधर को एसआइटी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

बीएचयू के वर्तमान व पूर्व कुलपति अवमानना के दोषी करार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ **छह हफ्ते में कारण बताने का निर्देश दिया कि क्यों न उन्हें अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए**

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी के वर्तमान व पूर्व कुलपति, दो पूर्व कुलसचिव व दो पूर्व उप कुलसचिव को प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया है। सभी से छह हफ्ते में कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उन्हें अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए। सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने डा. संदीप कुमार, अभिषेक चन्द्रा व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने बीएचयू के कुलसचिव को निर्देश दिया है कि अवमानना के आरोपित वर्तमान कुलपति राकेश भटनागर व पूर्व कुलपति डॉ लालजी सिंह (दिवंगत), पूर्व कुलसचिव डॉ जीएस यादव व डॉ नीरज त्रिपाठी तथा पूर्व उप कुलसचिव भर्ती सेल डॉ अश्वनी कुमार सिंह व डॉ सुनीता चंद्रा पर आरोप तामील करें।

मालूम हो कि बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आर्थोपेडिक और एनाटॉमी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन को इस आधार पर चैलेंज किया गया कि विज्ञापन में जोड़ी गई अतिरिक्त अहर्ता मानक के अनुरूप नहीं है। बताया गया कि नीति व योजना बोर्ड ने अतिरिक्त योग्यता तय की थी, जबकि बोर्ड को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। यह काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती थी। इस पर हाई कोर्ट ने विज्ञापन रद कर दिया था तथा विवि को नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद विवि ने नियुक्त किए गए एक प्रोफेसर को पद से हटाया नहीं और न ही कोई नया विज्ञापन जारी किया गया। जिसके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा कि विवि के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के 3 फरवरी 2014 और 17 फरवरी 2014 के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। जिसके लिए उनके विरुद्ध अवमानना का मामला बनता है।

दैनिक जागरण

मधुर वचन औषधि हैं और कटु वचन तीर

मुठभेड़ का सच

हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपी जिस तरह पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए उसे लेकर केवल सवाल ही नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि खुशी भी जताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराने और यहां तक कि उसे न्याय की संज्ञा देने वालों में आम आदमी के साथ सांसद भी शामिल हैं। ऐसा तब है जब इस मुठभेड़ से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और हर कोई इससे अवगत है कि पुलिस कई बार फर्जी मुठभेड़ों को भी अंजाम देती है। फर्जी मुठभेड़ें भीड़ की हिंसा का ही एक रूप हैं। यह जल्द सामने आना ही न्याय के हित में होगा कि हैदराबाद पुलिस ने जनाआक्रोश के दबाव में आकर मुठभेड़ को अंजाम दे दिया या फिर उसने वाकई आत्मरक्षा में सामूहिक दुष्कर्म कांड के आरोपियों को मार गिराया? यदि इस सवाल का जवाब सामने आने के पहले ही एक बड़े वर्ग की ओर से हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को जायज बताया जा रहा है तो इसकी जड़ में दुष्कर्म के मामलों का बढ़ना, महिला सुरक्षा का सवाल कहीं अधिक गंभीर हो जाना और न्यायिक तंत्र का शिथिल होना है। इस शिथिलता का शर्मनाक प्रमाण है सात साल पहले देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के गुनहगारों की दी गई सजा पर अमल न हो पाना।

किसी को सामने आकर यह बताना ही चाहिए कि आखिर निर्भया के गुनहगारों की सजा पर अमल में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल यही नहीं, इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं के निस्तारण में जरूरत से ज्यादा देरी क्यों हो रही है और ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर इतनी कम क्यों है? क्या निर्भया कांड के बाद कानूनों में तमाम संशोधन यही दिन देखने के लिए किए गए थे? अगर नहीं तो फिर हालात जस के तस, बल्कि उससे भी बदतर क्यों दिख रहे हैं? समाज को इन सवालों का जवाब मांगने के साथ ही इस पर भी गौर करना होगा कि दुष्कर्मी तत्व कहीं बाहर से नहीं आते। वे समाज का ही हिस्सा होते हैं। आम तौर पर ये वही तत्व होते हैं जो सरे आम महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं और उन्हें वासना की पूर्ति का साधन मात्र समझते हैं। समाज को अपने बीच सक्रिय ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना ही होगा। वास्तव में एक ओर जहां समाज को महिलाओं को ओछी निगाह से देखने वालों के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है वहीं दूसरी ओर नीति-नियंताओं को यह समझने की जरूरत है कि संचार तकनीक के जरिये हो रहे अश्लीलता के प्रसार ने एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले लिया है।

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। इन दिनों जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने जानकारी दी कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में प्रत्येक सरकारी डिग्री कॉलेज का अपना भवन तैयार हो जाएगा। इसके लिए अनुपूरक बजट में बाकायदा 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल उत्तराखंड गठन के 19 साल बाद भी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर है। उच्च शिक्षा के नाम पर हो रही सियासत ने हालात को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। वोट की फसल काटने के लिए माननीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन शायद ही कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सोचा जाता हो। पिछले दिनों बताया गया कि प्रदेश के 20 ब्लॉकों और 15 विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं। इन क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दे दिए गए। यह आलम तब है कि जबकि कि दो सौ से कम छात्रसंख्या वाले डिग्री कॉलेजों को नजदीकी कॉलेजों में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है। जाहिर ऐसे में यह सवाल मौजू है कि जब कॉलेजों को पर्याप्त संख्या में छात्र में नहीं मिल रहे तो एक के बाद एक कॉलेज खोलने का क्या औचित्य है। सच्चाई यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज जैसे संस्थान एक या दो कमरे में संचालित किए जा रहे हैं। कॉलेज में फैकल्टी का अभाव है तो छात्रों को अपने पसंदीदा विषय के अध्ययन की सुविधा भी नहीं है। इतना ही नहीं इन कॉलेज में न्यूनतम 180 दिन पढ़ाई कराना एक चुनौती बन गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर को छोड़ दें तो प्रदेश का कोई भी संस्थान देश में टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया। इस पर चिंतन और मनन की जरूरत है कि 12वीं के बाद क्यों पर्वतीय क्षेत्रों से बच्चे देहरादून, हरिद्वार अथवा नैनीताल और हल्द्वानी का रुख करने पर विवश हैं। प्रश्न यह है कि स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड भले ही छात्र-छात्राओं की पसंद हो, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वे अन्य राज्यों का रुख करना पसंद करते हैं। अच्छा है कि सरकार सभी सरकारी कॉलेजों के भवन बनाने के लिए दृढ़संकल्पित है, लेकिन इंफास्ट्रक्चर और गुणवत्ता पर भी फोकस करना होगा।

सरकार अब उच्च शिक्षा पर फोकस कर रही है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ भवन खड़े कर देने पर्याप्त नहीं है। फोकस गुणवत्ता पर होना चाहिए

निर्भया के बाद भी बदलाव का इंतजार

विक्रम सिंह

फास्ट ट्रैक अदालतों को सक्रिय करने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे तय अवधि में दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण करें

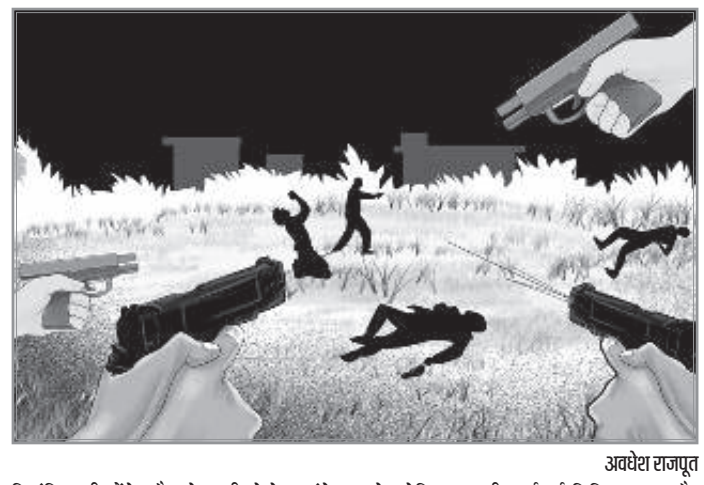

अवधेश राजपूत

हैदराबाद में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने की घटना ने संसद से लेकर सड़क तक बहस तेज कर दी है। पूरा देश इसी घटना पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। पुलिस अधिकारियों की मानें तो पुलिस इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद विवेचना के क्रम में उन्हें घटनास्थल पर ले गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर आक्रमण कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और अंततोगत्वा चारों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। इस मुठभेड की खबर सामने आते ही लोग पक्ष और विपक्ष में खड़े हो गए हैं। एक समूह कह रहा है कि यही होना चाहिए था। उसने पुलिस को बधाई भी दी। हैदराबाद में तो जश्न जैसा मनाया गया। दूसरा समूह यह कह रहा है कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस को और सावधानी बरतनी चाहिए थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रातःकाल आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया? क्या वांछित पुलिस बल नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और चारों आरोपियों को निष्क्रिय करना पड़ा। संदेह भरे सवाल उठना स्वाभाविक हैं, परंतु जो कानूनी स्थिति है उसे भी समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा या किसी अन्य की सुरक्षा अथवा जीवन को खतरे के आधार पर वांछित बल का प्रयोग किया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता ने प्रदान किया है, लेकिन बल प्रयोग का यह अधिकार मनमाना नहीं है। यदि अनुपातिक बल का प्रयोग नहीं किया गया तो यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

क्या हैदराबाद पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वह वांछित था और उसी अनुपात में इस्तेमाल किया गया जो आवश्यक था या उससे अधिक? आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। चूंकि पुलिस मुठभेड़ के मामलों में उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों का भी पालन आवश्यक होता है इसलिए इस मुठभेड़ के मामले में भी एक अपराध पंजीकृत किया जाएगा और उस अपराध की विवेचना क्राइम ब्रांच सीबीसीआइडी करेगी, न कि स्थानीय पुलिस। ऐसी सावधानियां यही सुनिश्चित करने के लिए बरती जाती हैं ताकि यदि पुलिस ने स्वार्थवश या जन भावनाओं के दबाव में कोई मनमाना व्यवहार किया हो तो उसे सामने लाया जा सके। पुलिस की जिम्मेदारी जनभावनाओं के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने की नहीं होती। उसे संविधान और कानून के तहत मिले अधिकारों के तहत ही काम करना होता है। अच्छा होगा कि हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच जल्द हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि हैदराबाद पुलिस की कोई गलती सामने आती है तो हत्या का मुकदमा कायम होने के साथ मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मी निलंबित भी होंगे और जेल भी भेजे जाएंगे, लेकिन यदि मुठभेड़ सही मानी जाती है तो पुलिस कर्मी पुरस्कृत भी हो सकते हैं।

एक बड़े समूह की ओर से हैदराबाद मुठभेड़ को सही बताने का जो काम हो रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। देश इससे स्तब्ध है कि निर्भया के गुनहगारों को सात वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी फांसी की सजा नहीं हो पाई। येन-केन प्रकारेण सजा विलंबित ही होती गई। इस विलंब के कारण समझ से परे हैं। यह देखना दयनीय है कि कानूनों में संशोधन के उपरांत भी हमारी बच्चियों और महिलाओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। दुष्कर्म के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में दुष्कर्म के आरोपी दोषमुक्त हो रहे हैं। निर्भया फंड का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण वांछित स्तर का नहीं हो पाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित गति से मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जन आक्रोश स्वाभाविक है। पुलिस के ऊपर यह दबाव भी रहता है कि वह कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे जनता में एक भरोसा पैदा हो, लेकिन उसकी कार्रवाई विधि सम्मत और कानून की परिधि के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबाव में आकर वह ऐसे कार्य करने लगे जो गैरकानूनी हों। उसकी द्वारा की जाने वाली मुठभेड़ फर्जी भी हो सकती है। कहीं भी फर्जी मुठभेड़ पुलिस अपसंस्कृति का भाग नहीं बन सकती। उसे बनने भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ आवश्यकता इसकी भी है कि आततायियों के मन में पुलिस और कानून का भय दिखना चाहिए। यह आज दिखाई नहीं देता। पुलिस कहीं अपराधियों के प्रति ढिलाई बरतती है तो कहीं चार्जशीट लगाने में देरी करती है। साक्ष्य संकलन में भी लापरवाही दिखती है। इस सबके चलते आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं या फिर उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। उन्नाव के ताजा मामले में ऐसा ही हुआ। जिन आरोपियों ने दुष्कर्म पीड़ित महिला को जलाया उन्हें आखिर जमानत कैसे मिल गई? सवाल यह भी है कि जमानत मिलने पर उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई? 13वें क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के पारित होने के बाद आइपीसी में धारा 166ए एवं उपधारा ई सम्मिलित की गई थी ताकि यदि कोई पुलिसकर्मी कर्तव्य के प्रति उदासीन हो तो उसके खिलाफ भी अपराध पंजीकृत हो सके। इसमें दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे दृष्टांत कम दिखाई देते हैं कि किसी गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मी को धारा 166ए के अंतर्गत जेल भेजा गया हो। यह अक्षम्य है कि कर्तव्य के प्रति उदासीन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति ढिलाई बरती जाए। पुलिस नेतृत्व से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराधियों के साथ-साथ अपराध की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी प्रभावी कार्रवाई करे। पुलिस प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती में भी प्राथमिकता बरती जानी चाहिए। अगर बेटियों-महिलाओं की सुरक्षा करनी है तो यह प्राथमिकता के आधार पर करना ही होगा।

दुष्कर्म के मामलों में न्याय होने में विलंब के कारण देश की जनता के मन में यह सवाल घर कर रहा है कि निर्भया जैसा खौफनाक मामला सामने आने के बाद आखिर सरकार ने किया क्या? अब यह अनिवार्य है कि फास्ट ट्रैक अदालतों को न केवल सक्रिय किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक तय अवधि में मामलों का निस्तारण करें। दुष्कर्म के मामलों में विवेचना 90 दिन के बजाय 45 दिन में की जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही यह अवधि न्यायपालिका की अनुमति से ही 45 और दिन बढ़ाई जानी चाहिए। बेहतर होगा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए। इससे भी आवश्यक यह है कि पुलिस की विवेचना समाप्त होने के बाद समस्त न्याय प्रक्रिया का निस्तारण 180 दिन के अंदर संपन्न करना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा करके ही पुलिस और कानून के प्रति लोगों के भरोसे को बल दिया जा सकता है।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख रहे हैं)

response@jagran.com

जब अपने ही सताएं तो बच्चे कहां जाएं

क्षमा शर्मा

सौतेली मां का बच्चों पर आतंक तो पहले से रहा है, पर इन दिनों सौतेले पिताओं के अत्याचार के मामले भी सामने आ रहे हैं

वर्षों पहले इंदु और आशीष की घटना ने लोगों को दहला दिया था। इंदु ने आशीष के साथ रहने के लिए अपने दो छोटे बच्चों को आग लगा दी थी। अखबारों ने लिखा था कि जब इस घटना के बारे में आशीष से पूछा गया तो वह हंस रहा था। दो छोटे बच्चों को आग लगाना और उस पर हंसना, सबको भयानक लगा था। बाद में इन दोनों का क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन इन दिनों तो ऐसी घटनाएं जैसे आम हो चली हैं। एक हफ्ते के भीतर दो ऐसी घटनाएं पढ़ीं कि उन अनजाने बच्चों के प्रति मन करुणा से भर उठा, जिन्होंने अपने ही परिजनों के कारण जान गंवाई हैं। अपने ही बच्चों से निजात पाने के इतने क्रूरतम तरीके। एक महिला के दो बच्चे थे। वह अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। बड़े बच्चे को उसने गांव में अपने माता-पिता के साथ छोड़ दिया था। दूसरा बच्चा छोटा था, इसलिए उसे साथ ले आई थी। जिसके साथ रहती थी, वह आदमी इस बच्चे को बहुत मारता-पीटता था। एक दिन उसने इस बच्चे को इतना मारा कि उसकी सांस उखड़ गई। मां ने यह देखा तो बच्चे का गला दबा दिया। दूसरी घटना में एक महिला की दूसरी शादी हुई। पहली शादी से उसकी चार साल की एक बच्ची थी। सौतेले पिता ने बच्ची के सीने पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह चल बसी।

सौतेली माताओं के अत्याचार से न केवल हमारे ग्रंथ, बल्कि समाज में बेशुमार कहानियां भरी पड़ी हैं। हालांकि सभी सौतेली मांएं बुरी नहीं होती हैं, वे अच्छी भी होती हैं। आमतौर पर तो वे पति पर पूरा अधिकार चाहती हैं इसलिए वे पहली शादी से हुए बच्चों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। वे सारे अधिकार सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं। समाज में सौतेली मां का बच्चों पर आतंक रहा है, लेकिन इन दिनों दूसरे पिताओं यानी सौतेले पिताओं के अत्याचार के किस्से भी पढ़ने को मिलते हैं। जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।

पहले सौतेले पिता कहानियों, स्मृतियों में इसीलिए नहीं आते थे, क्योंकि तब वे समाज में मौजूद नहीं थे। आमतौर पर औरतों की दूसरी शादी नहीं होती थी। पति के छोड़ देने या विधवा होने पर वे अकेली जीवन काटने को मजबूर होती थीं, जबकि आदमी पत्नी के मरते ही फौरन दूसरा विवाह कर लेते थे और बच्चों की सौतली मां ले आते थे। बहुत बार ये माताएं बच्चों से भी उम्र में छोटी होती थीं। बेमेल विवाह के ऐसे किस्से रोज देखे जाते थे। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला ऐसे ही बेमेल विवाह की कहानी है, मगर उसमें सौतेली मां एक अच्छी महिला है। वक्त बदल गया। समाज और कानून ने औरतों के दूसरे विवाह को स्वीकार किया। परिवारों में अब दूसरी मांएं ही नहीं, दूसरे पिता भी आते हैं। और यह कितना अफसोसनाक है कि वे अपने परिवार में किसी दूसरे के बच्चे को रहने देना नहीं चाहते। सारी इंसानियत स्वार्थ और किसी दूसरे पुरुष के बच्चे को देखकर नफरत में बदल जाती है। जैसे सौतेली माताओं को अपने पति के घर में किसी दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, वैसे ही पुरुषों को भी किसी दूसरे आदमी का बच्चा नहीं चाहिए। इसे वे अपनी तौहीन समझते हैं। औरतें इस बात को अच्छी तरह से समझती भी हैं। इसलिए अनेक बार बच्चों के कारण शादी नहीं करतीं।

वर्षों पहले साथ काम करने वाली एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। उसे अपने पति के स्थान पर उसी दफ्तर में नौकरी मिल गई थी। मैंने एक बार यों ही जिज्ञासावश उससे पूछा कि क्या वह दोबारा विवाह के बारे में नहीं सोचती? आखिर कब तक ऐसे अकेली रहेगी? तब उसने कहा था-मैडम, लोग मुझसे तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं अपनाना चाहते। वे कहते हैं कि उसे अपने साथ न लाऊं। अब भला उस बच्चे को कहां छोड़ूंगी। उसके पिता तो पहले ही नहीं हैं। अब मां भी उसका साथ छोड़ दे तो वह कहां रहेगा? किसके भरोसे रहेगा। मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगा कि मैंने अपने सुख के लिए उसका जीवन तबाह कर दिया। एक तरफ हमारा जीवन है। उसके अपने तर्क हैं, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का जीवन, जहां माता-पिता के निर्णयों के कारण वे तरह-तरह की हिंसा, यहां तक कि जीवन गंवा देने को मजबूर हैं। जाहिर है जब अपने ही सताएं तो बच्चे कहां जाएं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

दुष्कर्म के मामलों में सुनाई गई सजा का प्रतिशत

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

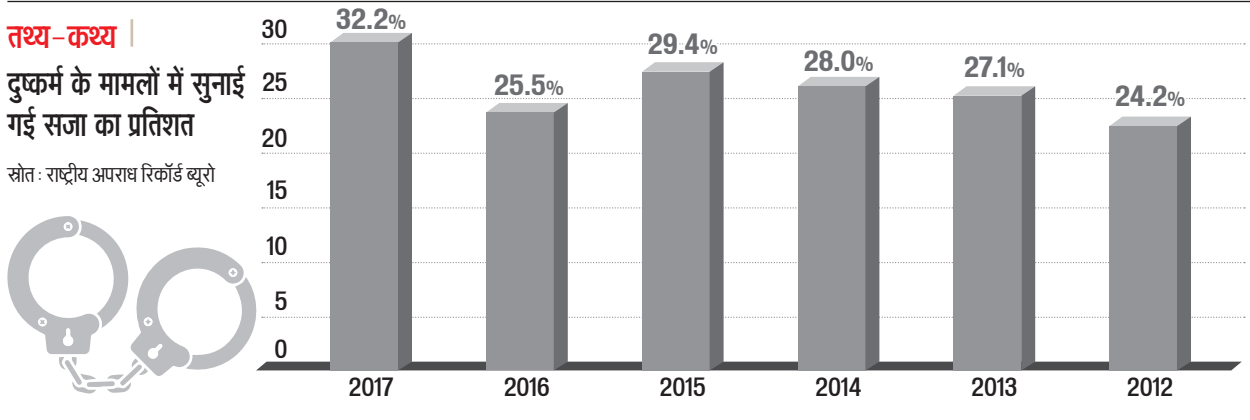

ऊर्जा

सहनशीलता

सहनशीलता में एक ऐसी अद्भुत शक्ति समाई रहती है जो आत्म चेतना को अमरत्व प्रदान कर अजेय बना देती है। दूसरी ओर जहां सहनशीलता का अभाव रहता है वहां व्यक्ति के टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जीवन का सत्य सहनशीलता ही है। अंत में जीत उसी की होती है जो जीवन में पड़ रही चोटों से विचलित न होकर इन्हें धैर्य पूर्वक सहता और स्वीकार करता रहता है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता अधिक होती है उसे जीवन में आने वाले कष्ट, कष्ट के रूप में नहीं लगते हैं। सहनशीलता यदि सामान्य है तो जीवन में प्रतिक्षण आने वाले अधिकांश कष्टों का निवारण विवेक का प्रयोग करके किया जा सकता है, किंतु जहां सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है वहां ऐसे लोग जीवनपर्यंत अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण ऐसे लोग जीवनपर्यंत भारी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान उठाते रहते हैं।

मानव स्वभाव में क्रोध, इच्छाएं, लालसाएं, अहंकार ऐसे अवगुण हैं जो कुछ न कुछ हर व्यक्ति में रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनमें इन चारों अवगुणों में से किसी भी अवगुण के कुछ अंश का समावेश न हो। जिन लोगों में इस प्रकार की कमियों का अंश बहुत ही कम होता है वे लोग अपने विवेक का प्रयोग करके इन कमियों से होने वाले नुकसान से अपने को बचा लेते हैं। इसे सामान्य स्थिति ही कही जाएगी, किंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें यही कमियां आसमान को छूती नजर आती हैं। अर्थात उनमें इन कमियों का अंश बहुत अधिक होता है। यह निश्चित ही व्यक्ति की असामान्य स्थिति है। ऐसे में इन पर विशेष रूप से ध्यान देकर इन्हें सामान्य स्थित तक लाना ही पड़ेगा।

सहनशीलता एक ऐसी दवा है जो ऐसी सभी स्थितियों को सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हर व्यक्ति को इतना सहनशील अवश्य होना चाहिए ताकि उसका क्रोध, उसकी लालसाएं एवं अहंकार उसके मस्तिष्क पर अपना विपरीत प्रभाव न डाल सकें।

वीके जायसवाल

भय के माहौल में बेटियां

डॉ. मोनिका शर्मा

योग्यता और क्षमता के बावजूद देश की अधिकांश महिलाएं खुद को चाहरदीवारी में कैद करने को मजबूर हैं

आज श्रमशक्ति में अहम भागीदारी निभा रहीं बेटियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित दफ्तर पहुंचने और घर लौट आने की ही है। असुरक्षा के कारण आज भी महिलाएं योग्यता और क्षमता के मुताबिक नौकरी नहीं चुन पातीं। असुरक्षित हो चले परिवेश में महिलाएं एक बंधे हुए रूटीन में ही काम कर पाती हैं। यही वजह है कि उच्च शिक्षा के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद 1994 से महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी लगातार घट रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने कुछ समय पहले महिला श्रम बल की हिस्सेदारी को लेकर यह अनुमान जारी किया था। यानी योग्यता और क्षमता के बावजूद देश की महिलाएं खुद को घरों में कैद करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखने वाले अभिभावक भी डरे-डरे रहते हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले आए एसोचैम के एक सर्वेक्षण में दिल्ली की 92 प्रतिशत, बेंगलुरु की 85 प्रतिशत, कोलकाता की 82 प्रतिशत और हैदराबाद की 18 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि वह दिन और रात दोनों ही पाली में काम करने में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं शत प्रतिशत महिलाओं ने माना कि महिलाओं की सुरक्षा की समस्या देश की किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ी है।

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़े भी आधी आबादी की चिंतनीय स्थिति को सामने रखने वाले हैं। वर्ष 2017 की रिपोर्ट बताती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में करीब छह फीसद का इजाफा हुआ है। एनसीआरबी के अनुसार घर के भीतर अपनों का दुर्व्यवहार हो या नाबालिग बच्चियों के शोषण के मामले हों, देश में हर उम्र, हर वर्ग की महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। 18 से 30 साल की युवतियों के लिए तेलंगाना देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। वर्ष 2017 में वहां दर्ज हुए दुष्कर्म के कुल मामलों में 91 फीसद पीड़िताएं 18 से 30 साल की हैं।

आज की बेटियां कामकाजी बन रही हैं। आत्मनिर्भर बन परिवार ही नहीं देश की तरक्की में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर रही हैं। बावजूद इसके नैतिक और सामाजिक मूल्यों की गिरावट के इस मौजूदा दौर में आधी आबादी भय के परिवेश में जीने को विवश है। हैदराबाद में हुई सहायता करने के नाम पर दरिंदगी की घटना भी पूरी सामाजिक व्यवस्था से भरोसा उठाने वाली है, कामकाजी बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को सामने रखती है। ऐसी घटनाओं से न सिर्फ इंसान का एक दूजे से भरोसा डगमगा रहा है, बल्कि खत्म होते सामाजिक ताने-बाने की हकीकत भी हमारे सामने आ रही है। दुखद है कि ऐसे हादसे उस समाज के बीमार और बदरंग होते चेहरे को दिखाते हैं, जिसमें बेटियों की सुरक्षा साझी जिम्मेदारी समझी जाती है। आपसी सहयोग और सम्मान विचार और व्यवहार का हिस्सा रहे हैं। जरूरी है कि समाज, परिवार और सरकार सभी चेतें। न सिर्फ ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, बल्कि त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सख्त सजा भी दी जाए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

दिशाहीन करने वाला निर्णय

कांग्रेस को दिशा देने वाला फैसला शीर्षक से प्रकाशित रशीद किदवई के लेख से सहमत नहीं हुआ जा सकता। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जाने का कांग्रेस का यह निर्णय पार्टी को दिशाहीन करने का काम करेगा। याद कीजिए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विचारधारा की लड़ाई की बात कही थी, लेकिन आज वही विचारधारा से समझौता करके कट्टर शिवसेना के साथ सरकार बना रही हैं। यह कैसा वैचारिक संघर्ष है जो सत्ता की मलाई देखते ही ढोंग बनकर रह जाता है। यह तो कांग्रेस की पूर्णतया मौकापरस्ती और कपट की राजनीति है। देश भर में कांग्रेस की विचारधारा का झंडा बुलंद करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं में इसका क्या संदेश जाएगा? क्या इस पर कांग्रेस नेतृत्व ने कभी विचार किया है? यह यक्ष प्रश्न है। महाराष्ट्र में विभागों के बंदरबांट का जो खेल चल रहा है उसे पूरा देश गौर से देख रहा है। बेहतर होता कि कांग्रेस अपनी वैचारिक पूंजी बचाकर जनता के बीच सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करती तो उसकी कहीं ज्यादा विश्वसनीय छवि बनती।

अभय सिंह, आदर्श नगर, अयोध्या

बेटियों की सुरक्षा

देश के हर राज्य में हम नारी को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। जिन बेटियों को हमने खो दिया है उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे घृणित लोगों से अन्य बेटियों को बचाने का प्रयास अवश्य किया जाया जा सकता है। इसके लिए हम सभी को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। अच्छे संस्कारों से ही ऐसे अक्षम्य आपराधिक मानसिक बीमार लोगों से मातृशक्ति की रक्षा की जा सकती है। घर, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में भी परिवार के साथ शिक्षकों को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से नारी सम्मान जैसे विषयों के प्रति बच्चों तथा युवाओं को समय-समय पर जागरूक करते रहने की जरूरत है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक बच्चे किस संगति में रहते हैं इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए उनको गलत हरकतों के लिए प्यार तथा सख्ती से मना करते हुए उन पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए। बेटियों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सक्षम बनाने का भी प्रयास करें। परिवार तथा अध्यापकों का दायित्व बनता है कि बच्चे किसी भी प्रकार के नशे अथवा बुरी संगति में नहीं पड़ें इसके लिए विशेष ध्यान देना होगा। सभी स्थानों पर हमारी रक्षा के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं हो सकता है, इसलिए हमको भी एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए बहन-बेटियों की रक्षा करने में उनकी मदद करने की जरूरत है। आप किसी स्थान पर बेटी की रक्षा करते हैं तो किसी अन्य स्थान पर आपकी बेटी की रक्षा करने के लिए भी आप जैसा कोई जरूर आगे आएगा।

आचार्य राम कुमार बघेल , पलवल

सब आएंगे

मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर चुका है कि अब इस धरती का धैर्य साथ नहीं दे रहा है। वह इसके प्रतिरोधस्वरूप कभी तूफान, कभी अतिवृष्टि, मौसम असंतुलित करके बार-बार चेतावनी दे रही है। पता नहीं कितनी बार दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इस असंतुलन को ठीक करने के लिए वैश्विक जलवायु सम्मेलन हो चुके, परंतु कुछ देशों का स्वार्थ इन सम्मेलनों के उद्देश्य पर पानी फेर देता है। विचारणीय है कि इन असंतुलनों से जब यह धरती पर संकट आएगा तो उसकी चपेट में सब आएंगे। संपूर्ण मानव मात्र के हित की सोच पर विचार कर ही कोई निर्णय करना चाहिए।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

प्याज के बढ़ते भाव

देश में प्याज 75 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इस बीच तुर्की से प्याज आयात की खबर आ रही है। गौरतलब है कि हमारे देश के ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की भरपूर पैदावार होती है। वहीं सरकारी गोदामों में रखे प्याज के हर साल सड़ जाने या खराब हो जाने की खबरें आती हैं। इसके बावजूद भी हमें विदेशों से प्याज आयात करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकारी गोदामों में सामान के रख-रखाव की स्थिति में सुधार लाए और कालाबाजारी पर रोक लगाने के प्रयास हों।

उपासना, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

8.5 प्रतिशत थी भारत में बेरोजगारी दर अक्टूबर माह तक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक। भारत में बेरोजगारी की यह दर अगस्त 2016 के बाद से सबसे अधिक है।

आजकल

रोजगार के मोर्चे पर निरंतर बढ़ती चिंता

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

देश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। बीते दो वर्षों के दौरान खास तौर पर देश में रोजगार विकास की रफ्तार सुस्त हुई है। देश-समाज की तरक्की के लिए आज आर्थिक विकास एक बड़ा पैमाना बन चुका है। ऐसे में रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार को व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुआयामी प्रयास करने होंगे। अर्थव्यवस्था पर सरकार की पकड़ कायम रहे, इसके लिए समय रहते उसे व्यावहारिक कदम उठाना चाहिए

प्रतीकात्मक

इन दिनों भारत में रोजगार के वर्तमान और भावी परिदृश्य को लेकर विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट्स में दो बातें उभर कर सामने आ रही हैं। पहला, मौजूदा समय में आर्थिक सुस्ती के कारण देश में रोजगार विकास दर धीमी हो गई है। दूसरा, युवाओं को बेहतर रोजगार लायक बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगामी एक दशक में महती प्रयासों और निवेश की आवश्यकता है। साफ है कि रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुआयामी प्रयास करने होंगे। नए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाए। साथ ही नवंबर 2019 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो 6.84 लाख पद खाली पड़े हैं, उन्हें शीघ्र भरने की कवायद की जाए। स्वरोजगार और स्टार्टअप से भी रोजगार अवसर बढ़ाए जाएं। बदलती दुनिया में उभरती नई-नई रोजगार जरूरतों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु निवेश बढ़ाया जाए

गंभीर हो रही रोजगार की दशा : केयर रेटिंग्स नामक एक रेटिंग एजेंसी द्वारा रोजगार की स्थिति पर प्रस्तुत हालिया अध्ययन के अनुसार देश में रोजगार संबंधी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस अध्ययन में उद्योग-कारोबार और सेवा क्षेत्र से जुड़ी 1,938 कंपनियों को शामिल किया गया था। अध्ययन से पता चला कि देश में रोजगार वर्ष 2015-16 में 2.5 प्रतिशत, 2016-17 में 4.1 प्रतिशत, 2017-18 में 3.9 प्रतिशत और 2018-19 में 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़े।

इस अध्ययन के तहत देश के मुख्य उद्योगों में तो रोजगार विकास की स्थिति नकारात्मक पाई गई, यानी रोजगार बढ़ने के बजाय घटे ही। वहीं देश के उपभोक्ता-उन्मुख उद्योगों ने एक अलग पैटर्न दिखाया, जैसे कृषि और टिकाऊ सामानों से जुड़े रोजगार में मंदी आई। एफएमसीजी और वस्त्र उद्योग में 3.3 प्रतिशत के औसत से कम स्तर पर वृद्धि हुई। इसी तरह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भी बढ़ती बेरोजगारी का चिंतनीय परिदृश्य उभरकर सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर अक्टूबर में बढ़कर 8.5 फीसद हो गई, जो अगस्त 2016 के बाद से सर्वाधिक है। ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यस्था में सुस्ती के लक्षणों को दर्शाते हैं। इसी तरह अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट द्वारा भारत में रोजगार के परिदृश्य पर हुए अध्ययन में कहा गया कि कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में कमी आई है, वहीं निर्माण व सेवा क्षेत्र भी इस गिरावट को कम नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार 47.42 करोड़ थे, जो वर्ष 2017-18 में घटकर 46.51 करोड़ रह गए।

यह तो हुई रोजगार की स्थिति की बात, अब हम रोजगारपरक शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी नजर डालते हैं। हाल ही में शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों की विश्व रैंकिंग से संबंधित दो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं। एक तो 26 नवंबर को आई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2020 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में भारत के अधिकांश प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में गिरावट आई। देश का कोई भी शिक्षण संस्थान शीर्ष 30 एशियाई संस्थानों की सूची में जगह नहीं बना सका। आइआइटी, मुंबई पिछले वर्ष के मुकाबले एक स्थान फिसलकर 34वें स्थान पर आ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक शिक्षा अध्ययन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी छात्रों की आबादी भारत में होगी। ऐसी नई आबादी को रोजगार योग्य बनाने के लिए भारत को अध्ययन तथा शोध कार्य में अपना निवेश बढ़ाना ही होगा।

इसी तरह 18 नवंबर को विश्वविख्यात आइएमडी बिजनेस स्कूल, स्विट्जरलैंड द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग, 2019 आई। इसमें भारत 63 देशों की सूची में पिछले वर्ष के मुकाबले छह पायदान फिसलकर 59वें स्थान पर आ गया। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में बहुत पीछे रहने पर चिंता लाजिमी है। इससे आगे बढ़ने की राह निकालनी ही होगी। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हुनरमंद और प्रतिभावान बनाकर ही रोजगार की संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। चूंकि भारत के पास विकसित देशों की तरह रोजगार बढ़ाने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अतएव इसकी युवा आबादी ही आज की जरूरतों के मुताबिक कौशल प्रशिक्षित होकर मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लिए उपयोगी और भारत के लिए कमाई का प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है।

देश में युवाओं के लिए रोजगार के परिदृश्य को सुधारने हेतु व्यापक उपाय करने होंगे। स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। इस समय दुनिया में भारत स्टार्टअप के मामले में तीसरे क्रम पर है। ऐसे में नई पीढ़ी को स्टार्टअप के माध्यम से भी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना श्रेयस्कर होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निकाय श्रम ब्यूरो ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 से लेकर 2018 के बीच मुद्रा योजना के तहत 4.25 करोड़ नए उद्यमियों को कर्ज बांटे गए। इन कर्जों ने कुल 11.2 करोड़ नए रोजगार पैदा किए। यह संख्या स्वरोजगार में लगे लोगों की 55 फीसद है। ऐसे में मुद्रा योजना को और अधिक विस्तारित करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने जरूरी हैं।

यह उम्मीद की जा सकती है कि सरकार देश में युवाओं की खातिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाएगी और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों/ योजनाओं आदि को बढ़ावा देगी। सरकारी विभागों में खाली पदों पर शीघ्रता से नियुक्तियां करेगी। इसके साथ-साथ सरकार स्वरोजगार और स्टार्टअप से रोजगार बढ़ाने के लिए त्वरित कदम उठाएगी। यह सही है कि देश में इस वक्त आर्थिक सुस्ती का माहौल है, जिसकी वजह से रोजगार भी घट रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार को चौतरफा उपाय करने होंगे। युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसके सही नियोजन के जरिये ही हम देश को तेजी से तरक्की की राह पर आगे ले जा सकते हैं। लिहाजा, हमारे नीति-नियंताओं को ऐसे उपाय करने ही होंगे, जिससे शहरी व ग्रामीण समेत तमाम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें और युवा ऊर्जा को सही दिशा में नियोजित किया जा सके।

अर्थव्यवस्था पटरी पर लाए सरकार

विजय कपूर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यह दावा किया कि अर्थव्यवस्था धीमी जरूर हो गई है, लेकिन न तो मंदी आई है और न ही कोई ऐसी आशंका है। लगता है उन्हीं के इस आश्वासन से अगले ही दिन शेयर बाजार ने रिकॉर्ड बना दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज देश के इतिहास की पहली 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी वाली कंपनी बन गई, जो देश के बजट की लगभग एक तिहाई हैसियत है। मगर इन उत्साही घटनाओं के साथ ही अब तक का सबसे बड़ा झटका भी अगले ही दिन सामने आ गया, जो न केवल निर्मला सीतारमण के दावे को तार तार कर गया, बल्कि देश को आर्थिक खौफ के एक नए चक्रव्यूह में फंसा गया है, क्योंकि लगातार छठी तिमाही देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है।

अर्थव्यवस्था की यह डरावनी तस्वीर सरकारी एजेंसियां ही लाई हैं, जिसे संसद में केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार ने पेश किया। क्या अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर संतोष गंगवार ने संसद में और सरकारी एजेंसियों ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की भारी गिरावट के रूप में पेश किया है उसकी वित्त मंत्री को खबर नहीं थी? या तो आपस में विभिन्न सरकारी महकमों के बीच कोई समन्वय नहीं है या फिर सबकी अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हाल के दिनों में ही कई विरोधाभासी बातें सरकार के ही अलग अलग हिस्सों से देखने में आई हैं।

बहरहाल मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की दर 4.5 प्रतिशत दर्ज की गई है जो कि पिछले छह वर्ष की न्यूनतम विकास दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़े झटके की तरह है। इससे पहले मार्च 2013 तिमाही में देश की जीडीपी दर इस स्तर पर थी। मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2019-20 की पहली तिमाही में भी जीडीपी ग्रोथ की दर पांच फीसद पर थी। इस लिहाज से महज तीन महीने के भीतर जीडीपी की दर में 0.5 फीसद की गिरावट आई है जो बहुत ज्यादा है। पिछली छह तिमाहियों से अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। वर्ष 2019 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट आठ फीसद थी। दूसरी तिमाही में यह घटकर सात फीसद रह गई। तीसरी तिमाही में 6.6 फीसद और चौथी तिमाही में 5.8 फीसद पर रही। इस तरह वित्त वर्ष 2019 में विकास दर लगातार पतन का शिकार रही। लग रहा था शायद मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस गिरावट से निजात मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में जीडीपी गिरकर पांच फीसद पर आ गई और रही सही कसर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही ने पूरी कर कर दी, जब यह दर पहली तिमाही से भी पांच प्रतिशत नीचे गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई।

इस बीच कोर इंडस्ट्री के भी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक एक वर्ष पहले के मुकाबले कोर सेक्टर में 5.8 फीसद की कमी आई है। दरअसल आधुनिक अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद की भूमिका केंद्रीय होती है। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे अहम पैमाना जीडीपी के आंकड़ों को ही माना जाता है। भारत में जीडीपी आंकड़ों की गणना तिमाही के आधार पर होती है। ये आंकड़े मुख्य तौर पर आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साझे उत्पाद और उपभोग पर आधारित होते हैं। इनके उत्पाद और सेवाओं के आंकड़े देश का केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जारी करता है। इन आंकड़ों को ही आधिकारिक माना जाता है। इन आंकड़ों को अलग-अलग मंत्रालय से सरकारी संस्था सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जुटाता है। इसके बाद सीएसओ इसकी गणना कर आंकड़े जारी करता है। जीडीपी के यही आंकड़े आधिकारिक माने जाते हैं।

जीडीपी का देश के हर व्यक्ति से एक विशिष्ट जुड़ाव होता है, क्योंकि इन आंकड़ों का आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट आती है जिससे आम लोगों की आय कम हो जाती है। लोगों की आय कम होने से देश की औसत आय भी घट जाती है। नई नौकरियां पैदा होनी कम हो जाती हैं। अर्थव्यवस्था के स्लो डाउन में चले जाने का मतलब सिर्फ आर्थिक संकट भर नहीं होता, यह कई किस्म के सामाजिक संकट और उथल पुथल को जन्म देता है। इसलिए हाथ से निकलती अर्थव्यवस्था अस्थिर सामाजिक व्यवस्था के लिए भी चिंता का कारण बन सकती है।

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

खरी-खरी

जीडीपी का गिरना भी कोई गिरना है!

अंशुमाली रस्तोगी

तो, क्या हुआ अगर जीडीपी गिर गई? जीडीपी के गिरने पर इतना हंगामा क्यों है! कौन नहीं गिरता यहां?

बड़े किस्मत वाले होते हैं वो, जो गिरते हैं। गिरने से ही तो उठने का हौसला आता है। मैं तो दिन भर में कितनी दफा यों ही गिर जाता हूं। सड़क पर पड़े केले के छिलके पर जान-बूझकर पैर रखता हूं ताकि गिर सकूं। इसकी तो मैंने कभी परवाह ही नहीं की कि लोग मेरे गिरने पर हंसेंगे या मजाक बनाएंगे। लोगों को सिगरेट पीने, कार खरीदने, सीटी बजाने का शौक होता है, मुझे गिरने का है। क्योंकि इस देश में जो जितना गिर रहा है, कमबख्त वो उतना ऊपर जा रहा है।

मुझे उन नेताजी की संसद में कही यह बात बहुत अच्छी लगी कि 'वर्ष 1934 से पहले जीडीपी थी ही नहीं। और भविष्य में जीडीपी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।' गलत क्या कहा उन्होंने! जीडीपी महज खानापूर्ति ही तो है। ये किसी के लिए 'खाना' है तो किसी के लिए 'पूर्ति'! आम आदमी क्या जाने खानापूर्ति के खेल! मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, फिर भी जीडीपी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे चैनलों पर देश की बात कहते लोग देश के बारे में कुछ नहीं जानते। अर्थव्यवस्था, जीडीपी, रेपो रेट आदि बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के समझने के मसले हैं। हम-आपको इससे क्या मतलब? रोजी-रोटी बनी रहे, बस यही बहुत है हमारे लिए। जीडीपी गिर रही है या उठ रही है, उससे अपने को क्या? ये अर्थशास्त्री जानें। पता नहीं विपक्षी लोग जीडीपी गिरने पर काहे इतना हल्ला काटे हुए हैं।

वो आज गिरी है, तो कल उठ भी जाएगी। वो कोई नेताजी की नीयत थोड़ी है जो हमेशा गिरी ही रहेगी। सेंसेक्स भी तो जाने कितनी बार गिरा है, फिर उठ गया। गिरना-उठना तो जीवन के शाश्वत सत्य हैं। विश्वास न हो तो किसी बाबा की सीडी (प्रवचन वाली) सुन लो। अब, इतने बड़े मुल्क में कुछ न कुछ गिरता ही रहता है। ऊंची बिल्डिंग बनाते-बनाते मजदूर गिर जाते हैं, मिग विमान उड़ते-उड़ते गिर जाते हैं, कभी कहीं कोई इंसान गिर जाता है तो कभी महाराष्ट्र में सरकार गिर जाती है। दरअसल, गिरने वाले के प्रति दिल में सम्मान रखना चाहिए। गिर तो कोई भी, कहीं भी सकता है। कई लोग सोते-सोते बिस्तर से गिर जाते हैं। तो फिर जीडीपी के गिरने पर ही हल्ला क्यों?

मेरा दावा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स न होगा, जो कभी गिरा न हो।

ट्वीट-ट्वीट

कानून जख्मों पर सो नहीं सकता! हैदराबाद पुलिस ने चारों दुष्कर्मियों को क्यों मारा यह जांच का विषय है, पर देश के 99 .9 प्रतिशत लोग इससे खुश हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि दुष्कर्म जैसे अपराध के मामलों में देश की न्यायिक प्रकिया फेल हो गई है।
मेजर सुरेंद्र पूनिया@MajorPoonia

संविधान, विधि-सम्मत राज्य व्यवस्था के दावों को झटके में ध्वस्त करके, दुष्कर्म-हत्या से आगबबूला बदला मांगते जनमत को संतुष्ट करके लोकप्रियता हासिल करने के लिए हैदराबाद पुलिस (या सरकार?) की जंगल न्याय वाली कार्रवाई पर लोग जश्न मना रहे हैं। आत्मघाती हैं ये भावनाएं।
राहुल देव@rahuldev2

अपराधी अपनी गति को प्राप्त हुए। पुलिस की आलोचना करने वाले यह भी सोचें, जरा कल्पना कीजिए, हैदराबाद में दुर्घटना का सीन रिक्रिएट किए जाते समय यदि कहीं ये चारों अपराधी वहां से भागने में सफल हो जाते तो आज पूरा देश पुलिस को कोस रहा होता। हैदराबाद पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया। मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

मनोज झा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

सियासी गहमागहमी के बीच हरियाली की बात

जब सिर पर चुनाव हो तो राजनीतिक गलियारे से आम तौर पर लोकलुभावन नारे या मुद्दे ही उछाले जाते हैं। सस्ता अनाज, खाना, कपड़ा, टीवी, मुफ्त लैपटॉप, कर्ज माफी जैसे चुनावी शिगूफों की इस देश में कोई कमी नहीं है। इनमें से कई नारे और वादे कारगर भी साबित होते रहे हैं। इतना ही नहीं, वोटरों से वादा करके सत्ता में आई पार्टी या सरकार इसे एक हद तक पूरा करने का प्रयास भी करती है। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां शिवसेना ने रियायती दर पर खाना उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है।

ऐसे सियासी माहौल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक ऐसे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया है जिसे लेकर अभी आम जनता में जागरुकता का अभाव है। लोकलुभावन तो यह कतई नहीं है। बात जल, जीवन और हरियाली मिशन की हो रही है।

गांधी जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किए गए इस मिशन का संकल्प और लक्ष्य बेशक बहुत बड़ा और व्यापक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे लेकर जिस तरह इच्छाशक्ति और सक्रियता दिखाई है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार इस मामले में फिर एक नजीर पेश कर सकता है। नीतीश ने इसे लेकर न सिर्फ सरकार की पूरी मशीनरी को कमर कसने को कहा है, बल्कि इसकी मॉनीटरिंग के लिए खुद ही कमान संभालने की बात भी कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पूरे प्रदेश में तालाबों और कुओं को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है।

चूंकि इस मिशन को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर दिखाई देते हैं, इसलिए बहुत संभव है कि इसके कुछ ठोस नतीजे भी जरूर देखने को मिलेंगे। इस मिशन में जल संसाधनों के जीर्णोद्धार और उन्हें सहेजने के साथ-साथ हरियाली के विस्तार का भी संकल्प जताया गया है। इसके तहत पूरे प्रदेश में छह करोड़ पौधे रोपने की योजना है। ऐसे में यह देखना जरूरी होगा कि इस मिशन के परवान चढ़ने की कितनी संभावना है? साथ ही यह भी कि इसकी राह में मुख्य बाधाएं क्या हैं।

प्रतीकात्मक

इस बात में संदेह नहीं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारें गंभीर हैं। हालांकि यह अलग बात है कि सरकार के स्तर की शुरुआती गंभीरता बाद में अमल के स्तर पर जाते-जाते उदासीनता के दंश का शिकार होने लगती है। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि इन योजनाओं या अभियानों से ऐसे सरोकार जुड़े हैं, जो सीधे तौर पर किसी व्यक्ति या मतदाता समूह को प्रभावित नहीं करते। प्रदूषित हवा, सिमटती हरियाली या दम तोड़ते नदी-तालाब तात्कालिक तौर पर कोई नुकसान पहुंचाते नहीं दिखाई देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीनता का नुकसान दीर्घकालिक या स्थायी है।

दूसरे शब्दों में चूंकि यह समस्या पूरे समाज, देश या भूगोल से जुड़ी है, इसलिए निजी तौर पर इसे लेकर संवेदनशीलता का अभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि हम अपने घर को तो साफ-सुथरा रखते हैं, जबकि मुहल्ले में कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आते। ऐसे हालात के बीच मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में जल, जीवन और हरियाली मिशन को लेकर अपना संकल्प दिखाया है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार के इस प्रयास में हम सभी को साथ-साथ कमर कसनी होगी। इसी प्रकार नौकरशाही भी जिस तरह चुनाव के दौरान पूरी सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभाती है, कुछ उसी मूड-मिजाज से उसे इस मिशन को भी लेना होगा।

बिहार के संदर्भ में सबसे संतोषजनक बात यह है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद इस प्रदेश ने पूर्व में कुछ ऐसे व्यापक हित के सामाजिक मुद्दों को लेकर दृढ़ संकल्प और उच्च संवेदनशीलता दिखाई है। शराबबंदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जिस तरह शराबबंदी ने बिहार में सामाजिक सुधार की राह एक हद तक आसान बनाई है, उससे यह पता चलता है कि ठोस पहल होनी चाहिए, बाकी का काम लोग मिल-जुलकर पूरा कर लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जल, जीवन और हरियाली मिशन भी उम्मीद जगाती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि बिहार के बंटवारे के समय प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र बहुत कम रह गया था। तब से सरकार और समाज के समवेत संकल्प और प्रयास का ही शायद यह परिणाम है कि आज हरियाली का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोग पानी और हरियाली बचाने को लेकर जागरूक भी हुए हैं। अभी पिछले दिनों भागलपुर जिले में चंपा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दैनिक जागरण के समाचारीय अभियान से जिस तरह पूरे समाज ने कंधे से कंधा मिलाया, उससे भी बहुत आश्वस्ति मिलती है।

ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जल, जीवन और हरियाली मिशन को भी कामयाब बनाकर बिहार देश के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा। मुख्यमंत्री ने ऐसी अपेक्षा भी जताई है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ दलों की आपत्ति उचित है?

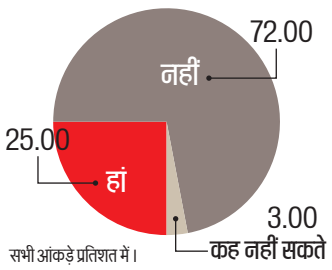

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

हैदराबाद में दुष्कर्म के चारों आरोपितों का एनकाउंटर किए जाने से अपराधियों के मन में डर बैठेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जहां पीड़िता थी मरी वहीं मरे जल्लाद,
हुआ पुलिस के नाम पर जमकर जिंदाबाद।
जमकर जिंदाबाद गए जल्लाद जहन्नुम,
शायद सीधी होय बंधु अब कुत्ते की दुम!
बजता देर-सबेर न्याय का बिल्कुल डंका,
बजा जिस तरह आज जली थी जहां पीड़िता।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

चुनाव पूर्व गठबंधन पर हो चुनावी सुधार

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाइएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आया, उसे देखते हुए अवसरवाद की सत्ता पर लगाम लगाने के लिए ठोस चुनावी सुधार किए जाने की आवश्यकता अब महसूस हो रही है

सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग ने वर्ष 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में चुनाव प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सुधार हेतु दर्जन भर सुझाव दिए थे। इसमें एक यह भी था कि दल-बदल कानून में परिवर्तन कर चुनाव पूर्व गठबंधन को एक ही दल माना जाए। यदि समय रहते इस सुझाव को अमल में लाया जाता तो संभवतः महाराष्ट्र में जो सियासी तस्वीर इन दिनों उभरी, शायद ऐसा न होता।

हो सकता है कि इन सुझावों को अपनाने में कठिनाई हो, लेकिन बदलती राजनीतिक तस्वीर के बीच मतदाताओं की राजनीतिक चेतना और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को प्रत्येक परिस्थितियों में स्वतंत्र छोड़ना भी कितना औचित्यपूर्ण रहेगा। गठबंधन की राजनीति अस्थिरता के कारकों से युक्त देखे जा सकते हैं। बावजूद इसके इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था के चलते ये परिस्थितियां उभरती रहेंगी। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया पर नतीजों के बाद सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते दोनों ने अलग राह पकड़ ली। नतीजन वहां एक सियासी संकट खड़ा हो गया। जाहिर है यहां यदि विधि आयोग की उक्त सिफारिश को जगह मिली होती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। चुनाव पूर्व गठबंधन अधिक भरोसे का होता है। मतदाता भी उसे उसी रूप में स्वीकृति देता है। जबकि नतीजों के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सत्ता साझा करने के लिए जो गठबंधन होता है वह अवसरवाद का परिचायक है।

महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा विधानसभा के नतीजे भी घोषित किए गए जिसमें 40 सीट जीतने वाली भाजपा सत्ता हथियाने में कुछ स्थानों से चूक गई और जिसके मुकाबले चुनाव लड़ा उसी जेजेपी से हाथ मिलाते हुए सत्तासीन हुई। इन संदर्भों से यह प्रतीत होता है कि चुनाव सुधार की दिशा में भले ही दर्जनों आयोग और समितियां बनाई गई हों, पर राजनीतिक दलों की स्वतंत्रताओं को कहीं पर भी अंकुश में नहीं रखा गया। हालांकि 1985 के 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दल-बदल कानून लाकर पार्टी के भीतर होने वाले टूट को रोकने का प्रयास किया गया जिसे लेकर 2003 में पुनः एक बार संशोधन किया गया। बाकी ऐसा कोई खास सुधार नहीं दिखता जिसके चलते सियासी दल कुछ और मामलों में राजनीति करने से बाज आएं।

उद्धव ठाकरे फाइल फोटो

देवेंद्र फड़नवीस फाइल फोटो

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के बगैर लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ऐसी ही व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए 1980 के समय से चुनाव सुधार की दिशा में तेजी से कदम उठने लगे। बावजूद इसके अभी यह पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाया है। अब तो मांग 'एक देश, एक चुनाव' की हो रही है। मौजूदा सरकार भी इस प्रक्रिया को लेकर कहीं अधिक सकारात्मक दिखाई देती है। इसके लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी और इसके समक्ष खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी।

चुनावी महापर्व में जिन नई बातों का उदय हो रहा है उसे भी सुधार का हिस्सा बनाना होगा, मसलन चुनाव पूर्व गठबंधन को अलग न होने की व्यवस्था और नतीजों के बाद विलग विचारधारा पर बनी सरकारें इतनी भी स्वतंत्र न हों कि जब चाहें पल्ला झाड़ लें। देश में निरंतर चुनाव होते रहते हैं और इसी को ध्यान में रखकर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की बात हो रही है। यदि ऐसा होता है तो जाहिर है कि चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में ही संभव होंगे। पिछले लोकसभा के चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हुआ था। इसके अलावा प्रांतों में चुनावी व्यय का सिलसिला जारी रहता है। देश समृद्ध तभी होगा जब पूंजी उत्पादकता मूलक हो ना कि बार-बार के चुनावी महोत्सव की भेंट चढ़ जाए।

वर्ष 1989 की दिनेश गोस्वामी समिति, टीएन शेषन की सिफारिशें, इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें समेत एमएस गिल की सिफारिशों की पड़ताल बताती है कि समय व परिस्थिति के साथ सभी ने अपने तरीके के चुनावी सुधार सुझाए हैं। लोक जनप्रतिनिधित्व कानून में भी समय-समय पर संशोधन होता रहा है। चुनाव आचार संहिता को लेकर भी निर्वाचन आयोग काफी सक्रिय रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग और चुनाव सुधार से जुड़ी बातें देखी जा सकती हैं। चुनावी प्रक्रिया के मामले में भी बहुत कुछ मजबूती दी गई है। समय के परिप्रेक्ष्य में मतदाता पहचान पत्र से लेकर ईवीएम को अंगीकृत हेतु कदम उठाए गए। स्पष्ट है कि इससे मतदान और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बल मिला, ठीक उसी प्रकार चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले सियासी दलों को भी निर्धारित सीमाओं के अलावा कुछ नए नियम में कसने की आवश्यकता है। इसमें चुनाव पूर्व गठबंधन को एक दल का रूप मानना जरूरी कर देना चाहिए। इससे मतदाताओं में न तो असंतोष पैदा होगा और न ही लोकतंत्र को नए खतरे का सामना करना पड़ेगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जो चुनाव से पहले गठबंधन में हो, बहुमत भी मिला हो और हित साधने की फिराक में उससे अलग हुआ हो। महाराष्ट्र इस मामले में शायद पहला राज्य है।

गठबंधन की सरकारें देश के लिए बुरी हैं या अच्छी, इस पर एकतरफा राय नहीं दी जा सकती, पर यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि विचारधाराओं के साथ सौदेबाजी एक सीमा के बाद कोई भी दल नहीं करता, चाहे चुनाव के पहले का गठबंधन हो या बाद का। कमोबेश यह उदाहरण देखने को मिला है। दो टूक यह भी है कि अटूट तो नहीं, पर काफी हद तक भरोसा चुनाव पूर्व गठबंधन पर अधिक कहा जा सकता है।

15 दिसंबर से 15 फरवरी तक के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर कार की स्पीड लिमिट 80 किमी प्रति घंटे अधिकतम रखनी होगी। वहीं, बड़े वाहनों के लिए अधिकतम लिमिट 60 किमी प्रति घंटा तक की गई है। ये कदम कोहरे में हादसे की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 7 दिसंबर 2019

'सेवा' ने फैलाया लाखों गरीब महिलाओं के जीवन में उजाला

- सेल्फ एम्प्लाइड वुमन एसोसिएशन के सेवा कार्य का विस्तार सात राज्यों के 25 लाख परिवारों तक
- गुजरात, राजस्थान, मप्र, बिहार, झारखंड, दिल्ली और ओडिशा में डेढ़ लाख ब्लॉक कार्यकर्ता बदल रहे गरीब परिवारों जीवन

गुजरात की सेल्फ एम्प्लॉइड वुमन ऐसोसिएशन और महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट की सहायिकाओं संग इला भट्ट (मध्य में)। सौ. सेवा ट्रस्ट

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

गुजरात से शुरू हुए सेल्फ एम्प्लाइड वुमन एसोसिएशन और फिर इसके सहायक संगठन महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट ने हालही रजत जयंती मनाई है। एसोसिएशन के डेढ़ लाख ब्लॉक कार्यकर्ता आज गुजरात सहित सात राज्यों के करीब 25 लाख गरीब परिवारों को मदद पहुंचा चुके हैं। इनका दायरा राजस्थान, मप्र, बिहार, झारखंड, दिल्ली और ओडिशा तक ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश तक है, जहां ये महिलाओं को सशक्त बना गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने में सफल हो रहे हैं।

गरीबी उन्मूलन

गांधीवादी विचारक एवं सामाजिक कार्यकता इलाबेन भट्ट ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, जो आज भी बागडोर संभाल रहीं हैं। स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के इनके आंकडों की बानगी आज 25 लाख से अधिक परिवार दे रहे हैं। 18 हजार बेघर महिलाओं को आवास भी इसमें शामिल है। करीब 900 स्लम विस्तारों का सेटलमेंट कराकर गंदी झोपड़पट्टी में रहने वालों परिवारों को आवासीय फ्लैट व घर उपलब्ध मुहैया हो चुका है। संस्था की ऑपरेशनल हैड बीजल भट्ट के अनुसार 15 लाख 60 हजार महिलाओं को संस्था निजी रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा चुकी है। करीब साढ़े तीन हजार कंस्ट्रक्शन वर्कर संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से 11 हजार नए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट ऐसी महिलाओं को सरकारी व अन्य मदद से घर उपलब्ध कराती है। पहले से बसी बस्ती में शौचालय, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं को पहुंचाने में भी सरकारों के साथ सामंजस्य से बदलाव लाने का काम किया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है।

संस्था के कम्युनिटी एक्शन ग्रुप की सदस्य प्रीतिबेन कांबले बताती हैं कि अशिक्षा और गरीबी के चलते ऐसे अनेक परिवार हताशा में जीवन बिताते हैं, हम उन्हें सशक्त बनने की राह दिखाते हैं और इसमें हरसंभव सहयोग भी। ट्रस्ट की एक प्रशिक्षित ब्लॉक अधिकारी गीता बेन ने बताया, अहमदाबाद में एक गरीब बस्ती में बसे सौ से अधिक परिवारों को शांतिदीप हाउसिंग सोसायटी तैयार कराकर सौंपी गई, ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

इलाबेन मुंबई की एसएनडीटी कॉलेज में शिक्षिका थीं, जिसके बाद अहमदाबाद में वकालत शुरू की। इस दौरान ही उनहें टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया और इस संस्था को उन्होंने देश का सबसे बड़ा लेबर यूनियन बना दिया। इलाबेन को वर्ष 1984 में पद्मश्री से और 1985 में पद्मभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा रेमन मेग्सेसे अवार्ड, इंटरनेशनल लाइवलीहुड अवार्ड व इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। एसोसिएशन से सेवा महिला बैंक, लोक स्वास्थ्य, हाउसिंग, सेवाभारत, सेवा निर्माण सहित करीब दो दर्जन संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में इलाबेन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ की वाइस चांसलर हैं और एसोसिएशन का संचालन कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि एसोसिएशन और इससे जुड़ी संस्थाएं महानगर पालिका, नगर निगम और कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, एचएसबीसी, युनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, जॉर्जिया तकनीकी संस्थान, मिलेनियम एलायंस, ऑक फाउंडेशन, एशियन कॉलिशन हाउसिंग राइट, अर्बलैब शिकागो आदि संस्थाओं से इसे सीएसआर के तहत आर्थिक व तकनीकी मदद मिलती है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

नो ब्रोकर! अदद कमरे की तलाश में शुरू किया स्टार्टअप

जागरण विशेष

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

- दो आइआइटीयन, मेरठ के सौरभ गर्ग और हापुड़ के अमित अग्रवाल की सफलता की कहानी
- किराये के कमरे की तलाश में बिचौलियों ने किया परेशान तो शुरू कर दिया खुद का स्टार्टअप
- महानगरों में उपलब्ध करा रहे सुविधा, नहीं लेते कोई कमीशन, पांच साल में जुटाया 850 करोड़ का निवेश

अमित अग्रवाल (बाएं) और सौरभ गर्ग। सौजन्य : अमित

दो आइआइटीयन मेरठ के सौरभ गर्ग और हापुड़ के अमित अग्रवाल का बिजनेस आइडिया कम समय में ही 850 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश जुटा चुका है। इनका स्टार्टअप 'नो ब्रोकर' महानगरों में उन लोगों के लिए मददगार बना है, जो किराए का कमरा, मकान, दुकान, ऑफिस के लिए बिचौलियों के चक्कर काट कर थक जाते हैं। उन्हें यह सरल, सुरक्षित और बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है। सबसे बड़ी बात, बिना कमीशन लिए।

किराए के कमरे की तलाश में सौरभ और अमित को भी अन्य छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं की तरह बिचौलियों (ब्रोकर) के चक्कर लगाने पड़े थे। कमीशन पर भी भारी भरकम खर्च करना पड़ता था। सौरभ बताते हैं, तब हमने सोचा कि क्यों न इसी विषय में बिजनेस की संभावना खोजी जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि महानगरों में पहुंचे बाहरी छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को किराए के कमरे की तलाश में बिचौलियों के चक्कर में न पड़ना पड़े।

अमित कहते हैं, महानगरों में रेंट और प्रॉपर्टी एजेंट्स की भरमार है, लेकिन इनमें से अनेक इस विधा के आदर्श तौर-तरीकों को अमल में नहीं लाते हैं। कमीशन भी इतना, कि जेब ढीली हो जाए। वहीं, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, रजिस्ट्री आदि के लिए भी भटकना पड़ता है। इसका भी भारी चार्ज वसूलते हैं। लिहाजा, हमने सर्वे किया। पाया कि महानगरों में इस काम का बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा सुव्यवस्थित नहीं है। यहां से हमें अपना बिजनेस फार्मूला मिल गया।

सौरभ उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं और आइआइटी मुंबई से पढ़ाई की है, जबकि अमित अग्रवाल हापुड़ से हैं और आइआइटी कानपुर से उन्होंने पढ़ाई की है। इनके साथ ही एक अन्य दोस्त निखिल भी जुड़े। आइआइटी के बाद सौरभ, अमित और निखिल आइआइएम अहमदाबाद में मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान मिले और दोस्त बने। इसके बाद नौकरी के सिलसिले में अलग-अलग जब एक शहर से दूसरे शहर गए तो किराए के कमरे की तलाश में वही परेशानी रही।

आखिरकार, जमा किए कुछ पैसों से तीनों ने मिलकर वर्ष 2014 में अपना यह स्टार्टअप शुरू किया। बेंगलुरु प्रयोग स्थल बना। यहां से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद मुंबई, चेन्नई और पुणे तक विस्तार किया। अब दिल्ली-एनसीआर में भी उन्हें अच्छा अनुभव हो रहा है।

अमित अग्रवाल बताते हैं कि उनके स्टार्टअप नोब्रोकर.कॉम ने बिचौलियों की जरूरत को खत्म कर दिया है। एपबेस्ड इस प्लेटफार्म पर या तो किराया पर कमरा देने वाले मकान मालिक हैं या कमरे की तलाश करने वाले लोग। दोनों से कोई कमीशन नहीं लिया जाता है, लिहाजा यूजर्स की संख्या हजारों पहुंच गई है। उपयोगकर्ताओं की यही विशाल संख्या इन्हें बड़ा बिजनेस दिलाती है। अमित ने बताया, हम दोनों ओर से कोई कमीशन नहीं लेते हैं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, रजिस्ट्री और लोन दिलाने जैसे सहायक कामों के जरिये हमें इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, बैंक, लॉ फर्म जैसे सेवाप्रदाताओं से थोक बिजनेस देने के बदले मोटा कमीशन मिल जाता है।

इन दोस्तों ने बताया कि इनके स्टार्टअप को अब तक विदेशी कंपनियों से 850 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्राप्त हो चुका है। स्टार्टअप को मिल रहे बिजनेस और मुनाफे को देखते हुए अन्य बड़ी कंपनियां भी निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं। छह बड़े शहरों में सफलता के बाद अब अब एनसीआर के शहरों गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद सहित बी-ग्रेड के अन्य शहरों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

राजपथ पर दिखेगी कुल्लू दशहरा उत्सव की झांकी

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

> रक्षा मंत्रालय ने दो चरणों की प्रक्रिया में हिमाचल भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदर्शित कुल्लू दशहरा उत्सव की जात्र (शोभायात्रा) की झांकी को मंजूरी दी है। अब इसका मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा।
> **-राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग**

गणतंत्र दिवस पर इस बार दिल्ली के राजपथ पर अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की जात्र (शोभायात्रा) पर आधारित झांकी हिमाचली संस्कृति की झलक पेश करेगी। रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल की झांकी को मंजूरी दे दी है। इसमें रघुनाथ जी के रथ के साथ दशहरा उत्सव में शिरकत करने वाले देवताओं और परंपरागत वाद्ययंत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा।

हिमाचल भाषा कला एवं संस्कृति विभाग अब अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव पर प्रस्तुत डिजाइन के आधार पर मॉडल तैयार कर 12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय के समक्ष पेश करेगा। 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने झांकी का डिजाइन दिया था। इनमें से सात की झांकी को अस्वीकार कर दिया है। 20 केंद्रीय मंत्रालयों में से सात के डिजाइन को ही मंजूरी मिली।

हिमाचल भाषा कला एवं संस्कृति विभाग ने गणतंत्र दिवस के लिए तीन झांकियों कुल्लू दशहरा उत्सव, मंडी शिवरात्रि और पहाड़ी चित्रकला के डिजाइन रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखे थे।

अब तक चार बार दिखी है हिमाचली झांकी : राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 2007 से लेकर अभी तक चार बार ही हिमाचल की झांकी शामिल हो सकी है। 2019 में हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग ने महात्मा गांधी की हिमाचल यात्राओं पर आधारित झांकी का मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया था।

30 लोग हो सकते हैं शामिल : झांकी में 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसमें ट्रैक्टर व ट्रॉली पर दस लोग जबकि बीस लोग पैदल हो सकेंगे। रघुनाथ जी के रथ को खींचने के अलावा तीन देवता के रथ भी शामिल होंगे। जो मॉडल पेश किया जाएगा, उसमें करनाल, रणसिंघे, ढोल और नगाड़े पेश किए जाएंगे। देव संस्कृति के महासंगम कुल्लू दशहरा का आयोजन दशहरा के बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय महोत्सव सात दिन तक चलता है। इसमें हिमाचली लोक संस्कृति व परंपरा देखने के लिए देश-विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं।

इंदौर ने 20 माह में 1.70 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड वातावरण में घुलने से रोकी

नईदुनिया, इंदौर

- अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था ने इंदौर का प्रोजेक्ट किया रजिस्टर्ड
- कार्बन क्रेडिट बेचकर निगम को एक से दो करोड़ तक हो सकती है कमाई

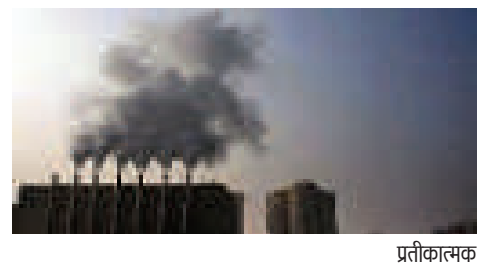

प्रतीकात्मक

देश के सबसे साफ शहर मप्र के इंदौर की आबोहवा को भी उतना ही स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इंदौर ने कंपोस्ट और बायोमिथनाइजेशन प्लांट लगाकर 20 माह में 1.70 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड वातावरण में घुलने से रोकी है। सोलर प्लांट लगने के बाद करीब 3.50 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड वातावरण में घुलने से रोकी जा सकेगी।

स्पेन की अधिकृत ऑडिटर कंपनी एप्पलुएस की रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए अधिकृत अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था वॉल्यूंट्री कार्बन स्टैंडर्ड (वीसीएस) ने मंजूरी के बाद इसे रजिस्टर्ड कर लिया है। इसके आधार पर इंदौर नगर निगम भविष्य में कार्बन क्रेडिट का दावा पेश कर सकेगा।

कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने में इंदौर के चार प्लांट ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित कंपोस्ट प्लांट, चोइथराम, रीजनल पार्क और कबीटखेड़ी स्थित बायोमिथनाइजेशन प्लांट शामिल हैं। इन सभी जगह कचरा प्रोसेस कर खाद या बायो सीएनजी गैस बनाई जा रही है। इससे कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन कितना कम हुआ है, इसके लिए अक्टूबर-17 से जून-19 तक ऑडिट कराया गया तो पाया कि 1.70 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड कम घुली है।

नगर निगम द्वारा इस काम के लिए नियुक्त कंसल्टिंग कंपनी ईकेआई एनर्जी सर्विसेस लि. के डायरेक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि गीले कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस में सामान्य से 24 गुना ज्यादा कार्बन कंपोनेंट होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इंदौर में प्लांट लगने से जो प्रदूषण फैल रहा था, वह कम हुआ। अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इसकी गणना के बाद शहर को कार्बन क्रेडिट मिल सकते हैं। ईकेआई ने आठ महीने पहले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, जिसकी रिपोर्ट स्पेन की एप्पलुएस ने अमेरिका की वीसीएस संस्था को पेश कर दी है। ईकेआई से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया है, जिसने माना है कि इंदौर ने 2017 से 2019 तक 1.70 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड को वातावरण में घुलने से रोका है। ट्रेडिंग की मंजूरी मिली तो इंदौर सालाना एक से दो करोड़ रुपये तक कमा सकता है।

> इंदौर एशिया का पहला शहर है जिसने कंपोस्ट और बायोमिथनाइजेशन के जरिये न केवल प्रदूषण कम किया है, बल्कि इसके लिए उसे कार्बन क्रेडिट भी मिलेंगे।
> **-आशीष सिंह, निगमायुक्त इंदौर**

फटने से पूर्व ही 'टाइम बम' ढूंढ़ लेंगे खोजी कैमरे

राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी

- फेस डिटेक्टर के बाद स्टेशनों की सुरक्षा में रेलवे का बड़ा कदम

प्रतीकात्मक

अब खुफिया कैमरे फटने से पूर्व 'टाइम बम' को ढूंढ़ निकालेंगे। स्पेशल सिक्योरिटी प्लान के तहत रेलवे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर शीघ्र सेंसरयुक्त कैमरे लगाने जा रहा है। फेस डिटेक्टर कैमरे के बाद आरपीएफ के इस कदम को यात्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूं काम करेगा सेंसरयुक्त कैमरा : कैमरा सेंसरयुक्त होगा। इसकी खासियत एक स्थान पर पांच से 10 मिनट तक पड़े किसी संदिग्ध सामान को ढूंढने एवं अलर्ट जारी करने की होगी। कंट्रोल रूम और एजेंसियों के पास बचाव करते हुए ऑपरेशन के लिए समय रहेगा। ऐसे में घटनाओं की आशंका कम रहेगी।

यात्रियों को होगा दोहरा लाभ : रेलवे स्टेशनों पर सेंसरयुक्त कैमरा लगाने की योजना जमीन पर उतरी तो दोहरा लाभ यात्रियों को होगा। कैमरा एक स्थान पर लावारिस पड़ी अटैची, बैग, कुकर इत्यादि के बारे में अलर्ट जारी करेगा। पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी कि संदिग्ध सामान आखिर में क्या है? किसी का सामान छूटा है तो मिल जाएगा।

कैंट स्टेशन पर हुआ था ब्लास्ट : वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में सात मार्च को विस्फोट हुआ था। उस घटना में 11 लोगों की जान गई थी। उस समय स्टेशन पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं थे। 12 वर्षों बाद फेस डिटेक्टर लगने जा रहे हैं। सेंसर कैमरे भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में आपराधिक घटनाएं रोकी जा सकेंगी।

> रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सेंसरयुक्त कैमरे लगाए जाने हैं। फेस डिटेक्टर लगाने का काम शुरू हो गया है, उसका दूसरा चरण टाइम सेंसर खुफिया कैमरों के लगाने का है।
> **-अरुण कुमार, महानिदेशक, आरपीएफ**

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

गोडसे पर अक्षय की वायरल हो रही पोस्ट फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

विश्वास न्यूज, एजेंसी: सोशल मीडिया पर नाथूराम राम गोडसे को लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में अक्षय कुमार गोडसे के अंतिम बयान को इतिहास की किताब में जोड़े जाने की वकालत कर रहे हैं। विश्वास न्यूज की टीम की पड़ताल में यह बयान फर्जी साबित होता है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने पड़ताल में पाया कि जिस ट्विटर हैंडल **(@kumarakshay_v)** से किए गए ट्वीट में गोडसे के बारे में लिखा हुआ है, ट्विटर की तरफ से इस हैंडल को सस्पेंड किया जा चुका है। अक्षय कुमार का वास्तविक ट्विटर हैंडल **@akshaykumar** के नाम से है और उन्होंने गोडसे के नाम से कोई भी ट्वीट नहीं किया है।

दैनिक जागरण के एडिटर (एंटरटेनमेंट) पराग छापेकर ने बताया कि सामान्य यूजर्स वेरिफाइड और अनवेरिफाइड हैंडल के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं और आम तौर पर फर्जी खबर फैलाने वाले अभिनेताओं के नाम में थोड़ा फेरबदल कर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और फर्जी खबर फैलाना शुरू कर देते हैं। यह पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार के नाम से फर्जी खबर वायरल हुई हो। इससे पहले भी राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपये का चंदा दिए जाने के दावे के साथ फर्जी खबर वायरल हुई थी, जिसकी पड़ताल विश्वास न्यूज ने की थी।

क्या है वायरल पोस्ट में?

फेसबुक यूजर **Antu Tiwari** द्वारा 'सुविचार जो आपका जीवन बदल देंगे' नाम के ग्रुप पर साझा की गई इस पोस्ट में लिखा है, 'मैं यह नहीं कह रहा है कि गोडसे द्वारा गांधी की हत्या करना सही है या गलत था पर इतना जरूर कहूंगा कि इतिहास की किताबों में गोडसे को गांधी का हत्यारा पढ़ाने के साथ-साथ गोडसे का अंतिम बयान भी पढ़ाओ कि उसने आखिर गांधी की हत्या क्यों की थी? बाकी सही गलत का फैसला भावी पीढ़ी अपने आप कर लेगी?' पड़ताल किए जाने तक इस पोस्ट को करीब 80 से अधिक लोग शेयर कर चुके हैं।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें: 9205 270 923

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल

- गंगा प्रदूषण मामले की सुनवाई अब तीन जनवरी को
- एसटीपी के शोधित पानी की गुणवत्ता परखेगी विशेषज्ञ समिति

लंबे अरसे के बाद गंगा प्रदूषण को लेकर बैठी इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने केंद्र सरकार से नमामि गंगे प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि जितने भी एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित किए गए हैं, वे ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं? उनकी क्या स्थिति है? गंगा में नाले का गंदा पानी सीधे कैसे जा रहा है? उन्हें रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया है? साथ ही गंगा में न्यूनतम जल प्रवाह रखने की क्या योजना है? याचिका की अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। गंगा प्रदूषण मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई पूर्णपीठ कर रही है।

प्रयागराज व कानपुर में गिर रहे नाले : न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए न्यूनतम 50 फीसदी पानी बनाए रखने की जरूरत है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से कार्य योजना की जानकारी मांगी थी, किंतु केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। राज्य सरकार से भी गंगा में गिर रहे नालों और एसटीपी के संचालन के संबंध में जवाबी हलफनामा मांगे गए थे। उसका भी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। गंगा में एसटीपी से शुद्ध हुए पानी में बायोकेमिकल पॉलीफॉर्म गंगा जल में मिलकर प्रदूषण फैला रहा है। ट्रीटमेंट के बाद पानी को गंगा में न गिराकर अन्यत्र ले जाया जाए। प्रयागराज में छह एसटीपी हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे। 83 नालों में से 43 नाले सीधे गंगा में गिर रहे हैं। कानपुर में चर्म उद्योगों के स्थानांतरित करने के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चर्म उद्योगों का गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। गुप्ता का कहना था कि ट्रीटमेंट के बाद भी पानी गंगा में प्रदूषण बढ़ाने का कारण है। इस पर कोर्ट ने उनसे विशेषज्ञों की सूची मांगी, जो जांच करेंगे कि गंगा में जा रहा ट्रीटमेंट वाला पानी क्या प्रदूषित है और उसे अन्य उपयोग में लाया जा सकता है? इस पर गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने प्रदूषित शोधित पानी को गंगा के उस पार अन्य कार्यों में लिए जाने का योजना तैयार करने को कहा था, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

कानपुर में आचमन के लायक भी नहीं हैं गंगा, क्या करेंगे प्रधानमंत्री!

कानपुर से लाइव : पोल-खोल पार्ट-3

जागरण संवाददाता, कानपुर

- कानपुर के लोगों की मानें तो यहां आचमन प्रधानमंत्री के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं
- अटल घाट गंगा बैराज से सिद्धनाथ घाट तक जा सकते हैं मोदी
- कानपुर में मार्च 2020 तक के लिए बनाई गई योजना में नहीं शामिल हुए एक दर्जन से अधिक नाले, 'बंद' हो चुके कुछ नाले अब भी गिर रहे गंगा में

नमामि गंगे समीक्षा की... जागरण पड़ताल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच राज्यों में चल रही महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के कामों की समीक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 दिसंबर को करेंगे। यह परियोजना उनके दिल के करीब है। परियोजना लंबी चलनी है, लेकिन अब तक जो हुआ, वह उम्मीद नहीं जगा रहा। इसीलिए कानपुर से यह पोल-खोल पड़ताल हमने शुरू की है, जो एक-एक कर गंगा पट्टी के अन्य शहरों तक जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित जनता को नमामि गंगे की प्रगति से अवगत कराया जा सके। 14 को समीक्षा कर प्रधानमंत्री खुद भी देश को अवगत कराएंगे।

चर्चा है कि 14 दिसंबर को पीएम गंगा सम्मेलन और समीक्षा बैठक में भाग लेने कानपुर पहुंचेंगे तो गंगा का नौका (स्टीमर) से भ्रमण कर गंगाजल से आचमन भी करेंगे...। इधर, कानपुर के लोगों और संतों की मानें तो यहां गंगा में आचमन प्रधानमंत्री के लिए किसी चैलेंज से कम न होगा, क्योंकि गंगा मैया में इतना मैल भर चुका है कि गंगाजल आचमन के लायक भी नहीं रहा है।

खामियों से भरी कार्ययोजना, भुगत रहीं गंगा : दैनिक जागरण ने शुक्रवार को जब नमामि गंगे योजना के तहत हुए कार्यों की पड़ताल अटल घाट से शुरू की तो पता चला कि पतित पावनी गंगा अधूरी कार्ययोजना का शिकार हो गईं। योजना में छह नाले टैप किए गए फिर भी गंगा की गोद में जहर जा रहा है। कागजों में बंद टेनरियां भी लाखों लीटर दूषित पानी उगल रही हैं। जल निगम ने वर्ष 2017 में नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता की कार्य योजना तैयार की। नाला टैपिंग के साथ गंगा से जुड़े 34 वार्डों में 370 करोड़ रुपये से सीवर लाइन की सफाई, मरम्मत और नई सीवर लाइन डालने का काम चरणबद्ध तरीके से मार्च 2020 तक पूरा करना था। गंगा में छोटे-बड़े दो दर्जन नाले गिरते हैं, लेकिन योजना में छह नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने की योजना बनी। इसमें भी चार नाले ही बंद हुए। पड़ताल में सामने आया कि परमिया नाला, डबका नाला, रानीघाट नाला, गोलाघाट नाला, सीताबाजार नाला, बुधियाघाट नाला, वाजिदपुर नाला, मैगजीनघाट नाला, तिवारी घाट नाला, सत्तीचौरा आदि नाले सभी सीधे गंगा में गिर रहे हैं।

नई योजना भी आधी अधूरी : पहली कार्ययोजना में छूटे नाले बंद करने के लिए दूसरी कार्ययोजना बन रही है। इनसे करीब 80 एमएलडी (मिलियंस ऑफ लीटर पर डे) प्रदूषित पानी गंगा में सीधे जा रहा है। इसमें गोलाघाट, सत्ती चौरा, गोलाघाट, सीता बाजार, बुधियाघाट और वाजिदपुर नाले की टैपिंग शामिल की गई है। लेकिन रानीघाट, सरसैया घाट, मैगजीन घाट, तिवारी घाट समेत छोटे-बड़े एक दर्जन से अधिक नाले गंगा में गिरते रहेंगे। इनसे 15 एमएलडी से अधिक प्रदूषित पानी रोज गंगा में गिरता है। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते जलनिगम और नगर निगम तेजी से काम कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम गुणवत्ता के दरकिनार होने के रूप में आ सकता है।

कानपुर के अटल घाट के समीप स्थित परमिया नाले से गंगा नदी में जाता दूषित पानी। यह नाला बंद हो चुके छह नालों की कार्ययोजना में शामिल था। जागरण

> बचे नालों को मोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसमें छावनी के नाले गोला घाट और सत्तीचौरा समेत गंगा में सभी तरह से दूषित पानी को रोका जाएगा।
> **-एसके कंछल, महाप्रबंधक जल निगम**

...तो दिख जाएगा गंगा से हुआ छल

प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अटल घाट गंगा बैराज से सिद्धनाथ घाट तक जा सकते हैं। वह यहां आचमन भी करेंगे। पीएम यहां से चंद किलोमीटर आगे डबकेश्वर मंदिर तक आ जाएं तो योजना का सच दिखेगा। हमारी पड़ताल में डबका नाले का हाल सबसे बुरा मिला। बड़े पैमाने पर सीवर का पानी गंगा में जाता दिखा। लोगों ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री यहां आकर आचमन करेंगे...।

> बस्तियों में एकल शौचालय बनाए जा रहे है। खुले में शौच न जाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। जल निगम के साथ भी बैठक कर नालों को बंद करने की कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा।
> **-अक्षय त्रिपाठी, नगर आयुक्त**

> गंगा में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं पहले रोज गंगा स्नान करता था, लेकिन अब स्थिति नहीं रही। नाले और सीवर का पानी गंगा को बदहाल कर रहा है।
> **-बालयोगी अरुण चैतन्यपुरी, महंत हनुमत कृपा आश्रम, सिद्धनाथ घाट**

पानी बढ़ेगा तो नाला नहीं दिखेगा

छह बंद नालों में एक परमिया नाला भी है। यहां मौजूद मसवाननगर निवासी शिवकुमार, मूलचंद और बबलू ने बताया कि यह नाला अभी तक बंद नहीं किया गया है। इससे गंदगी आ रही है। गंगा में पानी बढ़ेगा तो यह नाला दिखना बंद हो जाएगा। रानीघाट में दुर्गंध के मारे खड़ा होना दुश्वार था। यहां गोल्डीपाल, जयसिंह, राजू निषाद आदि ने बताया कि शौचालय नहीं था। अब यहां शौचालय बनना शुरू हुआ है। नाले की गंदगी गंगा में ही जा रही है। इन लोगों ने एकस्वर में कहा कि प्रधानमंत्री हमसे मिलें, हम उन्हें गंगा का हाल बताएंगे...।

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 7 दिसंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

इतिहास की चौखट पर वर्तमान के कदम

ये जो बुलंद दीवारें देख रहे हो। और आज भी अटल सी डटी छत है न किसी साधारण सीमेंट और ईंटों से इसकी चिनाई नहीं हुई है। दही, उड़द की दाल का पेस्ट, मेथी पाउडर, बेल फल का गुदा, गुग्गुल का घोल, चूने का प्लास्टर...यह सब मिलाकर हवेली की दर-ओ-दीवारों का निर्माण होता है। जिन हवेलियों की चौखट पर कदम पड़ते ही एक अलग नायाब धरोहर की अनुभूति होती है। ऐसी ही हवेली के सौंदर्य स्वरूप से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

देवकी नंदन की हवेली...पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों से बिजली के तारों के जंजाल की उलझनों से निकलते हुए जब देवकी नंदन की हवेली में कदम पड़ते हैं तो बाहर की सारी किचकिच और जाम-झाम सेकंड भर में भूल जाते हैं। चौखट के भीतर कदम पड़ते ही आपके सामने कुछ ऐसी नायाब दुनिया होती है।
-सभी फोटो, सौजन्य : देवकी नंदन, हवेली मालिक

धरोहर

आज हम पुरानी नायाब चीजों की कितनी शिद्दत से तलाश करते रहते हैं न। जहां कहीं कुछ छिटपुट चीजें दिखती हैं तो उन्हें सहेज लेना चाहते हैं। हमारे लिए अनमोल बन जाती हैं लेकिन काश यदि वक्त के साथ-साथ उन धरोहरों की अहमियत को समझा होता उनके संरक्षण पर ध्यान दिया होता तो आज भी हमारी पुरानी दिल्ली वास्तु की...नक्काशी की धनी होती। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में जगह-जगह लटके बिजली के तार झंझावत बना लिए। इन्हीं तारों की ओट में कहीं छिपे नजर आते हैं कुछ ऐतिहासिक द्वार। जहां कभी हवेलियां होती थीं। लोग बसते थे, इतिहास रचता था। कुछ एक हवेलियां हैं जो आज भी जीवंत रूप में अपने उसी दौर का परिचय दे रही हैं। और इंटैक समेत नगर निगम इनके संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहा है लेकिन इससे कहीं आगे बढ़कर हवेली मालिक भी कोशिश कर रहे हैं।

गुड़, उड़द की दाल से हुई चिनाई : कश्मीरी गेट में छत्ता बाजार में रामलाल की हवेली स्थित है। इसकी शानो शौकत आज भी लोगों को लुभाती है। देवकी नंदन कहते हैं कि यह हवेली के पिता के नाना स्नेही राम खेमका ने 1893 में खरीदी थी। यह किसी नवाब की हवेली थी। इसका वास्तु बहुत ही खास है। बकौल देवकी हमने जब इसके संरक्षण की प्रक्रिया शुरू की तो उस दौरान 6 फीट तक खोदाई की थी। हवेली का पिछला हिस्सा 1840 के पहले का है। पीछे लखोरी, छोटे पैटर्न की ईंटें मिलीं। और एक पतली गली भी है, जिसमें कुछ दूरी पर बकरुद्दीन की कब्र है। ऐसा कहा जाता है कि ये हुमायूं के गुरु थे। जब इनका निधन हुआ था तो हुमायूं खुद यहां मिट्टी डालने आया था। मुगल आर्किटेक्ट में बनी हवेली में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास है। महिलाओं, पुरुषों के लिए अलग-अलग भव्य कमरे हैं। हवेली निवासियों ने आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया था। दरअसल, स्नेही राम खेमका की पौत्रवधू ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। अरुणा आसफ अली ब्रितानिया पुलिस से छिपने के लिए अक्सर हवेली में आती थीं। वे हवेली के पहले तल पर छिपती थीं और यहीं से आंदोलनों की रूपरेखा तय करती थीं। हवेली 1,100 गज में फैली है। इसमें 40 से अधिक कमरे हैं। बकौल देवली हवेली के संरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें अन्य सामग्रियों के साथ घरेलू सामानों जैसे की गुड़, उड़द की दाल, मेथी पाउडर और चूने के प्लास्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

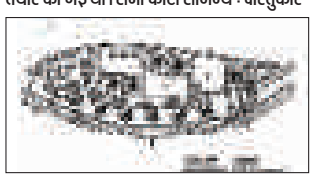

हवेली के भीतर कमरों की साज-सज्जा भी नवाबी अंदाज में नजर आती है।

भारत और इटली आए साथ

हवेलियों के संरक्षण के लिए भारत और इटली साथ आए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-इतावली द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत प्रयोगशाला से संरक्षण स्थल तक का आयोजन इसी कड़ी का हिस्सा है। जिसमें हवेलियों की बनावट का अध्ययन कर संरक्षण किया जा रहा है। पदाधिकारी बताते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इंडिया-इटली द्विपक्षीय अनुसंधान कार्यक्रम के तहत शाहजहांनाबाद की हवेलियों के संरक्षण के लिए एक हैंडबुक भी तैयार किया गया है। जिसका मकसद निवासियों को कुछ व्यवहारिक तरीकों और तकनीकों से परिचित कराना है जो उन्हें अधिक कुशल, आसान और किफायती मरम्मत, संरक्षण के लिए प्रेरित कर सके। पदाधिकारियों की मानें तो हवेलियों के अध्ययन में पता चला कि इनकी संरचना में लखोरी ईंटों और चूने की दीवारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पीरियड ईंटे हैं। जिनमें चूना मोर्टार है। चूना या मिट्टी के मोर्टार के साथ पत्थर कुछ ऐतिहासिक इमारतों में भी पाए गए हैं। इनका उपयोग नींव के लिए तो ज्यादातर किया ही जाता है साथ ही इमारत के निचली मंजिल का भी निर्माण इसी से किया जाता है। इन दीवारों की मोटाई पर्याप्त होती थी, जिसकी वजह से दिल्ली की मिश्रित जलवायु में स्थिरता और थर्मल आराम मिलता था। हवेलियों की दीवारों के आंतरिक और बाहरी हिस्से पर पारंपरिक चूने के प्लास्टर की परतों के साथ ईंट और रेत जैसे अकार्बनिक के साथ प्लास्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। इस चूने के प्लास्टर को कुशल कारीगरों द्वारा आयरिश प्लास्टर के अंतिम कोट के साथ पालिश कर दिया जाता था। पारंपरिक चूने के प्लास्टर का प्रयोग सजावट के लिए भी होता था। दरअसल, यह चूना प्लास्टर की परत सफाई के लिए आसान होती थी। यह पानी और नमी से भी प्रभावित नहीं होता। दही, उड़द की दाल का पेस्ट, बेल फल का गुदा, गुग्गुल के घोल को चूने के प्लास्टर, मोर्टार और छत की टेरेस में मिलाया गया था। हवेलियों की एक खासियत भव्य प्रवेश द्वार भी रहे हैं। इन द्वार में मेहराब, सजावटी पैनल होते थे। इन चौखट की चिनाई में अक्सर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। हवेलियों की ऊपरी मंजिल पर बालकनी, जो सैंडस्टोन ब्रैकेट्स की मदद से बनाई गई होती थी, लाजवाब थी। लकड़ी के ढांचे और बलुआ पत्थर की मदद से महीन कारीगरी की जाती थी। जबकि फर्श और छतों का निर्माण, बलुआ पत्थर की ईंटों के साथ लकड़ी के बीमों, लोहे के गार्डरों के साथ जैक मेहराबों की मदद से बनाया गया है। बेल के गूदे को हरड़ के साथ जोड़ा जाता था और निर्माण के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता था।

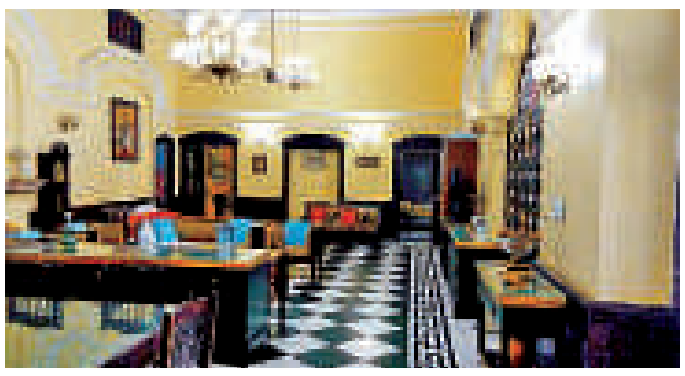

चीकू की हवेली में हुई थी पीके की शूटिंग : चांदनी चौक में कारोबारी राजीव ने अपनी 135 वर्षीय हवेली के संरक्षण का जिम्मा खुद उठाया। हवेली 42 कमरों की है। इसे स्थानीय लोग चीकू की हवेली कहकर बुलाते हैं। बकौल मालिक हम चार कमरों में रहते हैं। हवेली से दिल का नाता है। एक बार हवेली को फिल्म शूट के लिए किराए पर लिया गया था। इसमें राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्म पीके की शूटिंग की थी। बाद में रजत कपूर की आंखो देखी भी यहीं शूट हुई थी। कहते हैं हमने अपनी मेहनत और लगन से हवेली का संरक्षण किया है। वहीं स्थानीय लोगों की मानें तो इस गली में या यूं कहें इलाके में बहुत सी हवेलियां थीं। जिन्हें मदद की दरकार थी। नगर निगम हेरिटेज टैग लगा देता है लेकिन उसके बाद हवेली में छोटा काम कराने के लिए भी निगम के दफ्तरों का चक्कर लगाने पड़ते हैं।

मुशर्रफ का गहरा नाता था नहर वाली हवेली से : कुछ साल पहले पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ जब भारत दौरे पर आए तो उनके भ्रमण के स्थलों में दरियागंज टॉप पर था। दरअसल यहां गोलचा सिनेमा के पास स्थित नहर वाली हवेली से उनका पुराना नाता है। इसी हवेली में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का 11 अगस्त 1943 में जन्म हुआ था। उन्होंने चार साल यहां बिताए। उनके दादा, काजी मोहताशिम-उद-दीन भारत सरकार के साथ राजस्व के डिप्टी कलेक्टर थे। पंजाब के कमिश्नर के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने हवेली खरीदी थी। ऊंची छत, बड़ा आंगन और मेहराबदार दरवाजों में कभी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार के वजीर और मंत्रियों का भी निवास स्थान हुआ करता था। हवेली को बाद में प्रेम चंद गोला ने खरीदा था। किसी समय हवेली 24,800 वर्ग फीट में फैली थी।

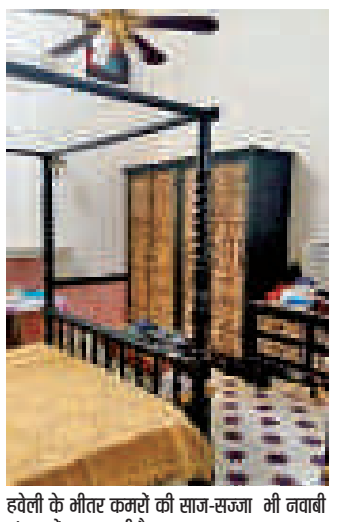

आरके पुरम सेक्टर-13 स्थित फ्लैट्स

हबीब रहमान ने दिया था मल्टी स्टोरी फ्लैट योजना को मूर्त रूप

नायाब वास्तु

राजधानी में बंटवारे के बाद आबादी में तेजी से इजाफा हुआ था। बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से आवासीय संकट बढ़ गया था। वहीं धीरे-धीरे दिल्ली में देश के अन्य राज्यों से नौकरी के लिए भी लोग आने लगे। और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में मल्टी स्टोरी फ्लैट समय की मांग बन गई। आमतौर पर शहर से बाहर इस तरह की इमारत बनाने से आवास से वर्कप्लेस तक परिवहन की दिक्कतें उत्पन्न होने का खतरा होता, इसलिए उन दिनों मल्टी स्टोरी फ्लैट का चलन न के बराबर ही था। साथ ही दो मंजिला आवासीय भवन के लिए कोई तार्किक प्लान या संबंधित भू भाग के समुचित उपयोग का प्लान नहीं होता था। लेकिन समय के साथ जमीन की बढ़ती कीमतों ने प्रशासन के माथे पर बल लाना शुरू कर दिया था कि मल्टी स्टोरी फ्लैट की तरफ रुख करना ही होगा। टाउनशिप के निकट सोसायटी बनानी होंगी। जहां रहने के साथ लोगों को खुला वातावरण, हरियाली और हवादार कमरे मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। मास्टर प्लान में सेंट्रल दिल्ली में आठ मंजिला भवन बनाने का खांका खींचा गया, इसलिए यह किसी के लिए नहीं है कि फैंसी या बहुमंजिला निर्माण को बहाल किया जा रहा है। केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग में कार्यरत प्रसिद्ध वास्तुकार हबीब रहमान ने उस समय मुश्किल से लगने वाली इस परिकल्पना को अमलीजामा पहनाया। आरकेपुरम सेक्टर 13 में 1960 में मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाए, जो दिल्ली के आवासीय समस्या के समाधान में सहायक साबित हुआ। वाई और टी आकार में बने फ्लैट वास्तु का नायाब उदाहरण है।

एमएस फ्लैट का विरोध : मल्टी स्टोरी फ्लैट का विरोध ज्यादा था। लोगों का तर्क था कि इसके मुकाबले दो मंजिला भवन ज्यादा मुफीद हैं। किरायेदार की स्थिति में भी ग्राउंड फ्लोर पर खूबसूरत बगीचा बनाया जा सकता है। बालकनी में भी काफी स्पेस होता है, छत का भी उपयोग किया जा सकता है। एक और बात, जो उस समय लोग कहते थे वो यह कि पानी की आपूर्ति, बिजली, जल निकासी परिवहन आदि जैसी सेवाएं दिल्ली में अभी तक अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई। शहरीकरण कुशल सेवाओं को निर्धारित करता है और इन्हें मास्टर प्लान में परिकल्पित विकास के साथ बनाए रखने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी शहर इनके बिना काम नहीं कर सकता है।

वीआइ फ्लैट : टाइप वीआइ ब्लॉक योजना में फ्लैट 'वाई' आकार के बनाए गए, ताकि प्रत्येक विंग का रेडियल द्विभाजन बेहतर हो और एक ही समय में सभी विंग को लिफ्ट, सीढ़ी आदि की सेवा समुचित तरीके से मिल सके। केंद्रीय कोर में एक प्रवेश द्वार, लिफ्ट्स हैं। सीढ़ी, मीटर कक्ष (भूतल पर) और सभी कमरों में पर्याप्त जगह है। प्रत्येक तल पर सहायकों के लिए भी कमरा है। हर विंग में, एक फ्लैट को स्व-निहित इकाई के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। इंट्रेस लॉबी कमरों में स्टडी रूम और लिविंग रूम दोनों तरफ स्थित हैं। जबकि इसके सामने डाइनिंग रूम है जो लिविंग रूम से सटा है और रसोई से बालकनी के माध्यम से भी जुड़ा है। किचन के पास बने सहायक कमरे का प्रवेश बाहर की तरफ से है। फ्लैट की बालकनी बड़ी कुशलता से ऐसी बनाई गई कि यहां से पूरा आकाश दिखे। वहीं वी ब्लॉक में मल्टी स्टोरी फ्लैट सामान्य लिफ्ट और सीढ़ी द्वारा तीन विंग में टी आकार के बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट के लिए एक कॉम्पैक्ट योजना तैयार की गई है। प्रवेश द्वार की लॉबी में एक तरफ एक अध्ययन कक्ष है, लिविंग रूम और भोजन कक्ष हैं, जिनका उपयोग सामाजिक समारोहों आदि के लिए एक हॉल के रूप में किया जा सकता है। दो बेडरूम लिविंग-डाइनिंग रूम में बालकनी बिल्कुल वाई फ्लैट की माफिक है। इन दोनों के वास्तु को देखें तो पता चलता है कि भूतल के स्तर पर विंग एक प्रवेश द्वार और भवन के नीचे से गुजरते हुए मार्ग प्रदान करता है। ब्लॉक के बीच में बड़ा खुला स्थान है जहां अच्छी हवा और प्रकाश के साथ खुलापन है। ले आउट योजना में टाइप वी क्वार्टर के 6 ब्लॉक और टाइप वीआइ क्वार्टर के 10 ब्लॉक बनाने थे। जिनमें 138 और 230 फलैट बनाने की योजना थी लेकिन भूमि विवाद के कारण वर्तमान में तीन ब्लॉकों का निर्माण नहीं किया जा सका है। नतीजतन, वहां 138 प्रकार वी फ्लैट और 161 प्रकार वीआई फ्लैट है।

वाई और टी आकार में बने फ्लैट की कुछ ऐसी ड्राइंग तैयार की गई थी। सभी फोटो सौजन्य : वास्तुकार

संजीव कुमार मिश्र

फिल्म के बहाने, पानीपत लड़ाई का पुण्य स्मरण

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

कल रिलीज हुई 'पानीपत' शीर्षक वाली हिंदी फिल्म से पानीपत की तीसरी लड़ाई नए सिरे से चर्चा में है। वास्तविक अर्थ में भारतीय इतिहास की धारा को बदलने वाले वर्ष 1761 में हुए पानीपत के युद्ध के प्रति जनसाधारण का उदासीन रवैया इस त्रासदीपूर्ण घटना से अधिक दुखदायी है। ऐसे में इस लड़ाई की पृष्ठ भूमि को जानना बेहतर होगा। वर्ष 1752 में उत्तरी भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जब मराठों ने दोआब में प्रवेश किया और विदेशी अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में। वर्ष 1752 और वर्ष 1761 के बीच का चरण वस्तुतः उत्तरी भारत के स्वामित्व के लिए मराठों और अब्दाली के बीच शक्ति परीक्षण का चरण था। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय (1699-1759) के समय में वजीर गाजीउद्दीन ने मराठों को सम्राट की सहायता के लिए दिल्ली बुलवाया था। उस समय के पेशवा ने अपने भाई रघुनाथ राव (राघोबा) को बादशाह की आज्ञा का पालन करने के लिए एक बड़ी सेना सहित दिल्ली भेजा। रघुनाथ राव ने अपनी सेना सहित और आगे बढ़कर अहमदशाह अब्दाली के नायब के हाथों से पंजाब विजय कर लिया और एक मराठा सरदार को दिल्ली बादशाह के अधीन वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किंतु इस अंतिम घटना ने उनके विरुद्ध अब्दाली का क्रोध भड़का दिया और वर्ष 1759 में एक जबरदस्त सेना लेकर वह पंजाब पर फिर से अपना राज कायम करने और मराठे का विध्वंस करने के लिए अफगानिस्तान से निकल पड़ा।

ऐसा जानकर, उसने (पेशवा) अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ को दिल्ली भेजने का निश्चय किया, जिससे वह अब्दाली को देश के बाहर खदेड़ दे। भाऊ लगभग दो लाख आदमी लेकर 14 मार्च को महाराष्ट्र के पतदूर से रवाना हुआ। भाऊ ने अगस्त 1760 को दिल्ली में प्रवेश किया। चंबल पार करने से पूर्व भाऊ ने राजस्थान के सरदारों, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को पत्र लिखे थे कि वे इस लड़ाई को देश की लड़ाई समझकर विदेशी अब्दाली को सिंधु के पार खेदड़ने में उसकी सहायता करें। किंतु मराठों की यह कूटनीति असफल रही।

राजपूत, सिंधिया और होल्कर के अत्याचारों के कारण मराठों के शत्रु हो गए थे, अतः वे तटस्थ रहे। परंतु शुजाउद्दौला दोआब के अपने पड़ोसी रूहेलों को मराठों से अधिक शत्रु मानता था, अतः वह भाऊ का साथ देने के लिए राजी हो गया। जब यह बात अब्दाली को मालूम हुई तो उसने शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में करने के लिए नजीबुद्दौला को लखनऊ भेजा। नजीबुद्दौला ने मेहंदी-घाट स्थान पर नवाब-वजीर से मिलकर उसे स्वार्थ और महजब के नाम पर अब्दाली का साथ देने के लिए राजी कर लिया। शुजाउद्दौला, नजीबुद्दौला के आग्रह से अनूप शहर के खेमे में अब्दाली से मिला और उसने उसका हार्दिक स्वागत किया। मराठों पर एक तो अब्दाली और शुजाउद्दौला के मिल जाने की चोट पड़ी और दूसरी राजा सूरजमल जाट के रूठकर दिल्ली से भरतपुर चले जाने की। कहा जाता है कि सूरजमल ने भाऊ को सलाह दी थी कि वह युद्ध सामग्री, तोपखाना और स्त्रियों को भरतपुर में सुरक्षित छोड़कर मराठों की पुरानी छापामार नीति को अपनाए और अब्दाली की रसद रोक दे हिंदु किंतु भाऊ ने इस सलाह को ठुकराकर खुले मैदान में डटकर लड़ाई लड़ना ही उचित समझा था। अब अब्दाली ने मराठा सेना के चारों ओर गारद बिठाकर दोआब, दिल्ली और राजपूताने से उसके रसद और यातायात को रोक दिया। मराठों के लिए केवल उत्तर का मार्ग खुला रह गया किन्तु अब्दाली ने शीघ्र ही कुंजपुरा पर अधिकार करके मराठों का पंजाब से भी यातायात रोक दिया। इस परिस्थिति के कारण मराठा शिविर पर बड़ा भारी संकट छा गया। भाऊ को न तो कहीं से रसद ही मिल सकी और न वह दो महीने तक पानीपत से दक्खिन को ही कोई समाचार भेज सका। 14 जनवरी 1761 को दिल्ली से करीब 97 किलोमीटर दूर, पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में इनका (अफगान-मराठों) युद्ध हुआ। अब्दाली ने मराठों के रसद-पानी की आपूर्ति के रास्ते रोक दिए और उन्हें खाली पेट लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में मराठों की जान-माल की भारी क्षति हुई। सदाशिव और विश्वास राव, दोनों मैदान में काम आए। विजय अहमदशाह की ओर रही। लड़ाई में रोहिल्लों और अवध के शुजाउद्दौला मुस्लिम शक्तियों का समर्थन उसे (अब्दाली) मिला। एचआर गुप्ता की पुस्तक, 'मराठा एवं पानीपत' के अनुसार, मराठों को लगभग 28,000 सैनिकों का नुकसान हुआ, जिसमें 22,000 मारे गए और बाकी के युद्धबंदी बना लिए गए। शहीद हुए फौजियों में सेना की टुकड़ियों के दो सरदार-भाऊ राव और पेशवा बालाजी राव का बड़ा लड़का विश्वास राव भी थे। इस युद्ध के एकमेव प्रत्यक्षदर्शी शुजाउद्दौला के दीवान काशी राज के विवरण (बाखर) के अनुसार, युद्ध के एक दिन बाद लगभग 40,000 मराठा कैदियों की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई। किंतु अब्दाली को भी अपनी इस विजय की बहुत जबरदस्त कीमत देनी पड़ी। उसके इतने अधिक आदमी लड़ाई में काम आए और घायल हुए कि आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर उसे फौरन अफगानिस्तान लौट आना पड़ा।

'आप की खातिर' हाजिर हैं कबाब

जायका

कनॉट प्लेस का मिडिल सर्किल, खुला आसमान, चारो ओर लाइटों की रंगीन रोशनी और इन सब के बीच चल रहीं सर्द हवाएं। ऐसे में अगर लजीज गरमागरम काकोरी कबाब खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देर किस बात की है आपकी खातिर जुबैर हैं न। नॉनवेज के शौकीनों के लिए दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के मिडिल सर्किल स्थित आपकी खातिर रेस्त्रां डिनर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कपड़े, जूते, बैग इत्यादि की शॉपिंग करते हुए अगर भूख लग जाए तो जुबैर अहमद (पप्पू) के हाथों की ग्रिल्ड काकोरी कबाब खा कर देखें। शॉपिंग की सारी थकान भूल जाएंगे। मटन के कीमे से बनी यह डिश आपको एक तो इंडियन स्वाद देती है तो दूसरी ओर इसमें लखनऊ के खाने का भी आनंद मिलता है।

25 वर्षों से परोस रहे कबाब : जुबैर अहमद कहते हैं कि वह 25 वर्षों से कबाब बना रहे हैं। उन्होंने मुगलई खाना बनाना लखनऊ के उस्ताद मुहम्मद वकील व अपने नाना से सीखा था। उसके बाद उन्होंने निजामुद्दीन मुख्य सड़क के पास उस्ताद के साथ ही काकोरी कबाब बनाने का काम शुरू कर दिया। करीब छह महीने पहले ही जुबैर ने कनॉट प्लेस में अपना काम शुरू किया है। लेकिन उनके हाथों में वह स्वाद है कि कबाब खाने के लिए दिल्ली ही नहीं एनसीआर से भी लोग आते हैं। यहां काकोरी कबाब के अलावा गलौटी कबाब, चिकन मलाई टिक्का, शाही पराठे व मुगलई खाने का ऐसा स्वाद मिलेगा कि आप बार-बार यहां आना चाहेंगे। वेज खाने वालों के लिए भी यहां काफी कुछ खास है।

मुंह में जाते ही घुल जाता है : काकोरी कबाब बनाने के लिए 15 से 20 मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर के अलावा कुछ साबुत मसालों का भी इस्तेमाल होता है। इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स और देसी घी भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसे ग्रिल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को मेहमान की तरह इज्जत दी जाती है, यही वजह है कि रेस्त्रां का नाम आपकी खातिर रखा गया है। कबाब परोसने का तरीका भी बेहद खास है। चाट मसाला, नींबू के छिलके और प्याज के छल्लों के साथ कबाब परोसा जाता है। जो देखने में भी आकर्षक लगता है।

शाही पराठा और सुरमई फिश : शाही पराठा, गलौटी कबाब, चिकन मलाई टिक्का व सुरमई फिश भी परोसा जाता है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। शही पराठा दूध, चीनी, अंडा व इलायची मिलाकर बनाया जाता है। इसे चिकन काठी व कोरमा के साथ परोसा जाता है। यहां का कबाब भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे काकोरी कबाब की तरह ही तैयार किया जाता है लेकिन अंत में स्वाद बदलने के लिए अदरक, नींबू व हरी मिर्च का मिश्रण किया जाता है। सुरमई फिश टिक्का बनाने के लिए फिश को ड्राई फ्रूट्स, दही व मसालों के साथ एक घंटे तक ग्रिल कर के तैयार किया जाता है। जिसके बाद वह बेहद मुलायम हो जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।

क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड सितारे भी हैं दीवाने : जुबैर बताते हैं कि जब वह निजामुद्दीन में थे तो भारतीय व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी कबाब खाने आया करते थे। खासकर कपिल देव और अजय जडेजा अक्सर उनके हाथ की कबाब खाने आते थे। वहीं बॉलीवुड सितारे संजय दत्त, दलेर मेहंदी, फारुख शेख, नंदिता दास, शत्रुघ्न सिन्हा, करिश्मा कपूर भी यहां कबाब खाने आ चुके हैं। शर्मिला टैगोर व मंसूर अली खान भी काकोरी कबाब मंगाया करते थे। इतना ही नहीं, वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के घर पर दो बार डिनर पार्टी में भी अपने हाथ की बनी कबाब परोस चुके हैं।

रितु राणा

आप की खातिर में कबाब ग्रिल करते मुहम्मद इमरान। जागरण

खुलने का समय : शाम छह बजे से रात 12 बजे तक।
नजदीकी मेट्रो स्टेशन : राजीव चौक।

वाह क्या कबाब है खाकर मजा आ गया। जागरण

आज भी ओन्ने की ओट से झांकती हैं महिलाएं

शहर के गांव

शहरी चकाचौंध से दूर एक गांव, जहां के लोग आज भी पुरानी परंपरा, रीति-रिवाज और संस्कृति को जीवंत बनाए हुए है। एक-दूसरे के घरों से सब्जी का आदान-प्रदान हो या सामूहिक समारोह सब कुछ बदस्तूर जारी है। पूर्वी दिल्ली स्थित ऐसा ही एक गांव है चिल्ला। दिल्ली के इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक गांव के पीछे भी एक लंबा इतिहास रहा है। गांव में वर्षों पुरानी चौपाल भी है जिसे पूर्व सासंद महेश गिरी ने नए सिरे से बनवाया था, लेकिन वर्तमान में वह बंद पड़ी है।

आजादी के लिए संघर्ष : दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर न्यू अशोक नगर के पास बसे चिल्ला गांव का इतिहास अपने आप में अनूठा है। गांव के बुजुर्ग चौधरी ब्रह्म सिंह बताते हैं कि गांव को बसे पांच सौ वर्ष से भी अधिक हो गया। इस गांव के लोगों ने देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया था। शहरीकरण के इस दौर में भी यहां के लोग पशुपालन व कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहां ज्यादातर गुर्जर (डेढ़ा) समुदाय के लोग निवास करते हैं। करीब दस हजार की आबादी वाले इस गांव में अन्य समुदाय के लोग भी मिल-जुलकर रहते हैं। सभी सुख-दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पूरा गांव एक परिवार की तरह है। गांव के एक छोर पर बसा परिवार यह बता सकता है कि दूसरे छोर पर बसे फलां परिवार के घर क्या सब्जी बनी है। पूरा गांव एकता के सूत्र में बंधा हुआ है।

शिव तथा राधा-कृष्ण मंदिर हैं ऐतिहासिक धरोहर : चिल्ला गांव के केंद्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मंदिर से पूरे गांव की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर के इतिहास के बारे में श्यामचंद बताते हैं कि वर्षों पहले बाबा मैहकुलाल ने संक्रांति के दिन यहां पर भंडारे की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी कायम है। प्रत्येक वर्ष संक्रांति के दिन मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। दो दिन तक चलने वाले इस आयोजन में गांव के लोग दूध, देसी घी, चावल आदि खाने-पीने की चीजों का दान करते हैं। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही राधा-कृष्ण मंदिर स्थित है, जहां अनेक नस्लों की दुर्लभ गाए देखी जा सकती हैं। राधा-कृष्ण मंदिर भी चिल्ला गांव की प्राचीन धरोहर का आधार रहा है।

अब भी पशुपालन व कृषि से जुड़े हुए हैं लोग : यमुना नदी के पास चिल्ला खादर में गांव के लोग वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। गांव में बहुमंजिला इमारत बन जाने के कारण अब पशुओं के लिए जगह का अभाव है, लिहाजा लोग अपने मवेशियों को यमुना नदी के तट पर खेतों में ही ले गए हैं और यहीं से दूध बेचकर व कृषि करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहें हैं। चिल्ला गांव के पास ही सरकारी रेडियो अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र में आज भी गांव का प्राचीन कुआं देखा जा सकता है।

आज भी कायम है रीति-रिवाज : भले ही आज दिल्ली के प्राचीन गांव शहरीकरण में आ गए हों, परंतु आज भी इन गांवों में वर्षों पुरानी परंपराएं व रीति-रिवाज कायम हैं। चिल्ला गांव भी इनसे अछूता नहीं है। आज भी शादी-विवाह जैसे आयोजनों में गांव में प्रत्येक परिवार के यहां बुलावा देने की प्रथा जारी है। गांव की महिलाएं मिल-जुलकर एक दूसरे के आयोजन में शरीक होती हैं, पारंपरिक लोक गीत गाती हैं और सामूहिक रूप में में तीज महोत्सव जैसे आयोजनों का हिस्सा बनती हैं।

बुजुर्गों के नेतृत्व में लोग गोवर्धन पूजा का हिस्सा बनते हैं। नवरात्र व देवउठनी के दौरान संपूर्ण गांव की लड़कियां व महिलाएं टोली बनाकर गीत व भजन गाती हैं। गांव की चौपाल पर छोटे-मोटे आयोजन किए जाते हैं। यहां पर सामूहिक होली मिलन समारोह देखने लायक है।

रितु राणा

मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती बुजुर्ग महिला। साथ देते परिवार के अन्य सदस्य। हरीश कुमार

पारंपरिक लिबास व देसी खानपान

गांव के बुजुर्ग सफेद धोती-कुर्ता पहनते हैं तो महिलाएं सलवार, कमीज व ओन्ने ओढ़ती हैं। हालांकि नई पीढ़ी में धीरे-धीरे कुछ बदलाव आ रहा है। दूध, दही, देसी घी, छाछ, सरसों का साग, मक्खन व बाजरे के मलीदा जैसे देसी व्यंजन इन्हें पसंद हैं। गांव के अधिकतर घरों में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है।

कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को ओपेक राजी

वियना, एएफपी : तेल उत्पादक देशों का समूह ओपेक उत्पादन में रोजाना पांच लाख बैरल की कटौती पर राजी हो गया है। बैठक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और गैर-ओपेक सदस्य रूस भी शामिल था। इतना ही नहीं, ओपेक ने कहा कि सऊदी अरब समेत कई अन्य सदस्य देश अपनी इच्छा से भी कटौती करेंगे। इस लिहाज से कटौती का स्तर 21 लाख बैरल प्रतिदिन के ऊपर भी जा सकता है।

सरकार टेलीकॉम उद्योग की चिंता समझ रही है। यह पूरी इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार हर सेक्टर को राहत देने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी।

— कुमार मंगलम बिड़ला
चेयरमैन, वोडाफोन आइडिया

सेंसेक्स	40,445.15 ▼ 334.44	निफ्टी	11,921.50 ▼ 96.90	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,895 ▼ ₹26	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 45,547 ▲ ₹52	$ डॉलर	₹ 71.20 ▼ ₹0.09	क्रूड (बेंट) प्रति बैरल	$ 63.24

हकीकत ▶ भारी घाटे से जूझ रही कंपनी ने मौजूदा स्थिति में नए निवेश को बताया बेमानी

वोडा-आइडिया सरकारी राहत के बिना बंद हो जाएगी : चेयरमैन

कहा - अगर सरकार ने मदद नहीं की तो कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में ले जाएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारी घाटे और वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कंपनी के भविष्य को लेकर आशंका जताई है। एक कार्यक्रम में शुक्रवार को बिड़ला ने कहा कि यदि सरकार एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मसले पर कंपनी को अपनी ओर से राहत नहीं देती है तो यह बंद हो जाएगी। बिड़ला ने कहा, 'यदि हमें कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि यह वोडाफोन आइडिया की कहानी का अंत है।' उन्होंने यह भी कह दिया कि राहत नहीं मिलने पर वह कंपनी को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में ले जाएंगे।

सितंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 50,921 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह अब तक किसी भी भारतीय कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा तिमाही घाटा है। इसकी मुख्य वजह कंपनी पर एजीआर मद का बकाया है। सुप्रीम

प्रतीकात्मक

कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया पर सरकार के अनुमानित 44,150 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसे चुकाने के लिए ही कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर, 2019 के दौरान 25,680 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग की, जिसके चलते उसका घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए ही वोडाफोन आइडिया की ओर से कहा गया था कि वह एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुर्नविचार याचिका दाखिल करने जा रही है। कंपनी का चल पाना इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार से राहत मिलती है या नहीं और कानूनी मसलों का कोई सकारात्मक समाधान होता है या नहीं।

मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो का मुकाबला करने के लिए पिछले वर्ष वोडाफोन और आइडिया ने कारोबार का विलय कर लिया। इस प्रक्रिया में वोडाफोन आइडिया पर कर्ज की कुल राशि 1.17 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंची है। जियो का परिचालन शुरूहोने के बाद से उसकी दोनों प्रतिद्वंद्वी कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन लगातार घाटे में रही हैं।

बिड़ला का कहना था कि डूब रही संपत्ति में निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा और हमें दुकान बढ़ानी पड़ेगी। बिड़ला के मुताबिक सरकार ने माना है कि टेलीकॉम बेहद संवेदनशील सेक्टर है और डिजिटल इंडिया का पूरा का पूरा कार्यक्रम इसी पर निर्भर है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार केवल टेलीकॉम सेक्टर को नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर सेक्टर को राहत देने के बारे में विचार करेगी।

इसी तरह के बयान में वोडाफोन सीईओ मांग चुके हैं माफी

पिछले महीने वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार दूरसंचार ऑपरेटरों पर भारी-भरकम टैक्स और शुल्क का बोझ डालना बंद नहीं करती है, तो भारत में कंपनी के भविष्य पर संकट आ सकता है। सरकार ने रीड के इस बयान और उनके लहजे को आपत्तिजनक माना और अपनी नाराजगी जाहिर की। सरकार के इस रुख के बाद कंपनी ने कहा है कि वह भारत में बने रहने को लेकर प्रतिबद्ध है। वोडाफोन सीईओ निक रीड ने सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि कंपनी भारत में अपना निवेश बनाए रखने को इच्छुक है। रीड ने कहा कि लंदन में उनके दिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

ई-कॉमर्स कंपनियों हर वर्ष दाखिल करेंगी एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कंपनियों को सालाना दाखिल करनी होगी कंप्लायंस रिपोर्ट
- एफडीआइ एफडीआइ नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा

प्रतीकात्मक

सरकार ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हर साल एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य बना दिया है। कंपनियों को यह रिपोर्ट हर साल 30 सितंबर से पहले अपने ऑडिटरों के जरिये दाखिल करनी होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां सरकार के नियमों का पालन कर रही हैं।

एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एफडीआइ कंप्लायंस की रिपोर्ट ई-कॉमर्स कंपनियों को सितंबर के अंत तक दाखिल करनी होगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि हर साल रिपोर्ट दाखिल होने से यह पता लगाना आसान होगा कि कंपनियां एफडीआइ नियमों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं। हालांकि कई कंपनियों के अधिकारियों का मानना है कि इससे उनकी कंप्लायंस लागत में वृद्धि हो जाएगी।

गौरतलब है कि व्यापारियों के संगठन लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियां एफडीआइ नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके चलते खुदरा कारोबारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी कंपनियां सरकार पर लगातार एफडीआइ नियमों में राहत के लिए दबाव बनाती रही हैं। वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) चाहता है कि सरकार विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को एफडीआइ नियमों के मामले में कोई राहत नहीं दे। संगठन ने सरकार को सुझाव भी दिया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले एफडीआइ कंप्लायंस का प्रमाणपत्र हासिल करने को अनिवार्य बनाया जाए। वर्तमान में देश में तीन बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट और क्लब फैक्ट्री काम कर रही हैं।

त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले डिस्काउंट और छूट को लेकर भी सरकार को व्यापार संगठनों ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कंपनियों को चेतावनी भी दी थी कि यदि इस तरह के ऑफर्स पर रोक नहीं लगायी गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक महीने पहले गोयल से साथ अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल की मुलाकात में भी यह मुद्दा चर्चा में आया था। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे वेंडर्स के प्रोडक्ट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिनमें उनकी इक्विटी हिस्सेदारी है।

अरैमको ने आइपीओ से जुटाई रिकॉर्ड रकम

न्यूयॉर्क, रायटर : सऊदी अरब की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरैमको ने गुरुवार को अपना प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) लांच कर दिया। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने प्राइस रेंज के ऊपरी स्तर पर 2,560 करोड़ डॉलर (करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये) जुटाए हैं। इस रकम के लिहाज से अरैमको आइपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा रकम जुटाने वाली कंपनी बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के नाम था, जिसने 2014 में आइपीओ के जरिए 2,500 करोड़ डॉलर जुटाए थे।

सूत्रों ने बताया कि रियाद स्टॉक एक्सचेंज में अरैमको के शेयर 32 रियाल के शुरुआती मूल्य पर बेचे जाएंगे। इस हिसाब से कंपनी का बाजार मूल्य 1.7 लाख करोड़ डॉलर (करीब 121 लाख करोड़ रुपये) होती है। इस हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि कंपनी 15 फीसदी ग्रीनशू विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इससे आइपीओ का आकार बढ़कर 2,940 करोड़ डॉलर तक हो सकता है।

- 1.80 लाख करोड़ रुपये जुटाकर चीन की अलीबाबा को पीछे छोड़ा
- पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई

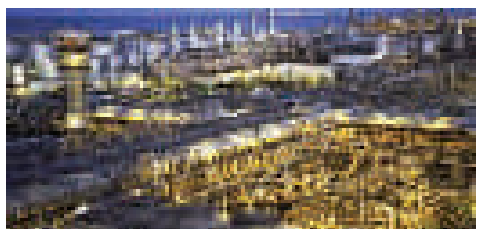

प्रतीकात्मक

विदेशी बाजारों में नहीं होगी लिस्टिंग : पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सऊदी अरैमको के आइपीओ दो स्टॉक एक्सचेंजं पर सूचीबद्ध होंगे। चूंकि पहले कंपनी पांच प्रतिशत शेयरों की बिक्री आइपीओ के जरिये करने वाली थी, लिहाजा उस वक्त दो प्रतिशत शेयर सऊदी अरब के तडावुल शेयर बाजार और बाकी तीन प्रतिशत शेयर एक विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले थे। लेकिन, बाद में कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी योजना अंतराष्ट्रीय बाजार में शेयर लिस्ट कराने की नहीं है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज से डील की बात : एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज की सऊदी अरैमको के साथ हिस्सेदारी बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है। रिलायंस की 42वीं एजीएम में यह साफ किया गया था कि अरैमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल-टु-केमिकल बिजनेस का 20 फीसदी हिस्सा खरीदेगी।

इसके लिए सऊदी आरामको 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के मामले में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। हिस्सेदारी खरीदने के बाद रिलायंस रिफाइनरी को अरैमको रोजाना पांच लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करेगी।

आरबीआइ से निराश बाजारों पर मायूसी हावी

मुंबई, प्रेट्र : रेपो रेट में कटौती नहीं होने से निराश शेयर बाजारों पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में शुक्रवार को मायूसी हावी रही। दिन के कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी 12,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स भी 334.44 अंकों की गिरावट का शिकार हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 40,445.15 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 96.90 अंक यानी 0.81 प्रतिशत टूटकर 11,921.50 पर स्थिर हुआ।

सेंसेक्स पैक में शुक्रवार को सबसे ज्यादा दबाव निजी क्षेत्र के कर्जदाता यस बैंक के शेयरों पर दिखा। इस बैंक के शेयर बीएसई पर 9.82 प्रतिशत यानी 6.10 रुपये लुढ़ककर 56 रुपये के स्तर पर रह गए। गुरुवार को अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बैंक का आउटलुक घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया था। रेटिंग पर इस दबाव के चलते शुक्रवार को बैंक के शेयर खासा लुढ़क गए। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा था कि अगर बैंक करीब 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, तो उसकी रेटिंग में फिर से सुधार किया जा सकता है।

- निफ्टी 12,000 के स्तर से नीचे आया, सेंसेक्स 334 अंक फिसला
- यस बैंक के शेयरों पर भारी दबाव, करीब 10 प्रतिशत टूटा

बैंकिंग और ब्याज संवेदनशील स्टॉक्स निवेशकों से निवेशकों ने बनाए रखी दूरी। प्रतीकात्मक

सेंसेक्स में शुक्रवार को एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा एचडीएफसी के शेयर भी खासा टूट गए। दूसरी तरफ कोटक बैंक, टाटा स्टील, आरआइएल, एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस व एचडीएफसी बैंक के शेयरों में सुधार देखा गया। सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में टेलीकॉम को छोड़कर अन्य सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए।

भारतीय बाजारों के विपरीत एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में ज्यादातर निवेशकों का मूड पॉजिटिव था। इसकी वजह यह थी कि अधिकांश निवेशकों का मानना है कि अमेरिका और चीन में पहले चरण की कारोबारी सौदेबाजी जल्द हो सकती है। चीन ने अमेरिका के कुछ उत्पादों से शुल्क हटाने या घटाने पर विचार की भी बात कही है। शुक्रवार को हांगकांग, शंघाई, टोक्यो, सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक व जकार्ता के स्टॉक एक्सचेंज में दो प्रतिशत तक का उछाल देखा गया। सियोल और ताइपेई के शेयर बाजार भी 0.4 प्रतिशत तक सुधरे। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान लंदन, फ्रैंकफर्ट और पेरिस के शेयर बाजार भी बढ़कर कारोबार कर रहे थे।

सोना फिसला, चांदी में मामूली सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को सराफा बाजार में सोना 26 रुपये फिसलकर 38,895 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर स्थिर हुआ। हालांकि चांदी में थोड़ा सुधार देखा गया और यह कारोबार के आखिर में 52 रुपये चढ़कर 45,547 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर स्थिर हुई। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के कमोडिटीज एनालिस्ट तपन पटेल का कहना था कि डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने के चलते सोने के भाव में फिसलन देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,473 डॉलर और चांदी भी थोड़ा फिसलकर 16.88 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार कर रहे थे।

इनग्राम माइक्रो क्लाउड समिट में भारतीय कंपनियां

नई दिल्ली (वि) : अमेरिका में होने वाली इनग्राम माइक्रो क्लाउड समिट के लिए भारत की बी2बी कंपनी रैपिडर का चयन हुआ है। यह कंपनी अगले साल मियामी में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगी। इसमें प्रथम विजेता को दस लाख डॉलर की फंडिंग मिलेगी। इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए चयन की प्रक्रिया पिछले साल अगस्त से प्रारंभ हुई थी।

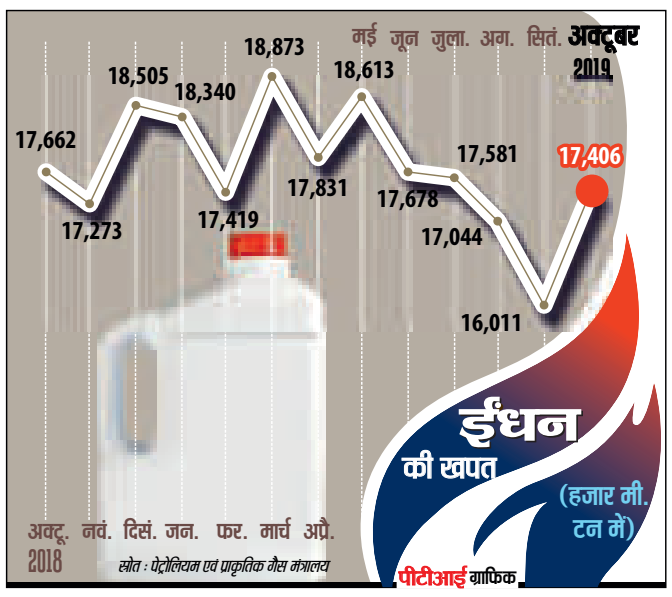

ऑटो कंपोनेंट उद्योग का टर्नओवर 10 प्रतिशत गिरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पहली छमाही के दौरान निर्यात में हुई महज 2.7 परसेंट की वृद्धि
- सुस्ती की वजह से एक लाख अस्थायी श्रमिकों की गई नौकरी

ऑटो सेक्टर की मंदी ने कंपोनेंट उद्योग पर गहरा असर डाला है। प्रतीकात्मक

ऑटो कंपनियों की बिक्री की धीमी रफ्तार के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपोनेंट उद्योग की बिक्री भी प्रभावित रही। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान न केवल उद्योग के टर्नओवर में 10.1 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई, बल्कि जुलाई तक एक लाख अस्थायी श्रमिकों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा।

ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एक्मा) के मुताबिक इस अवधि में उद्योग का टर्नओवर 1.79 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.99 लाख करोड़ रुपये का रहा था। एसोसिएशन का कहना है कि इसके चलते उद्योग को करीब दो अरब डालर के निवेश का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि इस अवधि में उद्योग के एक्सपोर्ट में 2.7 परसेंट की वृद्धि की गई है।

उद्योग के छमाही प्रदर्शन पर एक्मा के प्रेसिडेंट दीपक जैन ने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सुस्ती के दौर से गुजर रही है। पिछले एक साल से वाहनों की बिक्री में कमी आ रही है। कंपोनेंट उद्योग की बिक्री में पिछली बार ऐसी गिरावट 2013-14 में देखी गई गई जब इसके टर्नओवर में दो प्रतिशत की कमी हुई थी।

जहां तक उद्योग में नौकरियां जाने का सवाल है जैन ने कहा कि कंपोनेंट उद्योग में पिछले साल अक्टूबर से इस जुलाई तक छंटनी का दौर चला है। हालांकि छंटनी का सर्वाधिक असर अस्थायी कर्मचारियों पर ही हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उद्योग का क्षमता उपयोग 50 परसेंट रह गया है। वाहन उद्योग में उत्पादन चरम पर होने पर भी कंपोनेंट उद्योग का क्षमता उपयोग अधिकतम 80 परसेंट तक ही रहता है। पिछले कुछ समय में कई शहरों से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में छंटनी की बातें सामने आई हैं।

मारुति सुजुकी ने की 63 हजार से ज्यादा कारें रिकॉल

नई दिल्ली, प्रेट्र : मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) ने शुक्रवार को कहा कि वह 63,493 यूनिट कारें रिकॉल कर रही है। इसमें सियाज, अर्टिगा और एक्सएल-6 मॉडल के पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड (एसएचवीएस) वैरिएंट शामिल हैं। इन सभी कारों का उत्पादन इस वर्ष पहली जनवरी से 21 नवंबर के बीच हुआ है। एक बयान में कंपनी ने कहा कि इनकी मोटर जनरेटर यूनिट (एमजीयू) में खामी का अंदेशा है। यह खामी एक विदेशी पार्ट सप्लायर के द्वारा उत्पादन के दौरान ही पैदा हुई होगी। निरीक्षण के दौरान जिन कारों में खामी नहीं पाई जाएगी, उन्हें तत्काल ग्राहकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

डीएचएफएल की इंश्योरेंस इकाइयों को खतरा नहीं

मुंबई, प्रेट्र : दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही एनबीएफसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) की दोनों इंश्योरेंस शाखाओं को कोई खतरा नहीं है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन एससी खूंटिया ने कहा है कि डीएचएफएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दोनों इंश्योरेंस शाखाओं डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस और डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस के पास पर्याप्त पूंजी है। उन्होंने बीमाधारकों को भी यकीन दिलाया कि उनकी पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और डीएचएफएल की दिवालिया प्रक्रिया में उन पर कोई आंच नहीं आएगी। इरडा चेयरमैन ने दोनों इंश्योरेंस कंपनियों से कहा कि वे डीएचएफएल में अपने कर्ज के एवज में उसी तरह से प्रावधान करें, जैसा उन्होंने आइएलएंडएफएस के मामले में किया था। इस वक्त तक के हिसाब से दोनों इंश्योरेंस कंपनियों का पूंजी अनुपात पर्याप्त है। इस वर्ष सितंबर के आखिर में डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस की सॉल्वेंसी रेश्यो 388 प्रतिशत और डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस की 230 प्रतिशत थी।

आरबीआइ का सर्वे

आर्थिक हालात के बेहतरी की उम्मीद पांच वर्षों के निचले स्तर पर, 13 शहरों में कराया गया सर्वे, 5,334 परिवारों से आरबीआइ ने ली राय

आर्थिक हालात को लेकर जनता की नाउम्मीदी बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक हालात को ट्रैक पर लाने के लिए सरकार लगातार भले ही प्रयास कर रही है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल दिखता है। आरबीआइ के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट ने इसका संकेत दे दिया है। रिपोर्ट का सार यह है कि देश के आर्थिक हालात, महंगाई, रोजगार की स्थिति को लेकर नाउम्मीदी रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दरअसल, निकट भविष्य में हालात नहीं सुधरने की बात मानने वालों की संख्या मार्च, 2014 के बाद सबसे कम है। देश के 13 बड़े शहरों में कराए गए इस सर्वेक्षण के मुताबिक नवंबर, 2019 में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स घटकर 85.7 प्रतिशत रहा है। दो महीने पहले यह 89.4 प्रतिशत था।

आम जनता का मूड भांपने के लिए आरबीआइ ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना व तिरुअनंतपुरम के 5,334 परिवारों के बीच यह सर्वे करवाया है। हर दो महीने पर केंद्रीय बैंक यह सर्वे करवाता है और ब्याज दरों पर फैसला करने या आर्थिक विकास दर के अनुमान लगाने में इस सर्वे की अहम भूमिका होती है। गुरुवार को ही आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। पिछले सात महीनों में केंद्रीय बैंक उक्त अनुमान में पांच बार कटौती कर चुका है। अप्रैल में आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सात प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था।

दो महीने पहले के मुकाबले इकोनॉमी को लेकर लोगों का भरोसा गिरा है। प्रतीकात्मक

बहरहाल, सर्वे के मुताबिक नवंबर में 51.6 फीसद लोगों ने कहा है कि सामान्य आर्थिक हालात पहले से खराब हुए हैं। 30 फीसद लोगों का कहना है कि स्थिति सुधरी है, जबकि 18.4 फीसद का मानना है कि हालात में बदलाव नहीं हुआ है। दो महीने पहले के इसी सर्वे में 47.9 प्रतिशत लोग हालात को खराब मानते थे, जबकि 33.5 फीसद लोग हालात सुधरने का भरोसा जता रहे थे। उस वक्त 18.6 प्रतिशत लोगों ने स्थिति जस की तस बनी रहने की बात कही थी। अगर एक वर्ष पहले के सर्वे में देखे तो उक्त तीनों मानकों को मानने वाले लोगों का प्रतिशत 45.2, 33.2 और 21.6 था। इसका सीधा मतलब यह है कि बेहतरी की बात करने वालों की संख्या घटी है और हालात खराब होने की बात करने वालों की तादाद बढ़ी है।

इस सर्वे में शामिल लोगों से यह भी पूछा गया है कि एक साल बाद उनकी क्या स्थिति होगी, तो इसका जवाब भी बहुत उत्साह जगाने वाला नहीं है। नवंबरमें 48.9 फीसद लोगों ने कहा है कि हालात सुधरेंगे, 16.5 फीसद ने कहा है कि जस के तस रहेंगे और 34.7 फीसद मानते हैं कि हालात बिगड़ेंगे। अगर वित्त वर्ष की शुरुआत के सर्वे को देखे तो उक्त तीनों वर्ग में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 66.4, 15.8 और 17.8 रहा है। नवंबर, 2018 के मुकाबले भी स्थिति लोगों की नजर में बिगड़ी ही है। लोगों की यही भावना रोजगार और कीमतों को लेकर भी है।

अभी रुलाएगा प्याज, ज्यादातर शहरों में कीमत 100 के पार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यों की राजधानियों व महानगरों में बिक रहा सबसे महंगा
- आयातित प्याज की पहली खेप के 20 तक पहुंचने की संभावना

प्याज की किल्लत से राहत के लिए उपभोक्ताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विभिन्न राज्यों की राजधानियों व ज्यादातर महानगरों में प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। इस बीच सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि आयातित प्याज की पहली खेप के 20 दिसंबर तक पहुंचने की संभावना है।

खरीफ सीजन वाली प्याज की फसल के खराब होने से पैदावार में भारी कमी आई है। इसी कारण प्याज की कीमत आसमान छू रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के दैनिक मूल्य निगरानी सेल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्याज का अधिकतम मूल्य 165 रुपये व न्यूनतम 42 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। देश के 100 से अधिक शहरों में प्याज का औसत मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, अगरतला, इंफाल, शिलांग, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, पंचकुला, शिमला, देहरादून और चंडीगढ़ में प्याज 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है।

संसद में भी प्याज की कीमत का मुद्दा रोजाना उठाया जा रहा है। शुक्रवार को भी राज्यसभा में सवाल पूछे गए। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने बताया कि आयातित प्याज की खेप के 20 दिसंबर तक पहुंचने की संभावना है। दुनिया के विभिन्न देशों में प्याज की उपलब्धता पर काम जारी है। सरकारी एजेंसी एमएमटीसी इसमें जुटी हुई है। खरीफ सीजन वाली प्याज की पैदावार में भारी गिरावट आई है। पहले मानसून की अधिक देर तक होने वाली भारी बारिश ने प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है।

23 लोगों का अपहरण किया है बंदूकधारियों ने मैक्सिको के एक नशा मुक्ति केंद्र से। बाद में आरोपित 13 लोगों को रिहा कर वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुलभूषण से मुलाकात पर पाकिस्तान से हो रही वार्ता

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तानी जेल में बंद नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक सुविधा मुहैया कराने पर भारत और पाकिस्तान के उच्च अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। यह वार्ता अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को अमल करने के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी है।

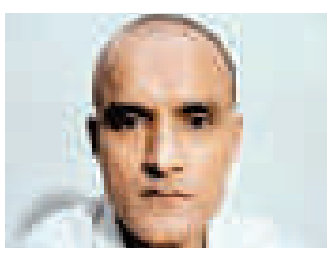
कुलभूषण जाधव। फाइल

प्रवक्ता ने बताया है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जाधव को अविलंब, प्रभावी और सीधी राजनयिक मुलाकात की सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कहां तक पहुंचती है। बीती 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को जाधव की भारतीय राजनयिक से मुलाकात सुनिश्चित कराने का आदेश दिया था। इस तरह की मुलाकात जाधव को तब तक मिलेगी जब तक उनकी सजा पर अमल नहीं हो जाता। यह व्यवस्था विएना संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों की साजिश रचने का दोषी ठहराकर उन्हें मौत की सजा सुनाई है। इस दौरान जाधव को अपने बचाव के लिए कोई वकील भी नहीं दिया गया। जाधव को ईरान में पाकिस्तानी सीमा के नजदीक से तालिबान ने तब पकड़ा था, जब वह वहां कारोबार के सिलसिले में गए थे, इसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों को सौंप दिया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के अधिकारी गौरव अहलूवालिया को दो सितंबर को जाधव से मुलाकात की इजाजत दी। लेकिन यह मुलाकात एकांत में नहीं हो पाई।

अभिजीत ने 'नोबेल चेयर' पर किए हस्ताक्षर

नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी (दाएं) और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो ने शुक्रवार को स्वीडन स्थित नोबेल म्यूजियम में पारंपरिक 'नोबेल चेयर साइनिंग सेरेमनी' के दौरान कुर्सी पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि 58 वर्षीय अभिजीत और एस्थर को वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करने को लेकर किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रायटर

पाक न्यायिक आयोग ने हिंदू छात्रा की मौत को बताया खुदकशी

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नमृता की हत्या की बात आई थी सामने
- हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला था शव

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई हिंदू छात्रा नमृता चंदानी के मामले में लीपापोती के प्रयास शुरू हो गए हैं। मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने दावा किया है कि छात्रा ने खुदकशी की थी। आयोग ने हत्या की बात को खारिज किया है। जबकि गत नवंबर में आई अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह उजागर हुआ था कि नमृता की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। घोटकी जिले की रहने वाली नमृता लरकाना के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज में स्नातक की छात्रा थीं। उनका शव गत 16 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला था।

सूत्रों के अनुसार, जांच आयोग ने 17 पेज की अपनी रिपोर्ट सिंध प्रांत के गृह विभाग के पास भेज दी है। लरकाना के जिला और सेशन जज की अगुआई वाले इस आयोग ने चश्मदीदों समेत डेंटल कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ से पूछताछ के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। आयोग ने पुलिस जांच, पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट की भी समीक्षा की। इसके अलावा नमृता के सेलफोन और लैपटॉप के साथ ही संदिग्धों और अन्य साक्ष्यों के फोरेंसिक डाटा को भी खंगाला गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'नमृता अपने एक दोस्त द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के चलते बेहद तनाव में थीं। गंभीर तनाव और हताशा के चलते नमृता ने आत्महत्या की थी।'

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह थी बात : नमृता (25) की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट गत छह नवंबर को जारी की गई थी। इसके अनुसार, नमृता की मौत दम घुटने से हुई थी। डीएनए टेस्ट में छात्रा के कपड़ों पर पुरुष डीएनए मिलने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा एक अन्य जांच में जबरन यौन संबंध बनाने की भी पुष्टि हुई थी।

इन सवालों का क्या : प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कराची स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि गले पर मिले निशान गला घोंटने की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि पांच फीट लंबी छात्रा खुद ही कैसे कमरे में पंखे से फंदा लगाकर लटक गई? जबकि पंखा 15 फीट की ऊंचाई पर था।

हिरासत में लिए गए थे 32 संदिग्ध

नमृता की मौत के मामले में 32 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें नमृता के दो सहपाठी मेहरान अब्रो और अली शान मेमन भी थे। पुलिस पूछताछ में मेहरान ने दावा किया था कि नमृता उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी से इन्कार कर दिया था।

न्यूज गैलरी

अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई में छह तालिबान आतंकी ढेर

काबुल : अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सेना की कार्रवाई में शुक्रवार को वरदाक प्रांत में छह आतंकी मारे गए। सेना ने बताया कि लड़ाकू विमानों की मदद से सैयदाबाद जिले में इनके आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए। हमले पर तालिबान ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। (आइएएनएस)

ईरान में गैस पाइपलाइन में धमाके से 11 की मौत

तेहरान : ईरान के कुर्द बहुल शहर साकेज में गुरुवार शाम गैस पाइपलाइन में तेज धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पांच बच्चे और पांच महिलाएं शामिल हैं। पाइपलाइन में यह धमाका उस वक्त हुआ जब वहां एक शादी समारोह चल रहा था। घटना को लेकर कुर्दिस्तान प्रांत में एक दिन का शोक घोषित किया गया है। (एपी)

छह घंटे बाद फिर धड़कने लगा ब्रिटिश महिला का दिल

लंदन : छह घंटे तक काम नहीं करने के बाद ब्रिटेन की एक महिला का दिल फिर धड़कने लगा। डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ मामला बताया है। यह वाकया पेश आया 34 साल की ऑड्री शोमैन के साथ। बार्सिलोना में रहने वाली ऑड्री हाल में हाइकिंग के लिए पति रोहन के साथ स्पेन के पर्वतीय इलाके पायरेनीस गई थीं। इसी दौरान अचानक आए बर्फीले तूफान में दोनों घिर गए। बर्फीली हवाओं के थपेड़े झेलने से ऑड्री के दिल की धड़कन रुक गई और वह बेसुध हो गईं। तेज तूफान के कारण राहत और बचाव सेवा भी देर से उनके पास पहुंची। भारी बर्फ के बीच घंटों बेसुध पड़ी पत्नी को रोहन ने मृत मान लिया था। लेकिन छह घंटे बाद बार्सिलोना के एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर डॉक्टर ऑड्री की जान बचाने में कामयाब रहे। डॉक्टरों ने बताया कि हाइपोथर्मिया के कारण ऑड्री के दिल की धड़कन रुक गई थी। लेकिन इसी वजह से उनके शरीर और मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। (आइएएनएस)

अमेरिका के साथ टू प्लस टू वार्ता 18 को

वाशिंगटन, : अमेरिका भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और व्यापक बनाने का इच्छुक है और उसकी यही सोच आगामी टू प्लस टू वार्ता में परिलक्षित होगी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की यह बैठक 18 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। पहली बैठक सितंबर 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। आगामी बैठक में दोनों देश बाहरी चुनौतियों, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर विचार करेंगे। रक्षा नीति मामलों के उप मंत्री जॉन सी रूड ने कहा, हम भारत के साथ अपने रक्षा संबंध और ज्यादा बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसी पर दोनों देशों के नेता बात करेंगे। हम दोनों देशों की सेनाओं के बीच हर तरह का सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। सेना के संयुक्त अभ्यास चल रहे हैं। तीनों सेनाओं का एक साथ संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रिफ भी हाल ही में पूरा हुआ है। प्रेट्र

कंगाली से उबरने को पाकिस्तान को मिला एडीबी का सहारा

मिली मदद ▶ एशियाई विकास बैंक देगा एक अरब डॉलर का कर्ज

देश की अर्थव्यवस्था के स्थिर होने की जगी उम्मीद

मनीला, एएनआइ : कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अब एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का सहारा मिला है। एडीबी ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने के लिए एक अरब डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) का आपात कर्ज देने पर शुक्रवार को अपनी मुहर लगा दी। पाकिस्तान को इससे पहले चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अपने मित्र देशों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से भी कर्ज मिल चुका है।

एडीबी के अनुसार, 'यह कर्ज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आइएमएफ के आर्थिक सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा आइएमएफ समर्थित सुधारों को लागू किए जाने के बाद कर्ज मंजूर किया गया। पाकिस्तान कमजोर विकास दर के साथ ही भुगतान में भारी अंतर और निम्न विदेशी मुद्रा भंडार के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।' एडीबी में मध्य और पश्चिम एशियाई मामलों के महानिदेशक वार्नर लीपेच ने कहा कि इस धनराशि से पाकिस्तान की सरकार को प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को रोकने के लिए जरूरी आपात पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।

इमरान खान। फाइल

आइएमएफ से मिला छह अरब डॉलर कर्ज

पाकिस्तान को आइएमएफ ने इस साल जुलाई में छह अरब डॉलर (करीब 42 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज मंजूर किया था। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी अरबों रुपये का आर्थिक पैकेज मिल चुका है।

पाक के आर्थिक हालात

3.3 फीसद जीडीपी (सकल घरेलू आय) रहने का अनुमान है इस साल, जबकि अगले वर्ष यह घटकर 2.8 फीसद हो सकती है

2019 में 7.3 फीसद रहेगी महंगाई दर, अगले वर्ष यह बढ़कर 12 फीसद हो सकती है

1.5 फीसद रहेगी प्रति व्यक्ति जीडीपी 2019 में और 2020 में 1.2 फीसद रहने का अनुमान है

(एशियन विकास बैंक के अनुसार)

विश्वबैंक ने भी दिया था कर्ज : इस साल जुलाई में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 72.2 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी थी। इस कर्ज का ज्यादातर हिस्सा कराची में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाना है।

कतर ने भी की थी मदद : तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को खाड़ी देश कतर ने तीन अरब डॉलर की आर्थिक मदद की थी। पाकिस्तान के दौरे पर गए कतर के शेख तमीम बिन हमद ने पाकिस्तान को यह सहायता राशि दी थी।

हाफिज सईद की सुविधाओं पर इमरान सरकार को लताड़

नई दिल्ली, एएनआइ : मुंबई के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार की सुविधाओं का उपभोग करते हुए मनमाने अंदाज में रह रहा है। जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र के इस घोषित आतंकी सरगना के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कही है। मुंबई हमले में कई विदेशियों समेत 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे।

हाफिज सईद। फाइल

प्रवक्ता ने कहा, हम सभी जानते हैं कि इस हमले के साजिशकर्ता कौन थे और मास्टरमाइंड कौन था। हम अच्छी तरह जानते-देखते हैं कि यह मास्टरमाइंड पाकिस्तान में सरकार की सुरक्षा-सुविधा में आजादी से घूमता है और मनमाने तरीके से रहता है। जाहिर है प्रवक्ता का इशारा पाकिस्तानी संगठन जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद की ओर था। प्रवक्ता ने कहा, भारत ने मुंबई हमले में हाफिज सईद और उसके संगठन के अन्य लोगों के हाथ होने के सुबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। लेकिन वहां की सरकार सईद के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय समझ चुका है कि पाकिस्तान मुंबई हमलों के दोषियों और भारत में अन्य आतंकी वारदातों के मास्टरमाइंड और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता।

जलवायु सम्मेलन के लिए मैड्रिड पहुंचीं पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा

मैड्रिड में एक कार्यक्रम के दौरान जलवायु कार्यकर्ताओं के साथ ग्रेटा थनबर्ग (मध्य में)। रायटर

मैड्रिड, रायटर : जलवायु परिवर्तन पर अपनी मुहिम से सुर्खियों में आईं 16 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग शुक्रवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंच गईं। वह यहां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही एक मार्च में भी हिस्सा लेंगी। यह मार्च वैश्विक नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सही मायने में कदम उठाने की मांग को लेकर निकाला जाना है। इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

जलवायु परिवर्तन पर युवा आंदोलन का वैश्विक चेहरा बनकर उभरीं स्वीडन की ग्रेटा ने मैड्रिड पहुंचने के लिए कार्बन मुक्त परिवहन अपनाया। इसके लिए वह एक नौका के जरिये अटलांटिक महासागर पार कर पिछले हफ्ते अमेरिका से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचीं। इसके बाद मैड्रिड तक का सफर उन्होंने ट्रेन और इलेक्ट्रिक कार के जरिये किया। ग्रेटा ने गत 23 सितंबर को जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं और सवालों से दुनिया को झकझोरा था। संयुक्त राष्ट्र में अपने भावनात्मक भाषण में उन्होंने दुनियाभर के नेताओं से कहा था, 'आपने हमारा बचपन और सपने छीन लिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसके लिए आपको माफ नहीं करूंगी।' ग्रेटा ने अपने आंदोलन के जरिये महज एक साल के अंदर पूरी दुनिया में हजारों युवाओं को प्रेरित किया है।

चीनी कर्ज में फंसा मालदीव धन चुकाने के नए रास्ते तलाशेगा

3.4 लाख की आबादी वाले देश पर दस हजार करोड़ का कर्ज

कोलंबो, एएफपी : मालदीव बीते वर्षों में चीन से लिए भारी कर्ज से उबरने के लिए अब उसे चुकाने की प्रक्रिया के पुनर्गठन का इच्छुक है। वह यह कार्य कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत करना चाह रहा है। चीन से बड़ा कर्ज ले चुका छोटा मालदीव अब धन वापसी की समस्या से जूझ रहा है।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने पांच साल के कार्यकाल में चीन से परियोजनाओं के लिए भारी कर्ज लिया था। बाद में आई सरकार ने यामीन को देश को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने गुरुवार को कहा, चीन उदार कर्जदाता है लेकिन पूर्व की सरकार ने कर्ज चुकाने के बारे में सोचे बगैर उधार लिया। इससे अब देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। श्रीलंका दौरे पर आए शाहिद ने बताया कि मालदीव के सरकारी उपक्रमों पर चीन का 1.4 अरब डॉलर (करीब दस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का कर्ज है। इन सबके लिए सरकार ने गारंटी दी हुई है। यह धनराशि 3.40 लाख सुन्नी मुसलमानों के देश के लिए काफी बड़ी है। अब्दुल्ला यामीन सरकार ने जिस तरह से बिना कारण के कर्ज लिया, उससे देश अब कठिनाई का सामना कर रहा है। लेकिन हम इस समस्या का कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालेंगे। चीन समर्थक यामीन को मालदीव की अदालत ने भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए नवंबर में पांच साल के कारावास और 50 लाख डॉलर (3,500 करोड़ भारतीय रुपये) सरकारी खजाने में जमा कराने का दंड दिया है। यामीन चुनाव हारने के बाद 2018 में सत्ता से बाहर हुए थे।

अब्दुल्ला यामीन। फाइल

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से खतरे में सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से के जंगलों में लगी भयंकर आग से देश के सबसे बड़े शहर सिडनी पर खतरा मंडराने लगा है। शहर के उत्तर की ओर 50 किलोमीटर क्षेत्र में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया है। इस आग से निकले धुएं और राख के कण न्यू साउथ वेल्स प्रांत की राजधानी सिडनी के आसमान पर छा गए हैं। बाहर निकलने के लिए लोगों को मास्क लगाने पड़ रहे हैं। शहर में सप्ताहांत में होने वाले सभी खेल आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग के अनुसार, सिडनी के नजदीक हॉक्सबरी, हंटर और सेंट्रल कोस्ट इलाके में आग ने तांडव मचा रखा है। आग इतनी प्रचंड है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं पिछले महीने शुरू हुई थीं। इनमें अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 700 के करीब घर जलकर राख हो चुके हैं। रायटर

डाकघर को सिख अफसर का नाम देने का बिल अमेरिकी संसद में पेश

ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिका के एक डाकघर का नाम ड्यूटी के दौरान शहीद हुए भारतवंशी सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल पर रखने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया है। यह बिल टेक्सास से सांसद लिजी फ्लेचर ने पेश किया है। गत 27 सितंबर को ह्यूस्टन शहर में ड्यूटी पर तैनात हैरिस काउंटी के डिप्टी शेरिफ संदीप (42) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अमेरिका के पहले सिख पुलिस अफसर थे जिन्हें दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी पहनने की छूट मिली थी।

संदीप सिंह। फाइल

फ्लेचर ने संसद में पेश बिल में ह्यूस्टन के एडिक्स हॉवेल रोड स्थित डाकघर का नाम शहीद सिख अफसर पर करने का प्रस्ताव रखा है। संसद में इस बिल को पेश करने के दौरान फ्लेचर ने कहा, संदीप को उनके बेहतरीन सेवा भाव के लिए लोग हमेशा याद रखेंगे। संदीप के नाम का डाकघर अमेरिका में उनकी सेवा और बलिदान की याद दिलाता रहेगा।

ईरान परमाणु समझौता बचाने के लिए हुई बैठक

वियना, एएफपी : ईरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम की सीमा का उल्लंघन करने के संकल्प के बीच परमाणु समझौते पर दस्तखत करने वाले देशों की एक बैठक हुई है। परमाणु समझौता बचाए रखने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधियों ने तीन घंटे तक विचार-विमर्श किया। यह जुलाई के बाद इन छह देशों की पहली बैठक है। मई के बाद से ईरान ने समझौते का उल्लंघन करते हुए कई कदम उठाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका द्वारा 2018 में संधि से बाहर आने और उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसे इस तरह के कदम उठाने का अधिकार है।

चीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख कांग फू ने पत्रकारों से कहा कि सभी पक्ष समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को ऐसे कदम उठाने से बचना होगा, जिससे हालत और जटिल हो जाए। संभवतः अमेरिका को छोड़कर इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। रूस के प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने ट्वीट किया कि तमाम कठिनाइयों और मतभेदों के बावजूद सभी पक्ष पूरी तरह समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

इक्वाडोर में नहीं है फरार नित्यानंद

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत में दुष्कर्म और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर फरार हुए नित्यानंद को इक्वाडोर ने शरण देने से इन्कार किया है। दक्षिण अमेरिकी देश ने साफ किया है कि भारत के इस स्वयंभू भगवान को जमीन खरीदने में किसी तरह की सुविधा भी नहीं दी गई है। नई दिल्ली स्थित इक्वाडोर के दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वास्तव में उनके देश ने नित्यानंद को शरण देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद वह हैती के लिए रवाना हो गया। दूतावास ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें नित्यानंद को इक्वाडोर में शरण मिलने की बात कही गई है।

दूतावास ने साफ किया है कि इक्वाडोर ने नित्यानंद को जमीन खरीदने के लिए न कोई सुविधा दी और न ही कहीं पर उसका सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि मीडिया में नित्यानंद के इक्वाडोर के नजदीक एक द्वीप खरीदने की बात आई है। इसके लिए उसे इक्वाडोर सरकार की सहायता मिलने की बात कही गई है। बयान में कहा गया है कि मीडिया ने यह दावा कैलासा. ओआरजी वेबसाइट के हवाले से किया है। जब वेबसाइट नित्यानंद या उसके किसी समर्थक है, जो स्वयंभू भगवान के बारे में अक्सर अनर्गल बातें सार्वजनिक करती है। वेबसाइट ने इक्वाडोर में नित्यानंद के खरीदे गए द्वीप को हिंदू देश कैलासा की संज्ञा दी है। कर्नाटक में अपने खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किए जाने के बाद नित्यानंद बिना पासपोर्ट के फरार हो गया। बाद में उसके इक्वाडोर में शरण लेकर वहां एक द्वीप खरीदने की चर्चा फैली।

विदेश मंत्रालय ने दूतावासों को किया सतर्क

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न और अपहरण मामलों के आरोपी बाबा नित्यानंद की फरारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अपने दूतावासों और मिशनों को सतर्क कर दिया है। वैसे विदेश मंत्रालय को अभी इस बात की पक्की जानकारी नहीं है कि नित्यानंद कब फरार हुआ है और अभी कहां है लेकिन मीडिया में आ रही खबरों को देखते हुए उक्त कदम उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि अभी तक किसी भी एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से नित्यानंद के प्रत्यर्पण को लेकर आग्रह नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि नित्यानंद को लेकर हमारे पास जो सूचना है वह इतनी है कि किसी वेबसाइट के जरिये उसने अलग देश बनाने की घोषणा की है। लेकिन हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि वेबसाइट के जरिये देश नहीं बनता। लेकिन उसकी फरारी को लेकर हमारे पास कोई पक्की सूचना नहीं है। जहां तक उसके पासपोर्ट का सवाल है तो उसे काफी पहले रद कर दिया गया था।

स्वयंभू भगवान पर पहले से दुष्कर्म के आरोप : नित्यानंद का असली नाम राजशेखरन है और वह मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है। उसने सन 2000 में बेंगलुरु के नजदीक आश्रम बनाया। सन 2010 में एक हीरोइन के साथ आपत्तिजनक अवस्था में उसका वीडियो ऑनलाइन हुआ। इसके बाद दुष्कर्म के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था।

चीन ने अमेरिकी राजनयिकों पर लगाई जवाबी पाबंदियां

बीजिंग, एएफपी : अमेरिका में अपने राजनयिकों पर बंदिशें लगाए जाने के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उसने अपने यहां अमेरिकी राजनयिकों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। चीन ने शुक्रवार को बताया कि देश में अमेरिकी राजनयिकों के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। उन्हें स्थानीय अधिकारियों से मिलने से पहले अब विदेश मंत्रालय को सूचित करना होगा। अमेरिका ने भी गत अक्टूबर में चीनी राजनयिकों को आदेश दिया था कि वे अमेरिका में किसी अधिकारी से मिलने और किसी कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने से पहले विदेश मंत्रालय को सूचित करेंगे।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, 'चीन ने नए उपायों के बारे में अमेरिकी दूतावास को बुधवार को सूचित कर दिया है। यह कदम चीनी राजनयिकों पर अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में उठाया गया है। हम फिर यह आग्रह करते हैं कि अमेरिका अपनी गलतियों को सुधार ले और नियमों को रद कर दे।' अमेरिका ने चीन के इस कदम को पारस्परिक करार दिया ।

फ्लोरिडा नौसैनिक अड्डे में गोलीबारी शूटर समेत चार लोग मारे गए

पेंसाकोला, एपी : पेंसाकोला में नौसैनिक हवाई अड्डे के क्लासरूम भवन में एक हमलावर ने गोलीबारी की। गोलीबारी के दौरान हमलावर समेत चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस सप्ताह अमेरिकी नौसैनिक अड्डे में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार को एक अमेरिकी नौसैनिक ने दो लोगों की गोली मार कर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। एस्कांबिआ काउंटी के शेरिफ डेविड मोर्गन ने कहा कि ग्यारह लोगों को एक साथ गोली लगी है। इनमें शेरिफ के दो डिप्टी भी शामिल हैं। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले जवाब दिया और उनमें से एक ने हमलावर को मार गिराया। एक डिप्टी की बांह में और दूसरे के घुटने में गोली लगी है।

मोर्गन ने यह नहीं बताया कि हमलावर सेना से जुड़ा था या नहीं। उन्होंने कहा कि वह यह अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं कि यह गोलीबारी आतंकवाद से संबंधित है। कमांडिंग अधिकारी कैप्टन टिमोती किन्सेल्ला ने कहा कि अड्डे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और जबतक खाली कराना सुरक्षित नहीं होगा तबतक जो वहां हैं उन्हें वहीं रहना होगा। वेबसाइट के मुताबिक, पेंसाकोला में 16000 से ज्यादा सैनिक और 7400 असैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जुड डीरे ने कहा कि राष्ट्रपति को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। वह स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

अमेरिका में पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरों समेत चार की मौत

मियामी, एएफपी : अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे दो हथियारबंद लुटेरों को पुलिस ने मार गिराया। मियामी के नजदीक कोरल गैबल्स में गुरुवार को हुई इस मुठभेड़ में ज्वैलरी शोरूम में लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों के अलावा दो अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इनमें एक ट्रक चालक था जिसे बदमाशों ने भागने के लिए अगवा कर लिया था, जबकि दूसरा व्यक्ति मुठभेड़ की जगह से गुजर रहा एक राहगीर था।

ये भी जानिए

इविन लुइस ने भारत के खिलाफ अब तक सात टी-20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा 282 रन बनाए हैं। इसमें अमेरिका में खेली गई 125 रनों की अहम पारी भी शामिल है।

मैच के दौरान शॉट लगाते भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एएफपी

लक्ष्य का पीछा करने में हम सिकंदर

पहले टी-20 में भारत ने वेस्टइंडीज को छह विकेट से हराया, कोहली ने 50 गेंदों पर बनाए नाबाद 94 रन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय टीम भले ही आइसीसी विश्व टी-20 रैंकिंग में पांचवें स्थान पर मौजूद है, लेकिन टी-20 क्रिकेट में यह टीम एक मामले में सिकंदर है। विराट कोहली के धुरंधरों ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 208 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने कोहली की 50 गेंद में नाबाद 94 रनों की पारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। यह टी-20 क्रिकेट में भारत के द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शिमरोन हेटमायर (56) की आक्रमक पारी की बदौलत 20 ओवर में पांच विकेट पर 207 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 18.4 ओवर में ही चार विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर मैच छह विकेट से अपने नाम कर लिया।

रोहित का फ्लॉप शो : 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा (08) के जल्द आउट होने की वजह से खराब रही। रोहित ने सिर्फ 10 ही गेंद का सामना किया और खारे पियरे की गेंद पर हेटमायर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए।

राहुल-कोहली की जुगलबंदी : केएल राहुल (62) और कोहली ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कतई नहीं बख्शा। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी करके टीम इंडिया की नींव खड़ी कर दी। 100 रन की साझेदारी पूरी होते ही राहुल को पियरे ने पवेलियन भेज दिया। राहुल ने 40 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और चार छक्के लगाए।

कोहली का कारनामा : पारी की शुरुआत में कोहली के बल्ले पर ठीक से गेंद नहीं आ रही थी और उन्हें साफ जुझते हुए देखा जा सकता था। किसी तरह से कोहली ने राहुल का अच्छे से साथ दिया। राहुल जैसे ही आउट हुए, कमान पूरी तरह से कोहली के हाथों में आ गई। कोहली ने शुरुआती 44 रन 34 गेंद में लगाए, लेकिन अगले 50 रन पूरा करने के लिए कोहली को सिर्फ 16 गेंद का सामना करना पड़ा। कोहली ने इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 112वीं बार 75 से ज्यादा का स्कोर बनाया। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (168) हैं। साथ ही कोहली टी-20 में 23 अर्धशतक लगा चुके हैं और उन्होंने रोहित शर्मा (22) को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने 50 गेंद में छह चौके और छह छक्के की मदद से नाबाद 94 रन बनाए।

लुइस से कौन बचाए : इतिहास गवाह रहा है कि इविन लुइस (40) ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया है। अमेरिका में तीन वर्ष पहले लगाए गए उनके टी-20 शतक को कौन भूल सकता है। लुइस ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। लुइस ने शुरुआत से ही गेंद को सीमा पार पहुंचाना शुरू कर दिया। दीपक चाहर, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, तीनों ही गेंदबाजों को लुइस ने पावरप्ले में अच्छे से कूटा। 17 गेंद पर तीन चौके और चार छक्के लगाने के बाद लुइस खुद की गलती से ही पवेलियन लौटे। सुंदर की गेंद पर अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया, लेकिन लुइस ने रिव्यू नहीं लिया और रिप्ले में नजर आया कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर टिप्पा खा रही थी।

छूटे कैच, हुई फजीहत : पहले टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण का स्तर बेहद ही खराब रहा। एक ओर जहां भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने चौके नहीं बचाए, तो वहीं मैच में चार कैच छोड़कर खुद की ही फजीहत करा ली। पहले हेटमायर के कैच को शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े सुंदर समझ नहीं सके और गेंद तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद पारी के 16वें ओवर में पहले सुंदर ने ही हेटमायर का कैच छोड़ दिया और फिर इसके बाद अगली गेंद पर पोलार्ड का रोहित ने कैच टपका दिया। इससे अगली ही गेंद पर एक बार फिर रोहित ने पोलार्ड का कैच छोड़ा और छक्का हो गया। आखिरी ओवर में कोहली ने भी होल्डर का कैच टपका दिया।

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (गेंदबाजी) | मैन ऑफ द मैच : विराट कोहली

वेस्टइंडीज — **207/5** (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लेंडल सिमंस का. रोहित बो. चाहर	02	04	00	00
इविन लुइस एलबीडब्ल्यू बो. सुंदर	40	17	03	04
ब्रेंडन किंग स्टं. पंत बो. जडेजा	31	23	03	01
हेटमायर का. रोहित बो. चहल	56	41	02	04
कीरोन पोलार्ड बो. चहल	37	19	01	04
जेसन होल्डर नाबाद	24	09	01	02
दिनेश रामदीन नाबाद	11	07	01	00

अतिरिक्त : (लेबा-2, वा-4) 6
कुल : 20 ओवर में पांच विकेट पर 207 रन

विकेट पतन : 1-13 (लेंडल, 1.2), 2-64 (लुइस, 5.4), 3-101 (किंग, 10.1), 4-172 (हेटमायर, 17.1), 5-173 (पोलार्ड, 17.3)

गेंदबाजी : सुंदर 3-0-34-1, दीपक चाहर 4-0-56-1, भुवनेश्वर कुमार 4-0-36-0, रवींद्र जडेजा 4-0-30-1, चहल 4-0-36-2, शिवम दुबे 1-0-13-0

भारत — **209/4** (18.4 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. हेटमायर बो. पियरे	08	10	01	00
लोकेश राहुल का. पोलार्ड बो. पियरे	62	40	05	04
विराट कोहली नाबाद	94	50	06	06
रिषभ पंत का. होल्डर बो. कॉटरेल	18	09	00	02
श्रेयस अय्यर का. एवं बो. पोलार्ड	04	06	00	00
शिवम दुबे नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (बा-4, लेबा-2, नोबॉ-3, वा-14) 23
कुल : 18.4 ओवर में चार विकेट पर 209 रन

विकेट पतन : 1-30 (रोहित, 3.2), 2-130 (राहुल, 13.3), 3-178 (पंत, 16.2), 4-193 (अय्यर, 17.6)

गेंदबाजी : कॉटरेल 4-0-24-1, जेसन होल्डर 4-0-46-0, खारे पियरे 4-0-44-2, वाल्श जूनियर 2-0-19-0, विलियम्स 3.4-0-60-0, कीरोन पोलार्ड 1-0-10-1

परिणाम : भारत छह विकेट से जीता

52 विकेट युजवेंद्रा के हो गए हैं टी-20 अंतरराष्ट्रीय में। उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने के अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी की

अजहर के नाम पर स्टैंड

हैदराबाद, प्रेट्र : महान बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने पूर्व भारतीय कप्तान और हाल में हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने मुहम्मद अजहरुद्दीन के सम्मान में शुक्रवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में नॉर्थ स्टैंड का उद्घाटन किया, जिसे नया स्वरूप दिया गया है। लक्ष्मण ने रिबन काटकर स्टैंड को शुरू किया और इस मौके पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर नोएल डेविड, वेंकटपति राजू और तेज गेंदबाज मुहम्मद सिराज भी मौजूद थे। इस बारे में अजहर ने कहा कि मैं काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस सम्मान से नवाजा गया। मैंने हमेशा खेल भावना के अंतर्गत क्रिकेट खेला और हैदराबाद में इस खेल के विकास के लिए काम करता रहूंगा। इतने कम समय में यहां पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का इंतजाम करने के लिए किए गए प्रयास के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिस दिन मुंबई ने पहले टी-20 की मेजबानी में हिचकिचाहट दिखाई थी, तो मैंने वहीं अपने साथियों से कहा कि हम इसकी मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर मैंने बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली और मुंबई क्रिकेट संघ के अधिकारियों को संपर्क किया। बातचीत के बाद उन्हें मनाने में कामयाब रहा कि हैदराबाद मैच की मेजबानी के लिए तैयार है।

2021 में एक से अधिक डे-नाइट चाहता है ऑस्ट्रेलिया : गांगुली

कोलकाता, प्रेट्र : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 2021 में भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बीसीसीआइ से एक से अधिक डे-नाइट के टेस्ट खेलने का अनुरोध करेगा जब दोनों बोर्ड के अधिकारी अगले साल जनवरी में तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान मिलेंगे। हालांकि बीसीसीआइ प्रमुख सौरव गांगुली ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव 'कुछ ज्यादा ही' हो जाएगा।

कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट के पहले टेस्ट में भारत की जीत के बाद से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष अर्ल एडिंग्स की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल 14 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान बीसीसीआइ अधिकारियों से मिलेगा। एडिंग्स ने कहा कि भारत ने डे-नाइट का पहला टेस्ट खेल लिया है। अब वे इसके लिए तैयार होंगे। मुझे यकीन है कि वे डे-नाइट के और टेस्ट खेलेंगे। हमें जनवरी में इसका इंतजार रहेगा। गांगुली ने हालांकि कहा कि अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हमें कुछ कहा नहीं है। चार में से दो टेस्ट डे-नाइट के खेलना कुछ ज्यादा हो जाएगा। यह पारंपरिक टेस्ट मैचों की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हर सीरीज में एक मैच ऐसा हो सकता है। एडिंग्स ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि बीसीसीआइ आगामी सीरीज में एक और टेस्ट जोड़े।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत के खिलाफ पांच टेस्ट खेलें। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत डे-नाइट का टेस्ट खेलने को राजी हो गया है जो अच्छी बात है। इससे साबित होता है कि गांगुली को खेल की परवाह है। मैं जनवरी में हमारे बोर्ड के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर बीसीसीआइ के नए प्रशासन से इस पर बात करूंगा।

गांगुली बोले, धौनी तक पहुंचने में पंत को 15 साल लगेंगे: बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि महेंद्र सिंह धौनी ने अपने करियर में जो कुछ हासिल किया है, उसकी बराबरी करने में युवा विकेटकीपर रिषभ पंत को 15 साल लग जाएंगे। गांगुली ने हालांकि खराब दौर से गुजर रहे पंत का साथ दिया है और कहा कि वह आलोचनाओं से सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें।

गांगुली के मुताबिक खराब दौर में पंत को 'धौनी-धौनी' जैसे नारे भी सुनाई देंगे, लेकिन उन्हें इन्हें नजरअंदाज करना होगा। गांगुली ने कहा कि दबाव और चुनौतियां पंत के लिए अच्छी हैं। उन्हें इससे सीखने को मिलेगा। उन्हें धौनी-धौनी नारा सुनने दीजिए, क्योंकि इस तरह के दबाव से ही वह अपने लिए रास्ता निकालेंगे।

गांगुली ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट को धौनी के योगदान के लिए धन्यवाद करना चाहिए। धौनी ने जो हासिल किया है, उसे पाने में पंत को 15 साल लग जाएंगे। बकौल सौरव, धौनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ किया है, उसे हम सिर्फ धन्यवाद कहकर चुका नहीं सकते। हम इस संबंध में विचार कर रहे हैं। हम विराट कोहली व चयनकर्ताओं से बात कर रहे हैं और हम धौनी के भविष्य को लेकर सही समय पर निर्णय लेंगे।

उम्मीद

- बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव ने कहा, यह कुछ ज्यादा हो जाएगा
- जनवरी में होने वाली वनडे सीरीज में दोनों देशों के बोर्ड करेंगे बैठक

सौरव गांगुली, फाइल फोटो ● एएनआइ

सिर्फ अटकलें : सौरव गांगुली ने मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ मतभेदों की अटकलों को कोरी अफवाह बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लोगों को परखने का मानदंड बस प्रदर्शन होगा।

शास्त्री और गांगुली के बीच मतभेद 2016 में सार्वजनिक हुए थे जब शास्त्री ने कोच के पद के लिए आवेदन किया था और गांगुली उस समय क्रिकेट सलाहकार समिति में थे जिसने अनिल कुंबले को चुना था।

अगले साल शास्त्री कोच बने जब कुंबले ने कप्तान विराट कोहली के साथ मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। गांगुली ने कहा कि ये सब अटकलें हैं। मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। उनसे पूछा गया था कि अतीत के मतभेदों के कारण शास्त्री को लेकर उनके पूर्वग्रह हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करिए और पद पर बने रहिए। प्रदर्शन खराब होगा तो कोई और आएगा। जब मैं खेलता था, तब भी यही नियम था। उन्होंने कहा कि अटकलें, रहस्योद्घाटन और कयास लगते रहेंगे, लेकिन फोकस 22 गज के बीच प्रदर्शन पर रहना चाहिए। गांगुली ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदर्शन अहम है और उसका कोई विकल्प नहीं है। गांगुली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में कोहली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि वह कप्तान हैं। टी-20 विश्व कप 2020 के बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रारूप बेखौफ क्रिकेट खेलने के बारे में है। टीम में अपनी जगह पक्की करने की सोच लेकर मैदान पर ना उतरें।

क्रिकेटर से प्रशासक बने गांगुली ने कहा कि हितों के टकराव के मसले के कारण पूर्व क्रिकेटर प्रशासनिक भूमिका के लिए बोर्ड में नहीं आ पा रहे। सचिन जैसे खिलाड़ी को भी जाना पड़ा। यह प्रशासकों पर लागू होना चाहिए, क्रिकेटरों पर नहीं। गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बोर्ड के सचिव हैं, लेकिन गांगुली ने कहा कि जय शाह ने एक चुनाव जीता है। उनका निष्पक्ष आकलन किया जाना चाहिए। उसके पिता राजनेता हैं, लेकिन उनका आकलन निजी तौर पर होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभावी लोग खेल के संचालन में शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिवंगत अरुण जेटली खेल से प्यार करते थे लेकिन बीसीसीआइ में उन्होंने कोई पद नहीं लिया।

पांचवें दिन भारत ने जीते 41 पदक

काठमांडू, प्रेट्र: बैडमिंटन खिलाड़ियों की अगुआई में भारत ने यहां शुक्रवार को 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के पांचवें दिन 19 स्वर्ण सहित 41 पदक जीतकर शीर्ष पर स्थान मजबूत करते हुए अन्य देशों से अंतर बढ़ा लिया। भारत ने पांचवें दिन 18 रजत और चार कांस्य पदक के साथ अपने पदकों की कुल संख्या 165 पर पहुंचा दी, जिसमें 81 स्वर्ण, 59 रजत और 25 कांस्य शामिल हैं। इससे भारत दूसरे स्थान पर चल रहे नेपाल (41 स्वर्ण, 27 रजत और 48 कांस्य) से काफी आगे हो गया है। नेपाल के कुल पदक 116 हैं। श्रीलंका कुल 134 पदक (23 स्वर्ण, 42 रजत और 69 कांस्य) के साथ तीसरे स्थान पर है।

भारत के लिए शटलरों ने शुक्रवार को सबसे ज्यादा चार स्वर्ण पदक हासिल किए। उन्होंने स्पर्धा में दबदबा बनाते हुए चार स्वर्ण और दो रजत पदक अपने नाम किए। अश्मिता चालिहा और सिरील वर्मा ने यहां क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स वर्ग के बैडमिंटन मुकाबलों में स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके साथ ही ध्रुव कपिला ने पुरुष डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीत कर दोहरी सफलता हासिल की। जूनियर विश्व चैंपियन के पूर्व उप विजेता सिरील ने फाइनल मुकाबले में पहला गेम गंवाने के बाद आर्यमन टंडन को 17-21, 23-21, 21-13 से हराया। महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता ने हमवतन गायत्री गोपीचंद को करीबी मुकाबले में 21-18, 25-23 पराजित किया। ध्रुव और कृष्णा प्रसाद गारगा की युवा पुरुष सिंगल्स जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के सचिन डियाज और बुवानेका गुणातिलके की जोड़ी को 21-19, 19-21, 21-18 से हराया। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव और मेघना जक्कमपुडी की जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त श्रीलंका की सचिन डियाज और तिलिनि प्रमोदिका की जोड़ी को 21-16, 21-14 से हराया।

ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने 12 पदक जीते, जिसमें दो स्वर्ण शामिल रहे, जो पुरुष और महिला गोला फेंक स्पर्धा में मिले। पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में एशियाई चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.03 मीटर के थ्रो से स्वर्ण जीतकर सैग खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने इस तरह हमवतन बहादुर सिंह सागू के पिछले रिकॉर्ड (19.15 मीटर) को पीछे छोड़ा। एक अन्य भारतीय ओम प्रकाश करहाना 17.31 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहे। महिला गोला फेंक स्पर्धा में आभा खातुवा ने 15.32 मीटर की दूरी से पहला स्थान हासिल किया। हमवतन कंचना चौधरी ने कांस्य पदक जीता।

देश के तलवारबाजों ने भी सैग खेलों में तीन स्वर्ण और इतने ही रजत जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज की। वांगेलंबाम थोईबी देवी ने महिला फोयल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। हमतवन राधिका प्रसाद को रजत पदक मिला। पुरुषों की साबरे स्पर्धा में करण सिंह और कुमारेसन पद्म गिशोनिधी ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए। पुरुषों की इपी स्पर्धा में सुनील कुमार ने स्वर्ण, जबकि जयप्रकाश गुरुप्रकाश ने रजत पदक प्राप्त किया। टेबल टेनिस में भी भारतीयों ने पुरुष और महिला सिंगल्स में स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए।

दक्षिण एशियाई खेल

- 19 स्वर्ण, 18 रजत व चार कांस्य पर किया कब्जा
- भारत के कुल पदकों की संख्या 165 पर पहुंची

स्वास्तिक ने 585 रन की पारी खेलकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

शाहनवाज अली ● गाजियाबाद

दीवान क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे 19वें शहीद रामप्रसाद बिस्मिल स्मृति ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में दो विश्व रिकॉर्ड बने हैं। यहां माही क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए गाजियाबाद के स्वास्तिक चिकारा ने क्लब क्रिकेट में सीमित ओवर के मैच में 585 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के शेन डेड्सवेल ने 2017 में 490 रन बनाकर यह कीर्तिमान बनाया था। वहीं, टीम ने सीमित ओवर के मैच में 704 बनाकर सर्वाधिक टीम स्कोर का क्लब क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड यूनाइटेड क्लब टीम के नाम दर्ज था। अमेरिका के रिचमंड कैलिफोर्निया में वर्ष 2006 में यूनाइटेड क्लब ने बे एरिया के खिलाफ 45 ओवर के मैच में 630 रन बनाए थे।

माही अकादमी के ओपनर 16 वर्षीय स्वास्तिक ने 167 गेंदों पर 52 छक्कों और 55 चौकों की मदद से 40 ओवर के मैच में 585 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही वह दुनिया में सबसे कम उम्र में यह रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के शेन डेड्सवेल के नाम दर्ज था, जिन्होंने 20 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। डेड्सवेल ने दक्षिण अफ्रीका के शहर पोचेस्ट्रूम में नॉर्थ-वेस्ट यूनीवर्सिटी पुके की तरफ से खेलते हुए 50 ओवर के मैच में पोर्स ड्रॉप क्लब के खिलाफ वर्ष 2017 में 490 रन बनाए थे। इस मैच में उनकी टीम ने 387 रनों से जीत हासिल की थी। पोर्स ड्रॉप की टीम नौ विकेट पर 290 रन ही बना सकी थी।

वहीं भारत में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इससे पूर्व भी स्वास्तिक के नाम ही दर्ज है। उन्होंने 40 ओवर के मैच में 148 गेंदों पर 356 रन बनाए थे। किसी भी टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बात करें तो यह विश्व रिकॉर्ड भी गाजियाबाद में दीवान क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में बना, जिसमें माही अकादमी की टीम ने वर्ष 2006 में अमेरिका के रिचमंड कैलिफोर्निया में 45 ओवर के मैच में यूनाइटेड क्लब ने बनाए गए 630 रन के स्कोर को पीछे छोड़ते हुए 704 रन बनाए।

22 दोहरे व सात तिहरे शतक : गाजियाबाद में चल रहे लीग टूर्नामेंट में स्वास्तिक के नाम रिकॉर्ड 585 रन के अलावा कई अन्य रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इससे पूर्व वह ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के अलावा अंडर-14 व अंडर-16 प्रतियोगिताओं में 22 दोहरे शतक व सात तिहके शतक लगा चुके हैं। उनके पिता के मुताबिक, स्वास्तिक ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी तक करीब 100 से अधिक शतक बना चुके हैं। स्वास्तिक वर्ष 2018 व 2019 में लगातार दो बार यूपीसीए का अंडर-16 कैंप कर चुके हैं। स्वास्तिक का सपना भारतीय टीम में शामिल होना है।

10 बीघा जमीन पर घर और मैदान में हैं 12 पिच : स्वास्तिक के पिता सुरेंद्र सिंह भारतीय एथलीट रहे हैं। वह सर्विसेज के अलावा देश के लिए पांच और 10 हजार मीटर की दौड़ में भाग ले चुके हैं। अटौर नंगला में करीब 10 बीघा में उनके घर के अलावा स्वास्तिक के लिए जिम, फ्लड लाइट युक्त ग्राउंड पर दर्जनभर पिच हैं। इसमें इन स्विंग, आउट स्विंग, फास्ट एवं स्पिन के लिए अलग-अलग पिच हैं।

द. अफ्रीका के शेन डेड्सवेल का 490 रनों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, माही क्रिकेट क्लब ने 704 रन के साथ बनाया सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड

पिता सुरेंद्र चिकारा के साथ स्वास्तिक चिकारा ● जागरण

मूल रूप से हरियाणा के हैं स्वास्तिक चिकारा

मूल रूप से हरियाणा के जनपद झज्जर में खेड़ी आसरा गांव के रहने वाले स्वास्तिक बचपन से गाजियाबाद के अटौर नंगला (राजनगर एक्सटेंशन) में रहते हैं। उनके पिता सुरेंद्र चिकारा दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। पिता खुद क्रिकेट के शौकीन हैं। उन्होंने अपने शौक को अपने बेटे स्वास्तिक का करियर बनाने की सोची और चार साल की उम्र में ही उन्हें बल्ला थमा दिया। स्वास्तिक ने शौकिया खेलने वाले अपने पिता सुरेंद्र चिकारा की कोचिंग में क्रिकेट का ककहरा सीखा।

समर्पण भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल दिव्यांश के पिता का सपना हुआ पूरा, रोजी-रोटी के लिए पिता श्याम को छोड़ना पड़ा था खेलों का शौक

दफन सपनों को बेटे में देखा तो लगा दी जी जान

जागरण विशेष

चंद्रशेखर वर्मा ● ग्रेटर नोएडा

उनका भी सपना था कि एथलीट बनूं। खेल की दुनिया में शोहरत पाऊं। रोजी-रोटी के लिए अरमानों को दफन करना पड़ा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने सपनों और शौक को अपने बेटे में पहचाना। उसके हुनर को बढ़ावा दिया। आज श्याम प्रकाश जोशी का बेटा दिव्यांश जोशी भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल होकर देश के लिए खेलने को तैयार है। उनका परिवार सेक्टर-अल्फा-2 में रहता है। पिता के साथ मां ने भी बेटे के लिए जो सपना संजोया था, बेटे ने अंडर-19 टीम में शामिल होकर गुरु दक्षिणा के तौर पर वापस किया।

श्याम प्रकाश के परिवार में बेटा दिव्यांश के अलावा पत्नी शशि जोशी और बड़ी बहन रिकांक्षी जोशी हैं। मूलरूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले श्याम अपने पिता के साथ वर्ष 1974 में दिल्ली आ गए थे। बचपन में आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। बड़े हुए तो नौकरी करनी शुरू कर दी, साथ में पढ़ाई भी पूरी की। बचपन में एथलेटिक्स का काफी शौक था। बेन जोहंसन के 100 मीटर दौड़ में 9.98 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे, लेकिन रोजी-रोटी के लिए सपने का दफन करना पड़ा। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वर्ष 2003 में ग्रेटर नोएडा आ गए। कुछ पैसे एकत्रित हुए तो जमीन खरीद ली और एक कमरे का मकान बनाया। जमीन के बाकी के हिस्से को बच्चों के खेलने के लिए छोड़ दिया। श्याम भी हर अभिभावक की तरह दिव्यांश को डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाना चाहते थे। वह जब छह वर्ष का था। एक दोस्त ने बात कही कि पांच से लेकर 12 वर्ष की उम्र में बच्चे से भरपूर प्यार मिलता है। इसके बाद दिव्यांश के साथ घर पर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया।

उन्होंने बताया कि क्रिकेट के तकनीक की जानकारी नहीं थी तो किताबों से लेकर इंटरनेट का सहारा लिया। वहां की जानकारी दिव्यांश को बताने लगे। 10 वर्ष तक उसने कोई भी मैच नहीं खेला था। साढ़े 10 वर्ष की आयु में दिल्ली में पहला मैच खेला और करीब 86 रन बनाए। इसके बाद दिल्ली में कोच तारक सिन्हा के पास ले गए। दिल्ली से रोजाना उसको लाते और ले जाते थे। इसके लिए कई बार छुट्टी तक लेनी पड़ती थी। स्टेडियम में सुविधा नहीं थी तो एस्टर पब्लिक स्कूल ने काफी साथ दिया। अब उसको भारतीय टीम के लिए खेलते देखना मकसद है।

कोच बताते तो नोट कर लेते: श्याम प्रकाश ने बताया कि बच्चे छोटे होते हैं तो एक बार में समझ नहीं आता। उनको कई बार समझाना होता है। दिल्ली में कोचिंग के दौरान डायरी पकड़कर खड़े रहते थे। कोच जैसे ही कुछ बताते, वह तुरंत नोट कर लेते। फिर घर आकर दिव्यांश के साथ चर्चा करते।

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल दिव्यांश जोशी ● सौ.स्वजन

दिव्यांश जोशी के बारे में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा दो स्थित अपने आवास पर जानकारी देते पिता श्याम प्रकाश जोशी और मां शशि जोशी ● राजेश गौतम

...जब लारा पर हावी हो गया था दबाव

मुंबई, प्रेट्र : मानसिक स्वास्थ्य के मसलों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वास्तविक बताते हुए वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने शुक्रवार को रहस्योद्घाटन किया कि अपने करियर के चरम पर उन्हें 'निराशा का सामना' करना पड़ा था। लारा के नाम प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट में दो बार (1994 और 2004) यह रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो चुका है।

यहां एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए आए कैरेबियाई दिग्गज लारा ने कहा, 'मेरे अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत (1989) से 1995 तक करियर ग्राफ ऊपर की तरफ ही गया। लेकिन, 1995 से 1998 के बीच प्रदर्शन गिरा। मुझे दोहरे विश्व रिकॉर्ड अपने नाम होने का दबाव महसूस हुआ और उस समय कैरेबियाई क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भी खराब था। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में निराशा से घिरा बैठा रहता था। मानसिक स्वास्थ्य का मसला वास्तविक है। सभी खेलों में यह होता है और अब खिलाड़ी इस पर बात करने लगे हैं।'

हाल ही में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल समेत ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्रिकेटरों ने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से क्रिकेट से ब्रेक लिया था। लारा ने कहा, 'आजकल खिलाड़ी इतनी तरह के दबाव में हैं। पिछली सदी के आठवें व नौवें दशक में खेल से प्यार के चलते देश के लिए खेलते थे। अब इतना फ्रैंचाइजी क्रिकेट हो रहा है और कई बार इतनी व्यस्तता बोझ बन जाती है।'

बेहतर टीम के रूप में लौटें : लारा ने कहा कि कीरोन पोलार्ड की अगुआई वाली टीम को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बेहतर टीम के रूप में लौटना चाहिए, भले ही वह जीतने में नाकाम रहे। लारा ने कहा, 'पोलार्ड को टीम बनानी होगी। भारत में खेलना हमेशा कठिन चुनौती होता है। भले ही जीत मिले या नहीं, लेकिन उन्हें टूर्नामेंट के बाद बेहतर टीम के रूप में लौटना चाहिए।'

पोलार्ड का समर्थन : लारा ने सीमित ओवरों के प्रारूप में पोलार्ड को कप्तान बनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'वेस्टइंडीज के लिए भले ही वह इतना नहीं खेले हों, लेकिन दुनिया भर में लीग खेले हैं। साथी व विरोधी उनका सम्मान करते हैं। उन्हें कप्तान बनाने का फैसला बुरा नहीं है। अगले 12 महीने के भीतर टी-20 विश्व कप होना है और उनके पास अपार अनुभव है। यह अच्छा फैसला है, लेकिन उनके सामने चुनौती आसान नहीं है। इस प्रारूप में टीमें वेस्टइंडीज से खौफ खाती हैं।'

गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान मुंबई में (बायें से) भारतीय बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर, गोल्फर राशिद खान व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ● प्रेट्र

मनप्रीत एफआइएच के शीर्ष पुरस्कार के लिए नामित

लुसाने, प्रेट्र : भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने वर्ष का खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया है। उनकी अगुआई में भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। दो अन्य भारतीयों विवेक प्रसाद और लालरेमसियामी को एफआइएच ने क्रमश : पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष उदीयमान स्टार पुरस्कार के लिए नामित किया है।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के निदेशक ग्रीम स्मिथ और कोच मार्क बाउचर को बनाया चाहिए।
– केविन पीटरसन, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज

फुटबॉल डायरी ▶ नील ने अहम गोल कर ब्राइटन को 2-1 से जीत दिलाई, 45 मिनट तक गोल नहीं कर पाई आर्सेनल

ब्राइटन ने ईपीएल में आर्सेनल को चौंकाया

न्यूकैसल ने शेफील्ड युनाइटेड को 2-0 से दी मात

लंदन, एएफपी : ब्राइटन की टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के मैच में आर्सेनल को 2-1 से हराकर उसे चौंका दिया, तो वहीं न्यूकैसल को भी शेफील्ड युनाइटेड को 2-0 से हराने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ब्राइटन को जीत नील मौपे ने दिलाई, जिन्होंने 1-1 के स्कोर के बाद टीम के लिए उपयोगी गोल किया। ब्राइटन के लिए अन्य गोल एडम वेबस्टर ने किया, जबकि आर्सेनल के लिए एकमात्र गोल एलेक्जेंडर लैकजेट ही कर पाए। इस जीत के बाद ब्राइटन की टीम अंक तालिका में 13वें स्थान पर आ गई, जबकि आर्सेनल 10वें स्थान पर है।

मैच के शुरुआती 45 मिनट तक ब्राइटन की टीम ने आर्सेनल को गोल नहीं करने दिया, जबकि 36वें मिनट में वेबस्टर ने बॉक्स के अंदर से गोल करके टीम को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। पहला हाफ 1-0 से ब्राइटन के नाम रहा। दूसरे हाफ में लैकजेट ने 50वें मिनट में ओजिल की मदद से गोल कर आर्सेनल की मैच में वापसी करा दी। हालांकि, जब मैच खत्म होने में 10 मिनट बचे थे तब नील ने आर्सेनल के दो खिलाड़ियों को छकाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया और ब्राइटन 2-1 से मैच में आगे हो गया। मैच के अंतिम समय तक कोई और गोल नहीं हुआ और ब्राइटन ने जीत हासिल की।

वहीं न्यूकैसल, शेफील्ड युनाइटेड को हराकर अंक तालिका में 11वें स्थान पर आ गया, जबकि शेफील्ड की टीम नौवें स्थान पर ही है। दोनों टीमों के समान 19-19 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के आधार पर शेफील्ड की टीम तालिका में नौवें नंबर पर विराजमान है। न्यूकैसल के लिए गोल एलन सेंट मैक्सीमिन ने 15वें मिनट में किया, जबकि जॉन्जो शैल्वी ने 70वें मिनट में गोल करके टीम का जीत का अंतर 2-0 कर दिया।

इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल के खिलाफ गोल करने के बाद ब्राइटन के खिलाड़ी नील मौपे। रायटर

एवर्टन ने मैनेजर मार्को सिल्वा को बर्खास्त किया

लंदन, आइएएनएस : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के क्लब एवर्टन ने अपने मैनेजर मार्को सिल्वा को बर्खास्त कर दिया। उनके स्थान पर डंकन फर्गुसन को फिलहाल टीम का चार्ज दिया गया है। एवर्टन को अपने पिछले ईपीएल मैच में लिवरपूल के हाथों शर्मनाक हार मिली थी। इसी को देखते हुए क्लब प्रशासन ने सिल्वा को कार्यमुक्त किया। अब क्लब ने सत्र के बाकी बचे मैचों के लिए नए मैनेजर की तलाश शुरू कर दी है और मैनचेस्टर युनाइटेड के पूर्व कोच डेविड मोएस का नाम संभावित कोचों में सबसे आगे है। अगर मोएस मैनेजर बनते हैं तो टीम काहिल उनके सहायक हो सकते हैं।

माने का बैलन डि ओर मतदान सूची में चौथे स्थान पर आना शर्मनाक : मेसी

मैड्रिड, आइएएनएस : अर्जेंटीना और बार्सिलोना के सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी ने कहा है कि बैलन डि ओर मतदान सूची में लिवरपूल के फॉरवर्ड सादियो माने का चौथे स्थान पर आना वाकई बहुत शर्मनाक है। इस सप्ताह की शुरुआत में मेसी ने दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिए जाने वाले बैलन डि ओर पुरस्कार को रिकॉर्ड छठी बार अपने नाम किया। माने को मेसी, वर्जिल वान डिज्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद चौथा स्थान मिला। मेसी ने कहा, 'यह शर्मनाक है कि माने चौथे स्थान पर आए। मैं समझता हूं कि इस साल इस खिताब की दौड़ में कई महान खिलाड़ी शामिल थे। पर मेरी नजर में माने साल के श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूं।'

पेले की आखिरी ब्राजीली जर्सी इटली में बिकी

मिलान, एएफपी : ब्राजीली फुटबॉल दिग्गज पेले ने अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान जो जर्सी पहनी थी उसे इटली में एक नीलामी में 33,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 24 लाख रुपये) में बेचा गया। तीन बार के विश्व कप विजेता पेले ने यह जर्सी युगोस्लाविया के खिलाफ जुलाई 1971 में रियो डि जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में खेले गए मैत्री मैच के दौरान पहनी थी। यह पेले का ब्राजील की तरफ से आखिरी मैच था। पेले अभी 79 साल के हैं और उन्हें सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में गिना जाता है। उन्होंने ब्राजील की तरफ से 92 मैचों में 77 गोल किए। इसी नीलामी में अर्जेंटीना के दिग्गज डिएगो मैराडोना की 1989-90 सत्र में नापोली की तरफ से खेलते हुए पहनी गई जर्सी 8318 अमेरिकी डॉलर (लगभग छह लाख रुपये) में बिकी। अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जोर्डन ने बेसबॉल में भी हाथ आजमाए थे। इस दौरान उन्होंने जिस बल्ले का उपयोग किया, वह 471 अमेरिकी डॉलर (लगभग 34 हजार रुपये) में बिका।

ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद संन्यास लेंगीं वोज्नियाकी

डेनमार्क की महिला टेनिस खिलाड़ी कैरोलाइन वोज्नियाकी। एपी

पेरिस, एएफपी : विश्व की पूर्व नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी कैरोलाइन वोज्नियाकी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अगले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। डेनमार्क की 29 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में अपना एकमात्र ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब जीता था।

उन्होंने इस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'मैंने कोर्ट पर जो कुछ हासिल करने का सपना देखा था उसे हासिल किया।' वोज्नियाकी 2005 में 15 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बनी थीं और अक्टूबर 2010 में विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंची थीं। उन्होंने अब तक 30 डब्ल्यूटीए खिताब जीते हैं जिनमें 2017 का टूर फाइनल्स भी शामिल है। इसके अलावा वह 11 लगातार सत्रों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष-20 में रही थीं। हालांकि इस साल वह चोट और खराब फॉर्म से जूझती रहीं और सिर्फ एक टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच पाईं। उनकी अभी विश्व रैंकिंग 37 है। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहती हैं। वोज्नियाकी पूर्व एनबीए चैंपियन डेविड ली की पत्नी हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ महीनों में मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हैं और अब परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है।' ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 14 जनवरी से होगी। इसके अलावा वह दो बार ग्रैंडस्लैम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची थीं जहां दोनों बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साल 2009 में किम क्लाइजर्स ने, जबकि उनकी अच्छी दोस्त सेरेना विलियम्स ने 2014 में वोज्नियाकी को यूएस ओपन के फाइनल में मात दी थी।

भारतीय वॉलीबॉल संघ को झटका

नई दिल्ली, जेएनएन

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय वॉलीबॉल महासंघ (वीएफआइ) को झटका देते हुए प्रो वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के आयोजन को लेकर जारी विवाद में बेसलाइन वेंचर्स द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

बेसलाइन वेंचर्स द्वारा दाखिल निषेध आवेदन पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने चार दिसंबर तक की यथास्थिति का आदेश दिया और दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। बेसलाइन वेंचर्स इस मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए पहले से ही वीएफआइ की कार्यकारी समिति को एक पत्र भेजकर मीटिंग के लिए समय और तारीख तय करने की मांग कर चुका है। वीएफआइ ने 18 नवंबर को पीवीएल के आयोजन को लेकर बेसलाइन के साथ हुए 10 साल के करार को रद कर दिया था। यह फैसला वीएफआइ के एजीएम में किया गया था, जो जयपुर में हुआ था। वीएफआइ ने कहा था कि वह खुद की लीग शुरू करना चाहता है।

ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश वीएफआइ के लिए तगड़ा झटका है क्योंकि कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस संबंध में वीएफआइ अगले दो सप्ताह तक किसी भी फ्रेंचाइजी, स्पांसर या फिर प्रसारणकर्ता से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि पहले उसे बेसलाइन के साथ जारी विवाद का समाधान निकालना है।

सोनिया, मीना राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में

स्वर्ण जीतने के बाद जश्न मनाती सोनिया। आइएएनएस

कुन्नूर (केरल), आइएएनएस : सोनिया चहल और मीना कुमारी देवी ने शुक्रवार को यहां जारी चौथी महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ दोनों मुक्केबाजों ने अपने लिए पदक पक्का कर लिया है। वर्ष 2016 में स्वर्ण और 2017 में कांस्य पदक जीतने वाली सोनिया ने 57 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश की विनाक्षी को कड़े मुकाबले में 3-2 से मात दी।

ऑल इंडिया पुलिस की मीना कुमारी देवी ने 54 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में झारखंड की सबीहा खानम को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। अर्जुन अवार्डी कविता चहल ने 81 प्लस किलोग्राम भारवर्ग में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दो बार कांस्य पदक जीतने वाली कविता ने स्वर्ण पदक के करीब अपने कदम बढ़ाते हुए राजस्थान की बरबार संपसन को 5-0 से हरा दिया।

पूर्व यूथ विश्व चैंपियन शशि चोपड़ा ने 60 किलोग्राम भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ की मंजू को 5-0 से करारी शिकस्त दी। उनके अलावा पूर्व यूथ विश्व चैंपियन असम की अंकुशिता बोरो ने 64 किलोग्राम भारवर्ग में अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए मिजोरम की अबिसाक वानलालवामावी को 5-0 से ही पराजित किया। इंडिया ओपन चैंपियन भाग्यवती कचारी ने 81 किलोग्राम भारवर्ग में अपना आक्रामक प्रदर्शन जारी रखा। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए रेफरी को पहले राउंड में ही तेलंगाना की सारा कुरैशी के खिलाफ मुकाबला रोकना पड़ा।

राजस्थान की ललिता और दिल्ली की अंजलि ने 69 किलोग्राम भारवर्ग के अपने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया। हरियाणा की नूपुर ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में उत्तराखंड की नेहा चौहान के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और रेफरी को पहले राउंड में ही मुकाबले को रोकना पड़ा।

इंडिया ओपन की उपविजेता वलाल दौती को 51 किलोग्राम भारवर्ग में मध्य प्रदेश की दीप कुमारी को 5-0 से हराकर अंतिम चार में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई जबकि चंडीगढ़ की रितु ने 57 किलोग्राम भारवर्ग में दिल्ली की ज्योति को 5-0 से करारी मात दी।

पंजाब की मुक्केबाजों में परमिंदर कौर (81 किलोग्राम भारवर्ग), मीनाक्षी (48 किलोग्राम भारवर्ग) और मंदीप कौर संधु (57 किलोग्राम भारवर्ग) ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

विविध

अवैध संबंधों के शक में पत्नी और बहू की हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

रिश्तों का खून

- बुजुर्ग ने बीचबचाव करने आए छोटे बेटे को भी चाकू से किया घायल
- रोहिणी सेक्टर-चार में परिवार के साथ रहता था आरोपित, गिरफ्तार

रोहिणी इलाके में शुक्रवार तड़के एक बुजुर्ग ने चाकू घोंपकर पत्नी और एयरहोस्टेस बहू की हत्या कर दी। आरोपित ने बीच बचाव करने आए छोटे बेटे को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। मृतकों की पहचान स्नेहलता (62) और बहू प्रज्ञा चौधरी (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से ही आरोपित सतीश चौधरी (64) को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी और बहू के दूसरों के साथ अवैध संबंध थे। पत्नी व बहू उसे छोड़कर शुक्रवार को गुरुग्राम में नए मकान में रहने के लिए जाने वाली थीं। ऐसे में वह इस बात से परेशान था कि दोनों उससे दूर रहेंगी और वह उन पर नजर नहीं रख सकेगा। दोनों वहां मनमानी करेंगी। इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। इसलिए उसने दोनों की हत्या कर दी। बहू प्रज्ञा के मायके वाले अवैध संबंधों की बात को सिरे से खारिज कर इसे आरोपित की मनगढंत कहानी बता रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से बतौर क्लर्क एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुकीं स्नेहलता परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर-चार स्थित शिवा अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल स्थित फ्लैट नंबर बी-6/119 में रहती थीं। परिवार में पति सतीश चौधरी, दो बेटे गौरव व सौरभ, गौरव की पत्नी प्रज्ञा और उनके दो बच्चे, बेटी आरोही (4) व बेटा आर्यन (1) हैं। गौरव सिंगापुर में आइबीएम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गौरव की पत्नी प्रज्ञा एक एयरलाइंस कंपनी में एयरहोस्टेस थीं। वहीं सौरव बेंगलुरू में इंजीनियर हैं जो इस समय छुट्टी लेकर घर आए हुए हैं। आरोपित सतीश पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। लेकिन इन दिनों कोई काम नहीं करता था।

आरोपित सतीश को ले जाते पुलिसकर्मी। जागरण

इस तरह दिया वारदात को अंजाम : प्रज्ञा दोनों बच्चों व सास के साथ अपने कमरे में सो रही थीं। सौरव ड्राइंग रूम में और आरोपित अपने कमरे में सो रहा था। शुक्रवार सुबह चार बजे आरोपित उठा और ड्राइंग रूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे सौरव बाहर न आ सके। इसके बाद वह दूसरे कमरे में घुसा और सब्जी काटने वाले चाकू से प्रज्ञा के पेट व छाती पर छह से सात वार किए, फिर गला रेत दिया।

प्रज्ञा की चीख सुनकर बगल में सो रहीं स्नेहलता जग गईं। वह बहू को बचाने आईं तो आरोपित ने उन पर भी हमला कर दिया। वह किसी तरह से भागीं और ड्राइंग रूम की कुंडी खोली। इसके बाद ड्राइंग रूम के बाहर आकर सौरव ने अपने पिता को काबू करना चाहा तो उसने उनको भी घायल कर दिया। हालांकि सौरव ने किसी तरह पिता को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से दोनों घायलों को रोहिणी के बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में भेजा। वहां डॉक्टरों ने प्रज्ञा को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के दौरान कुछ ही देर में स्नेहलता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रज्ञा के पति गौरव के सिंगापुर से आने के बाद शनिवार को शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एसडी मिश्रा, जिला पुलिस उपायुक्त, रोहिणी

आयुर्वेद संकाय सहित संस्कृत विभाग में भी चयनित हुए डॉ. फिरोज

जासं, वाराणसी : डॉ. फिरोज खान संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में पढ़ाएंगे, आयुर्वेद संकाय में ज्वाइन करेंगे या फिर उनकी पसंद कला संकाय का संस्कृत विभाग होगा। सब कुछ उन्हीं की मर्जी पर निर्भर है, क्योंकि आयुर्वेद संकाय सहित संस्कृत विभाग के लिए उनका चयन किया गया है। आयुर्वेद संकाय के लिए 29 नवंबर व संस्कृत विभाग के लिए 4 दिसंबर को डा. फिरोज खान साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल हुए थे। आयुर्वेद में जहां वह पहले नंबर पर थे, वहीं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी की तीन सीटों पर 39 उम्मीदवार साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए शार्टलिस्ट किए गए थे। इनमें फिरोज 11वें नंबर पर थे। सूत्रों के अनुसार आयुर्वेद संकाय सहित संस्कृत विभाग में भी उनका चयन कर लिया गया है। अब 7 दिसंबर को कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिफाफे खोले जाएंगे।

फिरोज खान की नियुक्ति 5 नवंबर को संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में हुई थी। कुछ छात्रों ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था।

कैडेटों ने दिया शारीरिक और मानसिक संतुलन का परिचय

जागरण संवाददाता, देहरादून

- आइएमए में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन

भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड से पहले तमाम गतिविधियां आयोजित की गईं। शुक्रवार को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में पासिंग आउट बैच के जेंटलमैन कैडेटों ने हैरतंगेज करतब दिखाकर हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सोमनाथ स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में बैठा हर शख्स रोमांच से भर गया।

कैडेटों ने माइक्रो एयर लाइट क्राफ्ट, घुड़सवारी, ट्रिक राइडिंग, रिंग फायर जंपिंग, टेंट पेगिंग, पीटी डिस्प्ले आदि से शारीरिक व मानसिक संतुलन का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बॉयो सेंसर डॉग स्क्वायड टीम का प्रदर्शन देखकर भी दर्शक गद्गद हो गए। वहीं, मराठा लाइट इंफ्रेंट्री की पांचवीं बटालियन की मलखंभ टीम ने भी शानदार साहसिक प्रदर्शन से सभी को हैरत में डाल दिया।

शहीद सैन्य अधिकारियों की जांबाजी को नमन : भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को पीओपी में शिरकत कर पास आउट होने वाले 377 जेंटलमैन कैडेटों ने शुक्रवार सुबह आइएमए युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। युद्ध स्मारक में आइएमए से पास आउट हुए उन 854 सैन्य अफसरों के नाम अंकित हैं जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। अकादमी के समादेशक ले. जनरल एसके झा समेत अकादमी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों व पासिंग आउट बैच में शामिल देश-विदेश के जेंटलमैन कैडेटों ने वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सैन्य अफसरों की शहादत को नमन किया।

सतरंगी प्रकाश में जगमग हुआ चेटवुड भवन

शुक्रवार की शाम को भारतीय सैन्य अकादमी का ऐतिहासिक चेटवुड भवन सतरंगी प्रकाश से जगमग हो गया। मौका था ऐतिहासिक चेटवुड भवन के ठीक सामने ड्रिल स्क्वायर पर पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर आयोजित 'साउंड एंड लाइट शो' का। इसके जरिये दिखाया गया कि अकादमी की स्थापना से लेकर वर्तमान तक यानी आठ दशक से अधिक के सफर में आइएमए में जेंटलमैन कैडेटों को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही अकादमी के संरचनात्मक ढांचे में कितना बदलाव हुआ है। अतीत में अकादमी की तस्वीर कैसी थी और वर्तमान में कितनी परिवर्तित हुई है। वहीं 64 जूनियर कैडेटों ने अपने सीनियर (पासिंग आउट बैच के कैडेट) को सैल्यूट कर अकादमी से विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आइएमए के समादेशक ले. जनरल एसके झा, डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल जीएस रावत समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और विदेशी मेहमान भी साउंड एंड लाइट शो देखकर गद्गद हुए।

फारूक अब्दुल्ला ने शशि थरूर को लिखा पत्र, कहा-हम अपराधी नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पिछले चार महीने से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में चल रहे नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ अपना दर्द साझा किया है। थरूर को लिखे पत्र में फारूक ने लिखा कि वह कोई अपराधी नहीं हैं। अपने लेटरहेड पर लिखे पत्र में फारूक ने अपना निवास सब जेल लिखा है।

अब्दुल्ला को पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हिरासत में लिया गया था। बाद में यह जानकारी दी गई थी कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्हें उनके गुपकार रोड स्थित निवास पर ही रखा गया है, जिसे सब जेल का दर्जा दिया गया है। केरल से कांग्रेस सांसद थरूर ने 21 अक्टूबर को फारूक को पत्र लिखा था। यह पत्र उन्हें दो दिसंबर को मिला। इस पत्र में क्या लिखा गया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फारूक ने अपने जवाब में थरूर को उन्हें पत्र लिखने के लिए धन्यवाद दिया। फारूक ने कहा कि उन्हें

डॉ. फारूक अब्दुल्ला। (फाइल)

21 अक्टूबर को भेजा गया पत्र दो दिसंबर को मिला। यह पत्र उन्हें सब जेल देख रहे मजिस्ट्रेट ने दिया। फारूक ने लिखा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें पत्र भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है।

उन्होंने लिखा कि हम अपराधी नहीं हैं। इस पत्र को साझा करते हुए थरूर ने लिखा कि सांसद को संसद की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। नहीं तो हिरासत में लेकर विपक्ष की आवाज को दबाना सरकार के लिए एक हथियार बन जाएगा। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सांसद कार्यवाही में भाग लें।

मिशन पूरा कर गृह मंत्रालय लौटे के विजय

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल के सलाहकार रहे के. विजय कुमार को अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय का वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ष 1975 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी कुमार केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के सुरक्षा संबंधी मामलों पर गृह मंत्रालय को सलाह देंगे।

कुमार जम्मू-कश्मीर में सलाहकार बनाने से पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार थे। ऐसे में वह जम्मू-कश्मीर में अपना मिशन पूरा करने के बाद फिर से पुरानी भूमिका में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन दिसंबर को जारी नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि कुमार अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

67 वर्षीय कुमार की जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने में अहम भूमिका रही है। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने से लेकर अलगाववादियों पर लगाम लगाने में भी उनकी रणनीति काम आई। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी जम्मू-कश्मीर में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि के. विजय कुमार की सीधी नजर जम्मू-कश्मीर पर रहेगी।

कुमार के सामने ये रहेंगी चुनौतियां

जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वह सीमा पर गोलाबारी करने के साथ आतंकवाद को फिर बढ़ाने पर लगा है। आतंकवाद पर पूरी तरह नकेल बड़ी जिम्मेदारी होगी।

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद है। इसे शुरू करने से पहले हालात की सुरक्षा संबंधी समीक्षा। इंटरनेट शुरू होने के बाद भी हालात पर नजर।

कश्मीर के युवाओं में अलगाव की सोच को दूर कर मुख्यधारा में जोड़ने में कुमार का अनुभव काम आएगा।

पर्यटकों के साथ धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा व उसे सुचारु चलाना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी।

आतंकवाद के खिलाफ अभियान को दी तेजी : सेवानिवृत आइपीएस अधिकारी ने जून 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के रूप में पुलिस को चाक चौबंद कर ऐसे हालात बनाए, जिससे श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के साथ कश्मीर में अलगाववादियों को काबू करना व अनुच्छेद 370 हटाने के बाद स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना संभव हुआ। नक्सलवाद से निपटने का उनका अनुभव जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद व अलगाववाद की समस्या से निपटने में भी कारगर साबित हुआ। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में देश विरोधी तत्वों को कमजोर कर दिया और आतंकवाद के खिलाफ अभियान को तेजी दी।

निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारी : के. विजय कुमार कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में खासी महारत रखते हैं। वह सीमा सुरक्षा बल के आइजी के रूप में कश्मीर में वर्ष 1998 व 2001 में तैनात रहे हैं। इसके साथ वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक भी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही पुलिस ने चंदन तस्कर वीरप्पन को मार गिराया था। वहीं, जम्मू-कश्मीर में सलाहकार के रूप में उन्होंने जेके पुलिस, सीमा सुरक्षा बल व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बेहतर समन्वय बनाकर देश के दुश्मनों पर सटीक प्रहार करने की रणनीति को कामयाब बनाया।

मौसम विशेष

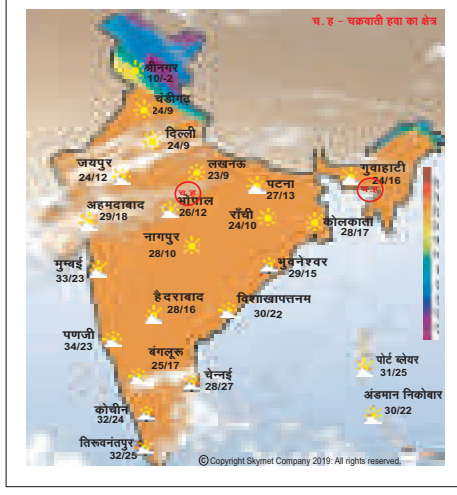

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में सुबह का मौसम काफी ठंडा रहेगा। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा छा सकता है। मैदानी इलाकों सहित पहाड़ी राज्यों का भी मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	35/22/व	अहमदाबाद	31/14/आंबा
कोलकाता	29/17/स्ना	बड़ौदा	32/15/स्ना
चेन्नई	29/22/व	नागपुर	29/10/व
हैदराबाद	29/18/स्ना	इन्दौर	28/14/आंबा
बंगलूरु	26/18/स्ना	रांची	26/15/व
त्रिवेन्द्रम	32/26/स्ना	पटना	27/16/आंबा
गुवाहाटी	22/16/स्ना	जमशेदपुर	27/17/आंबा
गंगटोक	06/-4/व	पुणे	30/20/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 7 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर की बमबारी

1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के नेवी बेस पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। इस हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इस हमले में 188 अमेरिकी लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे।

अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन डे मनाने की शुरुआत हुई

1994 में आज ही कंवेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के पचास वर्ष पूरे होने पर इस दिवस को मानने की शुरुआत हुई थी। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे मनाने की घोषणा की थी। इस कंवेंशन के तहत दुनिया भर में एयरस्पेस और हवाई सुरक्षा के नियम तय किए गए थे।

महान क्रांतिकारी बाघा यतींद्र को शत-शत प्रणाम

यतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 1879 में आज ही बंगाल में हुआ था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मार देने के कारण उन्हें बाघा यतींद्र के नाम से भी जाना जाता था। वह क्रांतिकारियों के प्रमुख संगठन 'युगांतर पार्टी' के मुख्य नेता थे। अंग्रेजों की बंग-भंग योजना का जमकर विरोध किया। आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने अपने चार साथियों के साथ मिलकर 26 अगस्त 1915 को कोलकाता रोड एंड कंपनी के बंदूक बिक्री केंद्र से पिस्टल लूट ली। 9 सितंबर, 1915 को अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में वह बुरी तरह घायल हो गए और 10 सितंबर को अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।

इधर-उधर की

रूस में ध्रुवीय भालुओं ने गांव पर किया कब्जा

मॉस्को, एजेंसी : रूस के एक गांव में इस समय ध्रुवीय भालुओं का आतंक फैला है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक में बड़े स्तर पर बर्फ पिघल रही है। ऐसे में अलग-अलग उम्र के शावकों के साथ करीब 56 ध्रुवीय भालू बर्फीले क्षेत्र से गांव में घुस आए हैं। इन भूखे शिकारी भालुओं की वजह से गांव के करीब 700 लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इसकी वजह से सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यह दूसरी बार है कि इस गांव के लोगों ने अपने दरवाजे पर ध्रुवीय भालुओं का सामना किया है। रूस के टेलीविजन चैनलों में फिलहाल इन भालुओं का आतंक चर्चा का मुद्दा बना है। हाल ही में सोशल मीडिया में कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुई हैं, जिनमें लोगों को इस खूंखार जानवर का सामना करते देखा गया। अधिकारियों ने 600 किलो वजनी और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकने वाले इन भालुओं से लोगों को बचने की सलाह दी है। रूस में इन्हें गोली मारना गैरकानूनी है।

भारतीय ने लंदन पुलिस के पुराने मुख्यालय को बनाया होटल

लंदन, प्रेट्र : भारतीय कारोबारी एमए यूसुफ अली के लुलु ग्रुप ने लंदन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के पुराने मुख्यालय को खरीद कर लक्जरी होटल में बदल दिया है। इसे ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल नाम दिया गया है। केरल में जन्मे यूसुफ के समूह ने मध्य लंदन में स्थित इस इमारत को 2015 में 1025 करोड़ रुपये में खरीदा था। बाद में इसे लक्जरी होटल में तब्दील करने के लिए 512 करोड़ रुपये और खर्च किए गए।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यूसुफ अली ने कहा, 'लंदन दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार है। ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल इस शहर के भव्य अतीत के साथ ही आधुनिक गौरव को भी दर्शाता है।' इस होटल का उद्घाटन इसी हफ्ते ब्रिटेन की डिजिटल, मीडिया, खेल व संस्कृति मंत्री निकी मोर्गन और भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम के हाथों होगा। यह होटल सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

भारतीय कारोबारी एमए यूसुफ अली (दाएं से तीसरे) ने लंदन में ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल का उद्घाटन किया। इस इमारत को उन्होंने 2015 में 1025 करोड़ रुपये में खरीदा था। प्रेट्र

15-16वीं सदी में स्कॉटलैंड के राजा का था आवास

15-16वीं सदी के दौरान स्कॉटलैंड के राजा, जब लंदन आते थे तो ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड इमारत में ही ठहरते थे। बाद में यह इमारत लंदन पुलिस का मुख्यालय बन गई थी। 2015 में इसे बेच दिया गया। लंदन पुलिस का मुख्यालय अब कर्टिस ग्रीन बिल्डिंग है।

एक रात के लिए चुकाने होंगे 40 हजार रुपये

इस इमारत में किसी समय लंदन पुलिस का मुख्यालय था। फाइल

सात मंजिला ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल में 152 कमरे और 15 सुइट के अलावा एक प्रेसिडेंशियल सुइट भी है। होटल में चार रेस्तरां भी बनाए गए हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय और ब्रिटिश व्यंजन परोसे जाएंगे। होटल के कमरों के किराये की शुरुआत 40 हजार रुपये से होगी।

तेजी से बढ़ रही है आर्कटिक में गर्मी

चिंताजनक ▶ बीते दस साल में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है इसका तापमान

धरती पर इतनी गर्मी बढ़ने में लगा एक सदी का समय

लॉस एंजिलिस : ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति आगाह करते हुए एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि पिछली एक सदी में पृथ्वी का कुल तापमान जितना बढ़ा, उतना ताप अकेले आर्कटिक में केवल एक दशक में ही बढ़ गया है। ध्रुवों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का आंकलन करने वाले इस अध्ययन में कहा गया है कि पिछले एक दशक में आर्कटिक का तापमान 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह आंकड़ा बीते 137 सालों में तापमान में हुई कुल वृद्धि के बराबर है।

जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित हुए इस अध्ययन में तापमान में वृद्धि का आर्कटिक और अंटार्कटिका के वन्य जीवन, टुंड्रा वनस्पति, मीथेन के रिसाव और बर्फ की चादरों पर पड़े प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (यूसी) डेविस के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान यह भी जांच की गई कि यदि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान दो डिग्री बढ़ता है तो इसका ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

यूसी डेविस में 'जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी' को पढ़ाने वाले और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक एरिक पोस्ट ने कहा, 'पिछले एक दशक में हुए कई बदलाव इतने नाटकीय हैं कि वे आपको आश्चर्यचकित करते हैं। साथ ही यह सोचने को मजबूर करते हैं कि गर्मी के कारण अगले दशक में पृथ्वी का स्वरूप कैसा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि हम पुराने चित्रों को देखकर यह कल्पना करते हैं कि आज भी आर्कटिक का स्वरूप वैसा ही है तो यह बस खुद को समझाने वाली बात है। इसका स्वरूप लगातार बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका परितंत्र भी काफी बदल गया है। यदि हम समय रहते इससे बचने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते तो यह निश्चित है कि आज से कुछ दशकों बाद आप अपने बच्चों से कहेंगे कि आर्कटिक का यह हिस्सा कभी बर्फ से ढका रहता था।

अमेरिकी शोधकर्ताओं का यह अध्ययन जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है। फाइल

उत्सर्जन में कटौती जरूरी

शोधकर्ताओं ने कहा, 'यदि हम 40 साल बाद भी तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना चाहते हैं कि हमारे नीति-नियंताओं को हर क्षेत्र में सामान्य दृष्टिकोण अपनाना होगा और उत्सर्जन में कटौती के लिए भी प्रयास करने होंगे।' पोस्ट ने कहा, 'यह बेहद चिंताजनक है कि जिस दर से आर्कटिक का तापमान बढ़ रहा है यदि इस गति पर काबू नहीं पाया गया तो अगले कुछ वर्षों में यहां का ताप दो डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है।'

सात डिग्री तक बढ़ेगा ताप

अध्ययन के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो इससे आर्कटिक के तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जबकि अंटार्कटिका के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसके भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए समय रहते कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

फिल्म रिव्यू

पति पत्नी और वो

प्रमुख कलाकार : कार्तिक आर्यन, भूमि पेडणेकर, अनन्या पांडेय, अपारशक्ति खुराना
निर्देशक : मुदस्सर अजीज
अवधि : 2 घंटे 8 मिनट

कॉमेडी के साथ रिश्तों में ईमानदारी

वर्ष 1978 में रिलीज हुई संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता अभिनीत क्लासिकल फिल्म 'पति पत्नी और वो' की रीमेक इसके निर्माता बीआर चोपड़ा के बेटे जूनो चोपड़ा ने बनाई है। कहानी को समसामयिक रूप देते हुए मूल कहानी की आत्मा को कायम रखा गया है।

कानपुर का इंजीनियरिंग टॉपर अभिनव त्यागी उर्फ चिंटू पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। सख्त अनुशासन में पला-बढ़ा चिंटू अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। उसका लंगोटिया यार फहीम अंसारी है। अभिनव अपने पिता की इच्छा पर भौतिक विज्ञान की शिक्षिका वेदिका त्रिपाठी के साथ विवाह के बंधन में बंध जाता है। दोनों शादीशुदा जिंदगी में खुश होते हैं। शादी के तीन साल बाद तपस्या सिंह यानी 'वो' की एंट्री होती है। दिल्ली की तपस्या कानपुर में व्यवसाय के लिए जमीन खरीदने आती है। उसके आते ही चिंटू की जिंदगी तपस्यामयी होती जाती है। तपस्या ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। चिंटू भारतीय परिधान पहनने वाली अपनी पत्नी से भी वेस्टर्न कपड़े पहनने को कहता है। आखिरकार एक दिन वेदिका को पता चल जाता है कि चिंटू की जिंदगी में कोई और है। पत्नी और प्रेमिका के चक्कर में अभिनव त्यागी को क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? इसे डायलॉग और पंचलाइन के साथ आगे बढ़ाया गया है।मुदस्सर अजीज ने फिल्म 'पति पत्नी और वो' का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं। इससे पहले वह 'हैप्पी भाग जाएगी' और उसकी सीक्वल का निर्देशन कर चुके हैं। इस बार उन्होंने हास्य के साथ संदेश भी रखा है। उन्होंने पति-पत्नी के रिश्ते के बीच 'वो' के आने की वजहों को भी खंगाला है। साथ ही हंसते-गुदगुदाते हुए रंगीनमिजाज पतियों को बेवफाई करने का सबक दिया है।

फिल्म में महिलाओं का सशक्त चित्रण है। पत्नी और प्रेमिका दोनों में किसी को भी अबला नहीं दिखाया गया है। फिल्म स्पष्ट संदेश देती है कि आधुनिक पत्नी पति की बेवफाई को खामोशी से सहन नहीं करने वाली है। वहीं पति को भी एहसास कराया गया है कि पत्नी से बेवफाई का क्या परिणाम हो सकता है। कहानी लखनऊ और कानपुर आती-जाती है। वहां की भाषा, रहन-सहन और पहनावे को कहानी में खूबसूरती से गूंथा गया है। 'मैं हूं ना' फिल्म के गाने तुम्हें जो मैंने देखा... का सटीक प्रयोग किया गया है।

कार्तिक आर्यन ने चिंटू त्यागी को बखूबी आत्मसात किया है। लहजा पकड़ने से लेकर चिंटू के मन में दबी इच्छाओं, उनकी पूर्ति को लेकर बोलने वाले झूठ तक उनकी परफॉर्मेंस में निरंतरता बनी रहती है। उनकी सिग्नेचर स्टाइल मोनोलॉग का प्रयोग निर्देशक ने यहां भी किया है। उसमें जीवन के कुछ कड़वे सच को बयां किया गया है। वहीं भूमि पेडणेकर लगातार अपनी परफॉर्मेंस से चकित कर रही हैं। छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखने वाली वेदिका की दबंगई, बेबाकी और उसके द्वंद्व को उन्होंने खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। उनका साड़ी पहनने का अंदाज ध्यान खींचता है। उन्होंने पारंपरिक तरीके से डाले जाने वाले पल्लू को दाएं की जगह बाएं डाला है। वहीं तपस्या की भूमिका में अनन्या पांडे चिंटू की तपस्या को भंग करने में कामयाब रही हैं। उनकी मासूमियत, स्टाइल और ताजगी स्क्रीन पर साफ झलकती है। अपारशक्ति खुराना अपनी परफॉर्मेंस से लुभाते हैं। उन्होंने फहीम की भूमिका को यादगार बनाया है। उन्हें दमदार डायलॉग का पूरा सहयोग मिला है। उनके स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कान स्वाभाविक रूप से आ जाती है। सहयोगी कलाकारों में नीरज सूद, केके रैना, राजेश शर्मा संक्षिप्त भूमिकाओं में अपना प्रभाव छोड़ते हैं।

क्लाइमेक्स को भांपना मुश्किल नहीं है, फिर भी कहानी से जुड़ाव बना रहता है। फिल्म का गीत-संगीत कहानी की लय के मुताबिक है। **स्मिता श्रीवास्तव**

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

डायबिटीज का जोखिम कम करेगी समय की पाबंदी

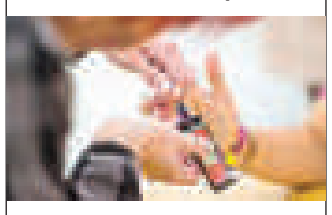

शोधकर्ताओं ने खानपान में समय की पाबंदी को लेकर किए अध्ययन में पाया है कि इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है, जिनके डायबिटीज से पीड़ित होने का सबसे ज्यादा खतरा है। अगर ऐसे लोग तीन माह तक रोजाना सिर्फ दस घंटे या इससे कम समय में अपना खानपान पूरा कर लेते हैं तो उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। सेल मेटाबोलिज्म जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, खाने में समय की पाबंदी से मेटाबोलिक सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की सेहत में सुधार पाया गया। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्राल स्तर जैसे कारकों के समूह का नाम मेटाबोलिक सिंड्रोम है। इस तरह के कारकों से हृदय रोग से लेकर स्ट्रोक और डायबिटीज तक का खतरा बढ़ जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता सचिन पांडा ने कहा, 'दस घंटे के दौरान खानपान निपटा लेने से बाकी 14 घंटे की अवधि में आपके शरीर को दुरुस्त होने का मौका मिल जाता है।' -आइएएनएस

25 की उम्र में कोलेस्ट्राल जांच दिलाएगी स्ट्रोक से निजात

एक अध्ययन का कहना है कि लोगों को 25 की उम्र से ही अपने कोलेस्ट्रोल स्तर की जांच करानी चाहिए। इसकी मदद से जीवन में आगे चलकर होने वाले हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। लैंसेट जर्नल में छपे अध्ययन के अनुसार, बचाव के लिए खानपान में बदलाव और उपचार के जरिये कोलेस्ट्राल को नियंत्रित करना बेहतर तरीका हो सकता है। कोलेस्ट्राल की एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन और विटामिन डी समेत कुछ दूसरे कंपाउंड को बनाने में जरूरत पड़ती है। हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल) कोलेस्ट्राल अच्छा होता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार है, जबकि लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एलडीएल) सेहत के लिए नुकसानदेह है। यह धमनियों को बाधित कर सकता है। -आइएएनएस

अमेरिका में मॉल के भीतर स्कीइंग की सेवा शुरू

अमेरिका के न्यू जर्सी में इन दिनों एक मॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ईस्ट रदरफोर्ड स्थित इस मॉल के भीतर ही एक दशक के लंबे इंतजार के बाद स्कीइंग सेवा शुरू की गई है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ओलंपिक डाउनहिल चैंपियन लिंडसे वॉन ने इसे तैयार करवाया है। मॉल के अधिकारियों के मुताबिक, उत्तरी अमेरिका में यह एकमात्र ऐसा प्लेग्राउंड है, जिसका प्लेटफॉर्म ताजी बर्फ से तैयार किया गया है। एपी

नेशनल क्रिसमस ट्री लाइटिंग सेरेमनी में पहुंचे ट्रंप दंपती

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास 'द एलिप्स' पार्क में 97वें वार्षिक नेशनल क्रिसमस ट्री लाइटिंग सेरेमनी में शिरकत की। इस मौके पर सफेद धारियां युक्त गहरे लाल रंग का कोट पहने मेलानिया ने बटन दबाकर क्रिसमस ट्री को रोशन किया। मेलानिया का कोट भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस 'द गैब्रिएला हर्स्ट कास्सैट' कोट की कीमत चार हजार डॉलर (दो लाख पचासी हजार एक सौ साठ रुपये) है। मोडाऑपरेंडी डॉट कॉम पर यह कोट 1960 डॉलर (करीब एक लाख चालीस हजार रुपये) में उपलब्ध है। रायटर

स्क्रीन शॉट

अब भी लोग मुझे नहीं पहचानते : सनी कौशल

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विक्की कौशल के छोटे भाई सनी कौशल अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 'गोल्ड' फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था और उनके पास फिल्मों की कमी भी नहीं है। आने वाले दिनों में एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे सनी कौशल तीन फिल्मों 'भांगड़ा पा ले', 'हुड़दंग' और 'शिद्दत' में नजर आएंगे। तीनों फिल्मों में वह सोलो हीरो के तौर

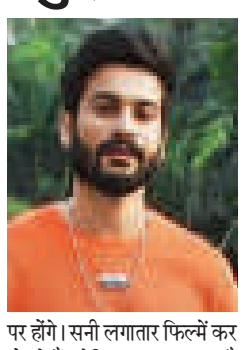

पर होंगे। सनी लगातार फिल्में कर तो रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि उन्हें अब तक वह कामयाबी नहीं मिली है, जिसकी वजह से लोग उन्हें देखते ही पहचान जाएं। सनी बताते हैं कि जब वह बीते दिनों में अपनी फिल्म 'हुड़दंग' की शूटिंग प्रयागराज में कर रहे थे, तब वे शहर के मिजाज को समझने के लिए अक्सर ही सड़क पर पैदल घूमने निकल जाया करते थे। कई बार दुकानों पर चाय पीने के लिए भी रुक जाया करते थे। सनी बताते हैं कि करीब दो महीने तक वहां शूटिंग करने के बाद एक चाय वाले चाचा उन्हें पहचानने लग गए थे। वह उनसे रोज हालचाल पूछते थे। वे रोज पूछते थे कि आज काम कैसा रहा और सनी उनसे कहते थे कि बहुत बढ़िया रहा। सनी कहते हैं, 'अब तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सड़क पर निकल जाऊं और लोग मुझे पहचान लें। 'गोल्ड' फिल्म करने के बाद भी लोग अब तक मुझे पहचानते नहीं हैं, क्योंकि उसमें मेरा लुक एकदम अलग था।' सनी बताते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि उन्हें जो थोड़ा-बहुत लोग पहचान रहे हैं, वे उन्हें फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि उनके वेब शो 'ऑफिशियल चुक्यागिरी' की वजह से पहचानते हैं। सनी बताते हैं कि उनकी यह वेब सीरीज अंदरूनी इलाकों तक पहुंची थी, जिसकी वजह से छोटे शहरों में लोग उन्हें पहचानते हैं।

जाह्नवी को पसंद हैं पुरुषों के परफ्यूम!

अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अक्सर पार्टियों में महिला और पुरुष दोनों के परफ्यूम लगाती हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषों के परफ्यूम अच्छे लगते हैं। जाह्नवी कहती हैं, 'मुझे पापा बोनी कपूर का परफ्यूम बहुत पसंद है। जब मैं बच्ची थी तो उनकी वार्डरोब खोलकर उनका परफ्यूम निकालकर लगाती थी। अभी भी रात की पार्टियों में जाना होता है तो मैं पुरुषों के परफ्यूम को महिलाओं के परफ्यूम के साथ मिक्स करके लगाती हूं।' जब जाह्नवी से प्यार को परिभाषित करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं प्यार को परिभाषित नहीं कर सकती हूं। मुझे लगता है कि प्यार ही एक ऐसी चीज है, जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह एक भावना है। यह हम सबसे बड़ी और सबसे ऊपर है। मैंने एक बार पढ़ा था कि आप जो भी करते हैं, वह प्यार पाने का एक तरीका होता है। मैं भी हमेशा ऐसा ही करती रहूंगी, जिससे मुझे लोगों का प्यार मिलता रहे।' वर्कफ्रंट की बात करें तो जाह्नवी के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें जोया अख्तर की 'घोस्ट स्टोरीज', शरन शर्मा की 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल', हार्दिक मेहता की 'रूही अफ्जा' और कोलिन डी की 'दोस्ताना 2' शामिल हैं।

...जब कपिल देव को मासूम और क्यूट लगे रणवीर सिंह

सोशल मीडिया पर सितारों की तस्वीरों पर अक्सर सितारे ही प्रतिक्रिया देते हैं, मगर जब रणवीर सिंह ने अपनी किशोरावस्था की तस्वीर शेयर की, तब प्रतिक्रिया आई पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की। उनकी प्रतिक्रिया आना लाजमी भी था, क्योंकि रणवीर कबीर खान की फिल्म '83 में कपिल देव की ही भूमिका निभा रहे हैं। रणवीर ने अपनी पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, 'फ्लैशबैक फ्राइडे'। इस पर कपिल देव ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'मासूम और बहुत क्यूट'। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने अर्जुन कपूर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है। रणवीर और अर्जुन अच्छे दोस्त हैं। तस्वीर में रणवीर ने अर्जुन को जिगरी यार की तरह पकड़ रखा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, 'बाजीराव और सदाशिव राव। आगे बढ़ो और जीतो। बाबा पावर।' रणवीर सिंह की आगामी फिल्में '83 और 'जयेशभाई जोरदार' होंगी। जबकि अर्जुन कपूर की 'पानीपत' इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है।

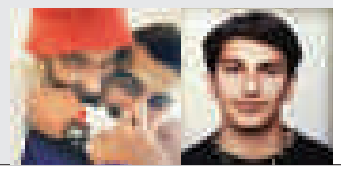

पहली बार आएगा विशुद्ध देसी डांस रियलिटी शो...

टेलीविजन पर इन दिनों अलग-अलग चैनलों पर रियलिटी शोज चल रहे हैं। उनमें कई विदेशी शोज का हिंदी संस्करण हैं। 'बिग बॉस', 'मास्टरशेफ इंडिया', 'इंडियन आइडल', 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे कई शोज विदेशी टीवी शोज से प्रेरित हैं। ऐसे में नए कॉन्सेप्ट के साथ देसी रियलिटी डांस शो शुरू होने जा रहा है, जो किसी भी विदेशी शो की कॉपी नहीं है। सोनी टीवी का नया शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' विशुद्ध देसी शो होगा। इस शो की खासियत यह है कि शो में 12 डांस गुरु होंगे, जो प्रतियोगियों को डांस सिखाएंगे। इस शो को मलाइका अरोड़ा, गीता कपूर और टेरेंस लुइस जज करेंगे। तीनों पहली बार एकसाथ जज पैनल में एकसाथ नजर आएंगे। शो से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस तरह का डांस रियलिटी शो अब तक टीवी पर नहीं देखा गया होगा। जनवरी से शो के लिए अलग-अलग शहरों में ऑडिशन की प्रक्रिया आरंभ होगी।

अध्ययन

बच्चों को फूड एलर्जी से बचा सकती है मूंगफली

किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा- शिशुओं को शुरुआती महीनों में अंडा-मूंगफली खिलाने से हो सकता है लाभ

लंदन, आइएएनएस : भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें पोषण तो मिलता ही है। साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। लेकिन कभी-कभी देखा जाता है कि किसी भोजन के कारण शरीर में तमाम तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। सामान्यतः इसे ही फूड एलर्जी कहा जाता है। कई बार किसी खाद्य पदार्थ को पंसद न करना भी फूड एलर्जी का कारण बनता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए शोधकर्ताओं ने अध्ययन में एक नया सुझाव दिया है। उनका कहना है कि यदि बच्चे को शुरुआती महीनों में ही मूंगफली और अंडे का सेवन कराया जाए तो बाद के वर्षों में होने वाली फूड एलर्जी की समस्या से बहुत हद तक बचा जा सकता है।

हालांकि, ब्रिटेन के वर्तमान स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुसार, शिशुओं को छह महीने तक स्तनपान कराने के अलावा कुछ भी नहीं खिलाया जाना चाहिए। उसके बाद ही शिशुओं को खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं। एलर्जी एंड क्लीनिक इन्यूनोलॉजी नामक जर्नल में बताया गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे एलर्जी हो सकती है, यदि शुरुआती महीनों में ही शिशुओं को उनका सेवन कराया जाए तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि भविष्य में वे फूड एलर्जी का शिकार नहीं होंगे। शोधकर्ताओं शिशुओं को मूंगफली और अंडे खिलाकर यह दावा किया है। बता दें कि इन दोनों खाद्यों से भी एलर्जी की संभावना रहती है।

किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर और इस अध्ययन के शोधकर्ता गीडन लैक ने कहा, 'शोध परिणामों के उम्मीद के मुताबिक हैं और यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिशुओं के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देशों को नए सिरे से तय करने की सिफारिश करता है।' उन्होंने कहा एलर्जी की संभावना वाले खाद्य पदार्थों को इन सिफारिशों का हिस्सा बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुबूत भी हैं। हालांकि, यदि दिशानिर्देशों में बदलाव लाना हो तो हमें लोगों के समर्थन की भी जरूरत होगी।

यह अध्ययन एलर्जी एंड क्लीनिक इन्यूनोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

ऐसे किया अध्ययन

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंग्लैंड और वेल्स के तीन माह के 1300 शिशुओं को शामिल कर उन्हें दो समूहों में बांटा। एक समूह के शिशुओं को स्तनपान के साथ-साथ मूंगफली और अंडा खिलाने को दिया गया, जबकि दूसरे समूह के बच्चों को अगले छह माह तक केवल स्तनपान कराया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जिस समूह के बच्चों ने केवल स्तनपान किया था, उनमें 34.2 फीसद फूड एलर्जी का शिकार थे। वहीं दूसरी ओर जिस समूह के बच्चों ने स्तनपान के सा-साथ मूंगफली और अंडे का सेवन किया था उनमें 19.2 फीसद बच्चे फूड एलर्जी से ग्रस्त थे।